सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
निष्पादन लेखापरीक्षा
2013 की सं. 16

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		*iii*
कार्यकारी सारांश		*v*
अध्याय 1	**भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य-पद्धति** (विदेश मंत्रालय)	1
अध्याय 2	**इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-पद्धति** (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	53
अध्याय 3	**बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-पद्धति** (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	81

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संविधान की धारा 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नलिखित शीर्षकों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं:

1.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य-पद्धति	विदेश मंत्रालय
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-पद्धति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
3.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-पद्धति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि हेतु उपरोक्त इकाइयों के अभिलेखों के परिणाम शामिल है।

कार्यकारी सारांश

विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य-पद्धति

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना भारत एवं अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों तथा पारस्परिक समझ को बनाने, पुनर्जीवित करने एवं सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गयी थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य सभा, शासी निकाय तथा वित्त समिति सहित परिषद के प्राधिकारियों, ने नीति एवं कार्यक्रम बनाये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये प्राधिकारी निर्धारित अंतराल पर नहीं मिले थे, और ना ही उनके द्वारा कोई वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी थी।

परिषद, भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना का पर्याप्त रूप से प्रचार करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम के अंतर्गत स्लॉटों का कम उपयोग एवं देशों का विषम प्रतिनिधित्व हुआ था। परिषद ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 25 *प्रतिशत* स्लॉट उन देशों को आवंटित किये जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हेतु वैध समझौता नहीं था।

परिषद द्वारा विदेश मंत्रालय की अपेक्षित स्वीकृति के बगैर तीन भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले गए एवं प्रचालित किए जा रहे थे। परिषद वित्त मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति लिए बगैर विभिन्न देशों में निदेशक, भा.सां.सं.प. के पद बनाये हुए था। परिषद ने निदेशक, भा.सां.सं.प. के पद पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं बनाये थे। परिणामस्वरूप, ये पद परिषद द्वारा मनमाने ढंग से भरे जा रहे थे। परिषद द्वारा अपनायी गयी प्रापण प्रक्रिया में बड़ी खामियां थीं। परिषद ने सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का पालन किए बगैर निजी संस्थाओं से सेवाओं के प्रापण पर काफी व्यय किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति

इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसे सितम्बर 1887 में स्थापित किया गया था। इसे एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया एवं जुलाई 2005 में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-2012 की आच्छादित अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में इनकी कार्य पद्धति में कई महत्वपूर्ण कमियां थी। विश्वविद्यालय अपने स्रोतों को दक्षतापूर्वक तरीके से उपयोग नहीं कर सका क्योंकि यहाँ शिक्षा स्टाफ की बहुत कमी थी तथा शिक्षक-छात्र का अनुपात भी निर्धारित मानदंडों से बहुत अधिक था। अध्यादेश के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा वांछित 15 केन्द्रों की अपेक्षा मात्र सात अन्तः अनुशासनात्मक केन्द्र खोले गए थे।

अनुसंधान परियोजनाओं पर निधियों के उपयोग में बहुत कमी थीं। विश्वविद्यालय विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त निधियों का केवल 33 *प्रतिशत* ही उपयोग कर पाया था। छात्रावास आवंटन में कमियां थीं, क्योंकि छात्रावास में अप्राधिकृत अतिक्रमण के साथ प्रतीक्षा सूची भी थी। विश्वविद्यालय में निधीयन प्रबंधन निम्न स्तर का था। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय की अनुप्रयुक्त धनराशि वर्ष 2006-07 में ₹64.80 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹97.15 करोड़ हो गयी। मा.सं.वि.मं. के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों के सां.भ.नि. पर ब्याज के भुगतान हेतु अनुरक्षण अनुदान का विपथन किया।

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का संचालन

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट/पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के अधीन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से पुनः नामित किया गया और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित (जनवरी 1996) किया गया।

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक अध्यादेश, 2004 के द्वारा प्रावधानित विभिन्न विद्यालयों एवं विभागों को खोलने के संबंध में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। विश्वविद्यालय अवसरंचना, शैक्षणिक स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, क्रीड़ा परिसर, स्वास्थ्य केन्द्र की कमी के साथ कार्य कर रहा था। विश्वविद्यालय द्वारा निधियों का उपयोग निम्न स्तर का था। परिणामस्वरूप, 2006-07 के दौरान ₹2.56 करोड़ की अव्ययित धन राशि बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹54.30 करोड़ तक पहुँच गयी थी।

विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्य-पद्धति

अध्याय I : विदेश मंत्रालय

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य बिन्दु:

- परिषद ने सामान्य सभा (सा.स.) एवं शासी निकाय (शा.नि.) की निर्धारित संख्या में बैठकें नहीं की थी। वर्ष **2007-08** से **2009-10** हेतु अपना बजट वित्त समिति, शासी निकाय, एवं सामान्य सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया था। इससे इन निकायों की भूमिका कमजोर हुई।

(पैराग्राफ 1.2.1.1, 1.2.1.2 एवं 1.2.1.3)

- परिषद ने वर्ष **2006-07** से लेकर **2011-12** तक वार्षिक कार्रवाई योजना तैयार नहीं की थी। यह चूक अपने संविधान एवं शा.नि. के विशिष्ट दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी।

(पैराग्राफ 1.2.1.4)

- अपने कार्यक्रमों की प्रभाविकता के आकलन हेतु तंत्र को स्थापित करने संबंधी शा.नि. तथा वित्त समिति के निर्देशों का अनुपालन करने में परिषद विफल रहा।

(पैराग्राफ 1.2.1.5)

- परिषद ने अपनी छात्रवृत्ति योजना में से एक को पर्याप्त प्रचार नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप स्लॉट का कम उपयोग तथा विषम प्रतिनिधित्व हुआ।

(पैराग्राफ 1. 2.2.1)

- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद ने **25** *प्रतिशत* स्लॉट उन देशों को आवंटित किए जिनके साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों/शिक्षा विनिमय कार्यक्रम हेतु वैध समझौता नहीं था।

(पैराग्राफ 1.2.2.2)

- विदेश में **14** भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (भा.सां.के.) खोलने हेतु अनुमोदन के विपरीत, परिषद ने **17** भा.सां.के. की शुरूआत की थी। इसके अलावा, परिषद अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही आठ अतिरिक्त भा.सां.के. को खोलने की प्रक्रिया में भी था।

(पैराग्राफ 1.2.3.3)

- वित्त मंत्रालय द्वारा पदों की मंजूरी बिना ही, परिषद विदेश में अपने भा.सां.के. हेतु निदेशकों के पद परिचालित कर रहा था।

(पैराग्राफ 1.2.4.2.क)

- परिषद ने भा.सां.के. में बाहरी व्यक्तियों के रूप में नियुक्त निदेशकों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान एवं नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश/मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(पैराग्राफ 1.2.4.2.ख)

- परिषद ने विदेश में की जाने वाली प्रदर्शनियों हेतु कलाकारों के प्रायोजन तथा चयन हेतु मानदंडों या नियम, विनियमों को तैयार नहीं किया था।

(पैराग्राफ 1. 2.5)

- 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹8.15 करोड़ का व्यय करते हुए 70 देशों में भेजे गए 34 प्रत्यायोजन, सक्षम प्राधिकारी अर्थात भा.सां.सं.प. अध्यक्ष के अनुमोदन की अनुपस्थिति में अप्राधिकृत थे।

(पैराग्राफ 1.2.6.1)

- परिषद में बिलों के भुगतान हेतु बिलों के प्रसंस्करण और प्रापण प्रक्रिया में बड़ी कमियाँ थी।

(पैराग्राफ 1.2.6.2)

अनुशंसाएं

- सांविधिक प्राधिकारियों की बैठकें निर्धारित अवधि के अनुसार होनी चाहिए।
- परिषद को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाओं के अनुमोदन तथा अपनाने हेतु सांविधिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। वार्षिक कार्रवाई योजना, शा.नि. द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए।
- परिषद को अपने कार्यक्रमों की प्रभाविकता के आकलन हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार करना चाहिए।
- भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना को भारतीय मिशन के साथ संवर्धित संचार के माध्यम से अधिक प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।
- स्लॉटों की उपयोगिता का अधिक विस्तृत आधार होना चाहिए।
- अभ्यर्थियों के चयन हेतु मानदण्ड की अतिसावधानी से अनुपालना की जानी चाहिए।
- परिषद योजना के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सा.वि.का./शि.वि.का. के अंतर्गत स्लाटों के कम उपयोग के मामले मिशनों/पोस्ट के साथ उठाए।
- परिषद यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्तियां उन देशों के छात्रों को प्रदान की गई हैं जिनके साथ करार विद्यमान है।
- बजट को वास्तविकता के आधार पर ही तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु वास्तविक व्यय को समय-समय पर मॉनीटर किया जाना चाहिए।
- भा.सां.के. को उनके प्रभावी कार्यकरण हेतु बजट आवंटन एवं प्रेषण की सूचना समय पर देना आवश्यक है।
- भा.सां.सं.प. को नए भा.सां.के. खोलने से पूर्व विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए।
- भा.सां.के. में निदेशक के पद के सृजन हेतु परिषद को वित्त मंत्रालय से संस्वीकृति लेनी चाहिए।
- परिषद को भा.सां.के. के निदेशकों के नियम एवं शर्तें तथा नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए और चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए।
- परिषद को मौजूदा काम के बोझ को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात मानव संसाधनों से, संख्या तथा पदनाम दोनों रूप में समीक्षा करनी चाहिए।
- परिषद को अंर्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों हेतु कलाकारों के चयन तथा उसी उद्देश्य के वित्तीय समर्थन हेतु उपयुक्त मानदंड निर्धारित करने चाहिए।
- सांस्कृतिक प्रत्यायोजनों को अनुमोदन देने हेतु वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन में परिभाषित सीमाओं का अनुसरण परिषद को करना चाहिए।
- हवाई यात्रा के संबंध में परिषद को भारतीय सरकार के निर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।

1.1 प्रस्तावना


भा.सां.सं.प., आजाद भवन, नई दिल्ली

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (परिषद) की स्थापना 1950 में भारत तथा अन्य देशों के बीच आपसी समझ और सांस्कृतिक रिश्तों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। परिषद, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। परिषद के उद्देश्य अपने संविधान में निहित उद्देश्यों के अनुसार हैं:

- भारत के विदेशी सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीति एवं कार्यक्रमों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन में भाग लेना;
- भारत तथा अन्य देशों के बीच आपसी समझ तथा सांस्कृतिक रिश्तों को प्रोत्साहन देना तथा सुदृढ़ करना;
- अन्य देशों तथा लोगों के साथ सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन देना;
- संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ रिश्तों को स्थापित एवं विकसित करना; तथा
- इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता के अनुसार अन्य कदम उठाया जाना।

1.1.1 संगठनात्मक स्थापना

परिषद, विदेश मंत्रालय (वि.मं.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चयन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें तीन उपाध्यक्ष हैं, जिनमें से दो को परिषद की सामान्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही निर्वाचित किया जाता है। भारत सरकार के विदेश सचिव पदेन तृतीय उपाध्यक्ष होते हैं।

सामान्य सभा (सा.स.), शासी निकाय (शा.नि.) एवं वित्त समिति, परिषद के तीन महत्वपूर्ण प्राधिकारी हैं।

महानिदेशक, परिषद के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं तथा उनकी सहायता दो उपमहानिदेशकों द्वारा की जाती है जिन्हें विशिष्ट क्षेत्रों/गतिविधियों से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। महानिदेशक एवं दो उपमहानिदेशकों को विदेश मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। अपने संविधान के अनुसार, वि.मं. का वित्तीय सलाहकार, परिषद का भी वित्तीय सलाहकार होता है।

परिषद के 20 क्षेत्रीय कार्यालय भारत में तथा 37 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (भा.सां.के.) विदेश में हैं (31 मार्च 2012)।

1.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा के कार्य, शक्तियां एवं शर्तें) अधिनियम, 1971 - धारा 20 (1) के अंतर्गत परिषद की लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

1.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई थी कि:

- परिषद ने अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त कार्यक्रम सूत्रबद्ध किए हैं;
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा था;
- वित्तीय प्रबंधन, संसाधनों का आर्थिक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है;
- भर्ती, पदोन्नति एवं तैनाती समेत श्रमशक्ति प्रबंधन नियमों के अनुसार एवं पारदर्शी थे;
- कलाकारों एवं सलाहकारों का चयन, नियमों के अनुसार एवं पारदर्शी था, तथा
- परिषद के भीतर आंतरिक नियंत्रण एवं मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण पर्याप्त था।

1.1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि को आवृत्त किया था सिवाय, विदेश में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों (भा.सां.के.) के, जिनके लिए अवधि 2008-09 से 2011-12 थी। विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 37 भा.सां.के. में से 12 तथा 20 क्षेत्रीय कार्यालयों में से तीन चयनित किए गए थे। परिषद के निष्पादन का मूल्यांकन

समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली तथा दिशानिर्देशों के अलावा पैरामीटरों, संस्थापन प्रलेख (सं.प्र.) एवं मानदंड/नीतियों के प्रति किया गया था।

1.1.5 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

परिषद की निष्पादन लेखापरीक्षा 27 जून 2011 से शुरू हुई थी। अगस्त 2011 में महानिदेशक के साथ प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। परिषद एवं मंत्रालय को लेखापरीक्षा निष्कर्ष 30 मई 2012 को जारी कर दिए गए थे। महानिदेशक, भा.सा.सं.प. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा हेतु निकास सम्मेलन का आयोजन 3 जुलाई 2012 को किया गया था। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दिए गए परिषद के उत्तर (28 सितम्बर 2012) को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। वि.मं. से उत्तर अभी प्रतिक्षित है (जून 2013)।

1.1.6 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, परिषद एवं उसके अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता को अभिस्वीकृत किया जाता है।

1.1.7 परिषद द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां

2006-07 से 2011-12 के दौरान परिषद द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियां, गतिविधियों की संख्या के अनुसार **तालिका-1** में दी गई है।

तालिका-1: परिषद द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां

(गतिविधियों की संख्या)

क्र. सं.	गतिविधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	विदेश में की गई प्रदर्शनियां (संयोजित/समर्थित)	5	16	22	20	44	42
2.	भारत में प्रदर्शनियां (संयोजित/समर्थित)	5	14	19	07	49	51
3.	सम्मेलन एवं सेमीनार (भारत तथा विदेश में सहायता प्रदान की गई)	23	24	25	27	36	12
4.	विदेश में भारतीय पढ़ाई की कुर्सियों का अनुरक्षण	21	29	32	43	75	91
5.	आनेवाला सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	34	33	52	39	42	44

क्र. सं.	गतिविधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
6.	जानेवाला सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल	78	63	93	101	124	148
7.	आने वाले आगंतुक	30	20	19	19	19	11
8.	जाने वाले आगंतुक	64	76	85	54	72	35
9.	विदेश में प्रतिमाओं/मूर्तियों की कमीशनिंग	9	9	01	13	03	15
10.	विदेशी विद्यार्थियों को दिलाई गई छात्रवृत्ति	1100	1205	1238	1517	1483	1530

इस प्रकार, परिषद अपनी अधिकतर गतिविधियों को विस्तृत कर रही है।

1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.2.1 परिषद के प्राधिकारी

1.2.1.1 सामान्य सभा

परिषद के संविधान[1] के अंतर्गत, सामान्य सभा (सा.स.) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को ध्यान में रखते हुए, परिषद के कार्यक्रमों पर विचार करने एवं तैयार करने, विदेशी सांस्कृतिक संबंधों पर भारत सरकार को सलाह देने, शा.नि. द्वारा अनुमोदित परिषद के वार्षिक बजट को अपनाने, शा.नि. द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार करने एवं अनुमोदित करने, के संबंध में निर्देश देने तथा परिषद के लेखाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदन को अपनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, संविधान[2] यह बताता है कि सा.स. वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य मिले।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2008-09 के दौरान सा.स. की कोई भी बैठक नहीं हुई थी। सा.स. को वर्ष 2007-08 से 2009-10 का बजट, वर्ष 2008-09 के वार्षिक लेखा एवं वर्ष 2006-07 से 2008-09 के वार्षिक प्रतिवेदन, अपनाने हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सा.स. एवं शा.नि. के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु वर्ष 2006-07 से लेकर 2011-12 तक के दौरान परिषद ने कार्रवाई की वार्षिक योजना तैयार नहीं की थी। इन महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू न किए जाने से यह तथ्य निकलता है कि सा.स. की भूमिका को कम आंका गया था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से यह प्रस्ताव/मद, सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके तथा जैसा कि

[1]धारा 5
[2]धारा 6, 8(V)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, सामान्य सभा के संचालन एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का ध्यान रखा जाएगा।

1.2.1.2 शासी निकाय

संविधान[3] के अंतर्गत, शासी निकाय (शा.नि.) के परिषद के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करने, सा.स. के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु विशिष्ट परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने, परिषद के वार्षिक बजट का अनुमोदन करने एवं सां.स. द्वारा अपनाए जाने हेतु परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखाओं के अनुमोदन का कार्य सौंपा गया था। इन गतिविधियों के निष्पादन हेतु, शा.नि. को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान अपेक्षित 12 बैठकों की आवश्यकता के विपरीत आठ बैठकें हुई थी। परिषद ने 2007-08 से लेकर 2009-10 हेतु बजट पर तथा 2006-07 से 2008-09 हेतु वार्षिक प्रतिवेदनों पर शा.नि. से अनुमोदन नहीं लिया था। यह न केवल उनके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था अपितु परिषद के मामले में मॉनीटरिंग एवं नियमन की कमी भी दर्शाता था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि शा.नि. की बैठक कुछ वर्षों को छोड़कर जिनमें यह वर्ष में एक बार हुई थी, संविधान के हिसाब से हुई थी तथा शा.नि. के समक्ष बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में चूक, संविधान का उल्लंघन नहीं करती। परिषद ने संवैधानिक प्रावधानों को अक्षरशः कार्यान्वित करने के अपने प्रयासों को दोहराया है। तथ्य यही रहता है कि अपने संविधान द्वारा आदृष्ट किए जाने पर भी शा.नि. के समक्ष न तो वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट प्रस्तुत किए गए थे और न ही बैठक की गई थी।

1.2.1.3 वित्त समिति

संविधान के अंतर्गत[4] वित्त समिति का कार्य परिषद के बजट अनुमानों पर विचार करना एवं उस पर शा.नि. के समक्ष अनुशंसाए करना, परिषद के प्रशासन एवं कार्यक्रमों जिन्हें कि समय-समय पर अध्यक्ष या शा.नि. या सा.स. द्वारा निर्दिष्ट किया जाता था, से संबंधित मामलों पर विचार करना एवं संस्तुति करनाथा।

---

[3]धारा 8

[4]परिषद के संविधान की धारा 11

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि परिषद ने वित्त समिति से वर्ष 2007-08 से 2010-11 हेतु बजट के लिए अनुमोदन नहीं मांगा था।

परिषद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (फरवरी और सितम्बर 2012)।

1.2.1.4 कार्रवाई योजना

संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति संसाधनों के उपयोग हेतु नियोजन आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत[5], शा.नि. के समक्ष बजट अनुमानों एवं गतिविधियों के कार्यक्रम का नियमन एवं प्रस्तुतीकरण वित्तीय सलाहकार एवं वित्त समिति के साथ परामर्श कर महानिदेशक द्वारा किया जाता है। परिषद 2005-06 तक शा.नि. के समक्ष बजट के साथ-साथ वार्षिक कार्रवाई योजना को प्रस्तुत कर रहा था। शा.नि. ने 2005-06 की वार्षिक कार्रवाई योजना अनुमोदित करते हुए, निर्देश दिया (नवम्बर 2005) कि अपने अनुमोदन हेतु कार्रवाई योजना को अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद ने 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि हेतु वार्षिक कार्रवाई योजना हेतु दस्तावेज तैयार नहीं किए थे। इस प्रकार, परिषद का यह कार्य अपने संविधान एवं शा.नि. के विशिष्ट दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि भविष्य में कार्रवाई योजना को अलग से तैयार एवं अनुमोदित किया जाएगा।

उपरोक्त विश्लेषण (1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 एवं 1.2.1.4) दर्शाता है कि सा.स, शा.नि. एवं वित्त समिति के बजट, वार्षिक लेखाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों तथा वार्षिक कार्रवाई योजना के अधिदिष्ट कार्य प्रभावी रूप से नहीं किए जा रहे थे, जिसके कारण इन निकायों की भूमिका को कम आंका गया था।

1.2.1.5 कार्यक्रमों की प्रभावशीलता

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति परिषद द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से होती है। कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु, वित्त समिति ने निर्णय लिया (फरवरी 2005) कि दिए गए प्रपत्र में दर्शकों से टिप्पणियां लिए जाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्थल पर नोटिस लगा दिया जाए। इसके अतिरिक्त, मिशन तथा भा.सां.के. को बाहर जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संबध में प्राप्त प्रतिपुष्टि को समाविष्ट एवं आकलन करने के पश्चात

---

[5]परिषद के संविधान की धारा 15 (iii) (ग)

भा.सां.सं.प. (मुख्यालय) से साभार करने की सलाह दी गई। शा.नि. ने यह इच्छा भी जाहिर की (मार्च 2005) कि मिलाई गई प्रतिपुष्टि के बारे में उसे भी सूचित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिपूर्ति को न तो संकलित किया गया था और न ही शा.नि. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

परिषद ने बताया (दिसम्बर 2011) कि वेबसाडट/मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त जनता की टिप्पणियां एवं आलोचकों की टिप्पणियां/रिपोर्टें उनके कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की सूचक है। इसने आगे बताया (सितम्बर 2012) कि वर्तमान तंत्रों को अधिक सुदृढ़ करने के लिए सदन समिति का गठन किया जा रहा है।

परिषद के उत्तर को वित्त समिति एवं शा.नि. के विशिष्ट दिशानिर्देशों के प्रकाश में देखा जा सकता है और तथ्य यह भी है कि कार्यक्रमों के बारे में जनता/मीडिया रिपोर्टों की टिप्पणियों से संबंधित कोई भी सूचना लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।

1.2.1.6 अन्य सांस्कृतिक संगठनो के साथ तालमेल

परिषद का एक उद्देश्य संस्कृति के क्षेत्र में देशी एवं विदेशी संगठनों के साथ संबंधों को स्थापित एवं विकसित करना है। सा.स. एवं शा.नि. ने विभिन्न बैठकों[6] में परिषद, संस्कृति विभाग के आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों (आं.सां.के.) एवं राज्य अकादमी विभाग (रा.अ.) की गतिविधियों में तालमेल करने की आवश्यकता को नोट किया था। शा.नि. ने निर्णय लिया (मार्च 2004) कि आ.सां.के., रा.अ. एवं परिषद के निदेशकों की वार्षिक बैठकें सहयोगात्मक कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 27-29 जनवरी के दौरान होनी चाहिए। भा.सां.सं.प., अध्यक्ष ने सुझाव दिया (सा.स. बैठक-सितम्बर 2009) कि उसी उद्देश्य के लिए भा.सां.सं.प., संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा साहित्य अकादमी में एक बुद्धिशीलता सत्र होना चाहिए। शा.नि. बैठक में (सितम्बर 2009)विदेश सचिव ने भी सुझाव दिया कि पर्यटन मंत्रालय एवं लोक राजनय प्रभाग के मध्य समन्वय के साथ, सांस्कृतिक संवर्धन हेतु समेकित दृष्टिकोण होना चाहिए। इस प्रकार, विभिन्न प्राधिकारियों ने संस्कृति के क्षेत्र में समान संगठनों के बीच समन्वय एवं तालमेल की आवश्यकता व्यक्त की है।

---

[6]21 जनवरी 2004 एवं 10 मार्च 2004 दिनांक की शा.नि. बैठकें, दिनांक 27 सितम्बर 2006 की सा.स. बैठक।

तथापि, परिषद के अभिलेखों में विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय या तालमेल के प्रयास को दर्शाते हुए कोई दस्तावेज नहीं थे।

परिषद ने बताया (दिसम्बर 2011) कि भा.सां.सं.प. के शा.नि. के अधिकतर सदस्य साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी जैसे समान संगठनों के सदस्य थे तथा इन संगठनों के सदस्यों में आपस में प्रतिपुष्टि प्रदान कर दी जाती थी।इसके अतिरिक्त, परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि किसी भी निर्णय एवं शुरू की गई या नियोजित गतिविधि के बारे में सदस्यों को सूचित कर दिया जाता था, एवं भा.सां.सं.प. के वैधानिक निकायों से अनुमोदन लिया जाता था।

कथित तंत्र प्रभावकारी नहीं पाया गया था क्योंकि सा.स. के साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी के प्रतिनिधियों द्वारा बहुत कम बैठकों में भाग लिया गया था। परिषद की सा.स./शा.नि. के भारत में समान प्रकार के निकायों के बीच तालमेल को सुधारने हेतु दिए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं किया गया था।

अनुशंसाएं

- ❖ *वैधानिक प्राधिकारियों की बैठकें निर्धारित अवधि के अनुसार होनी चाहिए।*
- ❖ *परिषद को वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष अपनाने एवं अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखाओं का प्रस्तुतीकरण होना सुनिश्चित करना चाहिए। शा.नि. द्वारा वार्षिक कार्रवाई योजना को अनुमोदित करना आवश्यक है।*
- ❖ *परिषद को अपने कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त क्रियाविधि निर्मित करनी चाहिए।*

1.2.2 छात्रवृत्ति योजनाएं



भारत में परिषद पूर्वस्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने हेतु विदेशी छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रबंध करती है। छात्रवृत्तियां भारतीय नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला सीखने हेतु भी

प्रदान की जाती हैं। परिषद की स्वयं की 11[7] छात्रवृत्ति योजनाएं हैं इसके अतिरिक्त यह भारत के मंत्रालय/विभागों की ओर से 10[8] छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करती है।

चूंकि ये योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए हैं इसलिए इन्हें विदेश में भारतीय मिशनों के समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जाता है। परिषद भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में चयनित छात्रों के नामांकन का प्रबंध करती है। छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भुगतान के लिए तीन घटक हैं (क) शैक्षणिक संस्थान द्वारा लिए जाने वाला शिक्षा शुल्क (ख) निर्वाह भत्ता तथा (ग) निर्धारित आकस्मिक भत्ता।

2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान, परिषद ने उपलब्ध 12604 में से 8073 छात्रवृत्ति स्लॉटों का उपयोग किया, जैसा कि **तालिका-2** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2: छात्रवृत्ति स्लाटों के उपयोग की वर्ष-वार स्थिति

अवधि	छात्रवृत्ति की संख्या			
	स्वयं की छात्रवृत्ति		अभिकरण कार्य	
	उपलब्ध स्लॉट	उपयोग किए गए स्लॉट	उपलब्ध स्लॉट	उपयोग किए गए स्लॉट
2006-07	1150	596	654	504
2007-08	1218	625	660	580
2008-09	1234	685	606	553
2009-10	1212	689	1105	828
2010-11	1178	677	1172	806
2011-12	1223	667	1192	863
योग	**7215**	**3939**	**5389**	**4134**

तीन छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात्, अफगान नागरिकों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना, भा.सां.स.प. छात्रवृत्ति योजना तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जांच की गई थी। जांच के परिणामों ने प्रकट किया कि यद्यपि अफगान नागरिकों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक था फिर भी अन्य दो योजनाओं के कार्यान्वयन में कुछ कमियां थीं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

---

[7] सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना, बंग्लादेश छात्रवृत्ति योजना, श्रीलंका छात्रवृत्ति योजना, मोरिशियस छात्रवृत्ति योजना, मोरिशियस नागरिक हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना, भा.सा.स.प. छात्रवृत्ति योजना, सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम, राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति योजना, अफ्रीका दिवस, दादू नायकर

[8]मालद्वीप को सहायता, सार्क अध्यक्ष/शिक्षावृत्ति योजना, बीम्सटेक देशों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना, वि.मं. एवं आयुष विभाग की ओर से बीम्सटेक सदस्य देशों तथा गैर -बीम्सैटक देशों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना, मीकोंग गंगा सहकारिता छात्रवृत्ति योजना, प्रशान्त द्वीप देशों हेतु छात्रवृत्ति, आई.यो.आर-ए.आर.सी. छात्रवृत्ति योजना, अफ्रीका छात्रवृत्ति योजना, रजत जंयती, अफगानिस्तान छात्रवृत्ति योजना

1.2.2.1 भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना

इस योजना में छात्रवृत्ति किसी भी विदेशी छात्र को प्रदान की जाती है जो भारतीय कला, संस्कृति तथा संगीत सीखने का इच्छुक है। भारतीय मिशनों द्वारा प्रेषित विदेशी छात्रों से आवेदनों की कुल योग्य मानदण्डों पर संवीक्षा की जाती है । चयनित छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा गुरूओं से जुड़े हैं।

इस योजना की समीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

(क) स्लॉटों का उपयोग

यद्यपि इस योजना के अंतर्गत किसी भी समय छात्रों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती थी फिर भी परिषद वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक के लिए केवल क्रमशः 52, 35, 45, 49, 55 तथा 57 स्लॉटों का उपयोग कर सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्लॉटों का कम उपयोग इच्छुक छात्रों से आवेदन आमंत्रित करने (जैसा कि अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु किया जा रहा था) के संबंध में भारतीय मिशनों/पोस्ट को किसी भी सम्प्रेषण के अभाव के कारण था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि इसने विदेशों में संबंधित मिशनों के माध्यम से इस विशिष्ट छात्रवृत्ति योजना के विस्तृत प्रचार हेतु पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए थे।

(ख) देश-वार उपयोग

परिषद विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विभिन्न देशों को स्लॉटों की संख्या आंवटित करती है परंतु इस योजना में प्रत्येक देश के लिए स्लॉटों की संख्या निश्चित नहीं थी। स्लॉटों के देश-वार उपयोग के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि स्लॉटों का सार्थक रूप से बड़ा अनुपात (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 49.15 प्रतिशत) का उपयोग एक विशिष्ट देश अर्थात् श्रीलंका से छात्रों द्वारा किया गया था। इसने दर्शाया कि छात्रवृत्ति योजना को विषम प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि आवेदनों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर संसाधित किया गया था तथा पिछले वर्षों के दौरान, इस विशिष्ट योजना के अंतर्गत श्रीलंका द्वारा उपयोग किए गए स्लॉटों की संख्या उस देश से आवेदनों की बड़ी संख्या के कारण उच्च रही थी तथा उनका कार्य मानदण्डों तथा पूर्व प्रक्रिया के अनुसार था।

हालांकि, परिषद के उत्तर को इस तथ्य की दृष्टि से देखा जाए कि कई अन्य छात्रवृत्ति योजनाएँ, जो कि देश अथवा क्षेत्र विशिष्ट थीं, से अलग इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसी भी देश से छात्र द्वारा उठाया जा सकता था। वर्तमान प्रबंध सीमित था

क्योंकि इसने इस योजना के उपयोग को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित किया था।

(ग) छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु योजना मानदण्ड

छात्रवृत्ति योजना हेतु विदेशी छात्रों का चयन कुछ योग्यता मानदण्ड के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जैसा कि **तालिका-3** में वर्णित किया गया है। विभिन्न योग्यता मानदण्ड के प्रति छात्रों के चयन से संबंधित अभिलेखों (2006-07 से 2011-12 की अवधि हेतु कुल 116 मामलों में से यादृच्छिक रूप से चयनित 62 मामलों) की संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

तालिका-3: योग्यता मानदण्ड में अभ्युक्तियां

क्र.सं.	योग्यता मानदण्ड	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ
1.	अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता जैसा कि आवेदन प्रेषित करने वाले मिशन द्वारा प्रमाणित है।	16 छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति बिना अंग्रेजी प्रवीणता प्रमाणपत्रों के थी।
2.	पंजीकृत चिकित्सक द्वारा भौतिक स्वस्थता प्रमाणपत्र	तीन छात्रों के पास अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं था।
3.	संबंधित मिशन/केन्द्रों से प्रमाणपत्र की पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात अभ्यार्थी अपने देश वापस लौटेगा ।	19 छात्रों को मिशन से प्रमाणपत्रों के बिना छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
4.	संरचनाबद्व स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के वृत्ति छात्रों के पास पूर्ण अवधि छात्र वीजा होना चाहिए तथा पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों के वृत्ति छात्रों के पास 4-5 वर्षों की विशिष्ट अवधि हेतु अनुसंधान वीजा होना चाहिए।	16 छात्रों के मामले में वीजा तथा पासपोर्ट ब्यौरे तथा अन्य 16 छात्रों के मामले में केवल वीजा ब्यौरे अभिलेख में नहीं पाए गए थे।
5.	छात्रों को प्राथमिकता जिन्होंने भारत में कभी अध्ययन नहीं किया था।	11 मामलों में, वृत्ति-छात्रों ने पहले भी भारत में अध्ययन किया था ।

लेखापरीक्षा हेतु चयनित समग्र 62 मामलों में से 45 में योग्यता मानदण्ड को पूरा करने में एक अथवा अधिक समस्याएं थीं। इस प्रकार, परिषद ने उचित सचेतन के साथ छात्रवृत्ति आवेदनों की संवीक्षा नहीं की थी तथा उन अभ्यर्थियों का चयन किया जिन्होंने न्यूनतम मानदण्ड पूरा नहीं किया था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि अंग्रेजी निपुणता प्रमाणपत्रों के संबंध में मिशन अभ्यर्थी का साक्षात्कार अथवा परीक्षा लेकर निपुणता को प्रमाणित करने हेतु रीतियों का निर्णय करते हैं। उसने आगे बताया कि शब्द 'प्राथमिकता' भा.सां.सं.प. को उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रस्तावित करने से वर्जित नहीं करता है जिन्होंने पहले ही छात्रवृत्तियां प्राप्त

की हैं। तथापि, परिषद ने भविष्य में अनुपालना हेतु लेखापरीक्षा की अन्य अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा मिशनों द्वारा चुनी गई रीतियों पर आपत्ति नहीं कर रही है परंतु यह बताती है कि 16 छात्रों के अंग्रेजी निपुणता प्रमाणपत्र अभिलेख में नहीं थे।

अनुशंसाएं

- ❖ *भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना का तात्पर्य भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है जिसे भारतीय मिशनों के साथ संवर्धित संचार के माध्यम से अधिक प्रभावकारिता से कार्यान्वित किया जा सकता है।*
- ❖ *स्लॉटों के उपयोग को अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है।*
- ❖ *अभ्यार्थियों के चयन हेतु मानदण्ड की अतिसावधानी से अनुपालना की जानी चाहिए।*

1.2.2.2 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना (सा.वि.का.छा.यो.) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सा.वि.का.)/शिक्षा विनिमय कार्यक्रम (शि.वि.का.) पर आधारित है जिसे विभिन्न देशों के साथ भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया है। सा.वि.का./शि.वि.का. पारस्परिक रूप से सहमत नियमों एवं शर्तों, जिन्हें राजनायिक प्रणाली के माध्यम से तय किया गया है, पर सांस्कृतिक प्रोत्साहन अथवा शिक्षा सहयोग हेतु किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित करार है। करार आमतौर पर निर्धारित अवधि के लिए हैं।

इन करारों में भा.सां.सं.प. की भूमिका छात्रवृत्तियों के कार्यान्वयन तक सीमित है। प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षरित सा.वि.का./शि.वि.का. के नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिषद द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों को विभिन्न विषयों में छात्रवृत्तियां प्रस्तावित की गई हैं।सा.वि.का.छा.यो. के अन्तर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विभिन्न विषयों में डाक्टरेट अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

पिछले छः वर्षों के दौरान सां.वि.का.छा.यो के अंतर्गत उपलब्ध स्लॉटों के प्रति उपयोग किए गए स्लॉटो की स्थिति निम्नलिखित **तालिका-4** में दी गई है।

तालिका 4: उपयोग किए गए छात्रवृत्ति स्लॉटों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	आवंटित स्लॉट	उपयोग किए गए स्लाट	उपयोग किए गए स्लॉटों का प्रतिशत
2006-07	313	141	45.04
2007-08	330	140	42.42

वर्ष	आवंटित स्लॉट	उपयोग किए गए स्लाट	उपयोग किए गए स्लॉटों का प्रतिशत
2008-09	324	147	45.37
2009-10	318	138	43.30
2010-11	309	141	45.63
2011-12	306	131	42.81
योग	**1900**	**838**	**44.10**

उपरोक्त डाटा दर्शाता है कि छः वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत उपयोग किए गए स्लॉटों की प्रतिशतता 42.42 से 45.63 *प्रतिशत* के बीच थी। इसके अतिरिक्त, 14[9] देशों के संबंध में 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान किसी भी स्लॉट का उपयोग नहीं किया गया था जिसका परिणाम 158 स्लॉटो के अप्रयुक्त रहने में हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद ने 10[10] देशों के छात्रों हेतु 470 (कुल आंवटित स्लॉटों का 25 *प्रतिशत)*स्लॉट आवंटित किए जिनमें कोई वैध सा.वि.का./शि.वि.का. विद्यमान नहीं थे। इन 470 स्लॉटों में से, 227[11] अभ्यार्थियों को योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। दूसरी ओर परिषद ने साईप्रस (करार अवधि 2007-10) तथा न्यूजीलैण्ड (करार अवधि 2005-10) को कोई स्लॉट प्रस्तावित नहीं किए जिनके साथ भारत सरकार ने सा.वि.का./शि.वि.का. हस्ताक्षरित किया था। इस प्रकार परिषद यह सुनिश्चित करने में विफल रही कि छात्रवृत्तियॉ वैद्य सा.वि.का./शि.का. वाले देशों से छात्रों को प्रदान की गई है।

परिषद ने स्लॉटों के कम उपयोग के विभिन्न कारण आरोपित किए (फरवरी 2012) जैसे समय पर आवेदन की गैर-प्राप्ति, योग्यता मानदण्ड को पूरा न करना, विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध सीमित सीटें, विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. दाखिले की देरी से पुष्टिकरण आदि। परिषद के उत्तर ने स्लॉटों के कम उपयोग हेतु विभिन्न संभव कारणों को गिनवाया परंतु परिस्थिति को सुधारने हेतु उठाए गए कदमों को नहीं बताया था।

---

[9]कुवैत (6), नौर्वे (12), स्लोवॉक (12), बेहरेन (8), लाओस (12), अलजीरिया (12), नाइजिरिया (24), सेनेगल (6), टयूनिशिया (6), जिम्बाब्वे (12), खांडा (6), आस्ट्रेलिया (18), नीदरलैण्ड (18), तथा डी.पी.आर. कोरिया (6)

[10]ईराक (170), जापान (66), मंगोलिया (60), नाईजीरिया (24), पोलैण्ड (66), स्लोवॉक (12), दक्षिण कोरिया (12), स्पेन (30), टर्की (24), तथा यूक्रैन (6)

[11]ईराक (76), जापान (12), मंगोलिया (41), पोलैण्ड (58), दक्षिण कोरिया (12), स्पेन (19), टर्की (7) तथा यूक्रैन (2)

परिषद ने आगे बताया (सितम्बर 2012) कि भविष्य में छात्रवृत्तियां उन देशों को प्रस्तावित की जाएगी जिनके पास वैद्य सा.वि.का. विद्यमान है।

अनुशंसाएं

- ❖ *परिषद योजना के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सा.वि.का./शि.वि.का.के अंतर्गत स्लाटों के कम उपयोग के मामले मिशनों/पोस्ट के साथ उठाए।*
- ❖ *परिषद यह सुनिश्चित करें कि छात्रवृत्तियां उन देशों के छात्रों को प्रदान की गई हैं जिनके साथ करार विद्यमान है।*

1.2.3 वित्तीय प्रबंधन

1.2.3.1 बजट

बजट एक संगठन की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित व्यय को मॉनीटर तथा नियंत्रित करने हेतु एक साधन है। परिषद के संबंध में 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए बजट अनुमानों (ब.अ.), प्रस्तावित संशोधित अनुमानों (सं.अ.), वि.मं. द्वारा आवंटित निधियां तथा वास्तविक व्यय की वर्ष-वार स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है)।

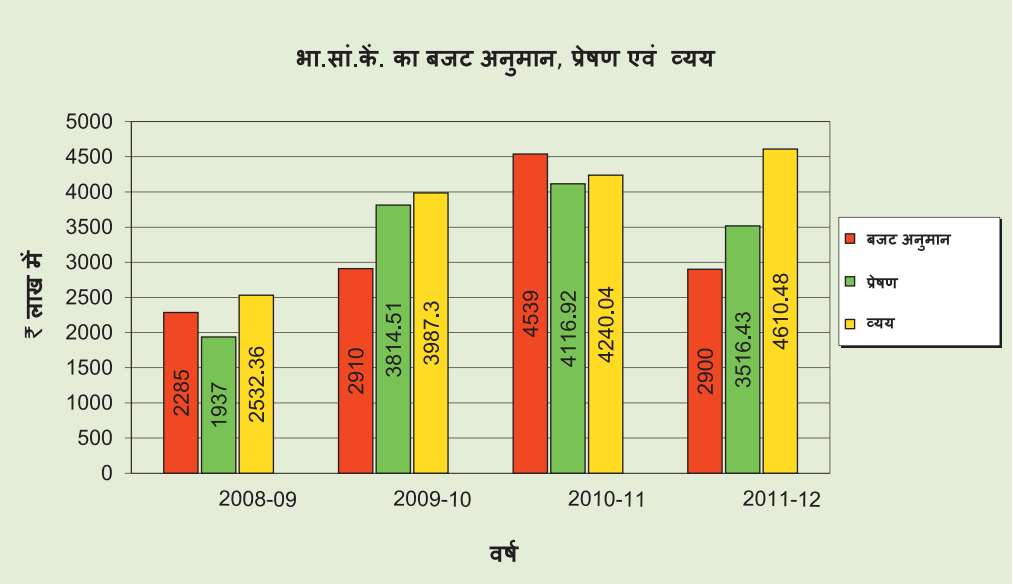
यह पाया गया है कि 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2011-12 के दौरान क्रमशः₹ 497.52 लाख,₹71.46लाख,₹182.11लाख, ₹3639.01 लाख के अधिक व्यय थे तथा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए क्रमशः₹ 890.88 लाख तथा ₹163.00 लाख की बचतें थी। मद 'निर्धारित प्रभारों' में 2008-09 से 2011-12 के दौरान 7.97 से 22.71 *प्रतिशत* के बीच निरंतर आधिक्य व्यय को दर्शाया। मद 'गतिविधियां' के अंतर्गत 2007-08 से 2009-10 के दौरान 1.63 से 18.20 प्रतिशत के बीच निरंतर बचतें थी। उपरोक्त ने बजटीय नियंत्रणों में कमियों को दर्शाया।

परिषद ने बताया (फरवरी 2013) कि 2011-12 के दौरान किए गए अधिक व्यय को भा.सां.सं.प. की स्वंय की प्राप्तियों तथा अभिकरण कार्यों हेतु विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से प्राप्त राशियों तथा इसके बकाया से पूरा किया गया था। परिषद का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि यह बजटीय नियंत्रण कमियों को उल्लेखित नहीं करता है।

1.2.3.2 विदेश में भा.सां.के. को धन प्रेषण

भा.सां.के. के लिए बजटीय अनुमान परिषद के मुख्यालय में तैयार किए जाते हैं। परिषद, वि.मं. के माध्यम से, भा.सां.के. को स्थापना तथा गतिविधि व्ययों को पूरा करने के लिए

तिमाही किस्तों में निधियां अंतरित करती है। 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों, भा.सां.के. को किए गए धन- प्रेषणों तथा विदेश में किए गए वास्तविक व्यय को नीचे दर्शाया गया है:



डाटा के विश्लेषण (**अनुबंध-II**में ब्यौरे) ने निम्नलिखित प्रकट किया -

क. बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय में विचलन - चार में से तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 एवं 2011-12) में 10.80 से 58.96 *प्रतिशत* के बीच बजट अनुमानों से अधिक व्यय था।

ख. धन प्रेषणों की कमी - प्रेषित निधियां सभी चार वर्षों में 3.01 से 31.11 *प्रतिशत* के बीच वास्तविक व्यय से कम थी। कमी को संबंधित मिशन की निधियों से पूरा किया गया था।

ग. धन प्रेषणों को विलम्ब से जारी करना - 2008-09 के दौरान तीन भा.सा.के. (जकार्ता, बीजिंग तथा पोर्ट ऑफ स्पेन), 2010-11 के दौरान दो भा.सां.के. (कोलम्बों तथा बैकांक) तथा 2011-12 के दौरान चार भा.सां.के. (काबुल, अलमेटी, कैरो तथा बाली) में कुल धन प्रेषणों के 40 *प्रतिशत* अथवा अधिक को वित्तीय वर्ष के अंतिम माह/ तिमाही के दौरान जारी किया गया था। विलम्बित धन प्रेषणों ने उनके कार्यों को प्रभावित किया।

घ. भा.सां.के. को बजट आवंटन की सूचना - वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भा.सां.के. को बजटीय आवंटन के संबंध में कोई सूचना नहीं थी जबकि वर्ष 2010-11 के लिए सूचना सितम्बर 2010 में दी गई थी।

वित्त समिति ने यह भी निर्देशित किया (फरवरी 2005) कि दिशानिर्देश तैयार किए जाएं जिसने इस पर बल दिया कि सभी भा.सां.के. को सूचित बजट अनुमान अधिक नहीं होने चाहिए। परिषद की पूर्व अनुमति के बिना बजट आवंटन में से किसी प्रकार का विचलन नहीं किया होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे।

यह पाया गया था कि परिषद वास्तविक आधार पर बजटों को तैयार नही कर रही थी और ना ही अपने भा.सां.के. को बजटों के आधार पर तथा समय पर निधियों का प्रेषण कर रही थी। इस प्रकार परिषद वित्तीय अनुशासन के लिए किसी बजटीय क्रियाविधि का उपयोग नहीं कर रही थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि कम किए गए अनुदान के कारण यह भा.सां.के. की ओर से धन का व्यय करता है तथा बाद में अधिक आहरण को वि.मं. द्वारा अनुदान के अनुवर्ती निर्गम में से समायोजित किया जाता है। परिषद ने आगे बताया (फरवरी 2012) कि विदेश में भा.सां.के. हेतु दिशानिर्देश सक्रिय विचाराधीन थे तथा जल्द ही कार्यान्वित किए जाएंगे।

अनुशंसाएं

- ❖ *बजट को वास्तविक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु वास्तविक व्यय को आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाना चाहिए।*
- ❖ *भां.सा.के. को बजट आवंटन की सामयिक सूचना तथा प्रेषण उनके प्रभावी कार्य हेतु आवश्यक है।*

1.2.3.3 विदेश में नए भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (भा.सां.के.) खोलना

वित्त मंत्रालय ने अपने बजट भाषण (मार्च 2008) में भारत की 'मधुर शक्ति' परियोजना, जो कि विश्व में संगीत, साहित्य, नृत्य, कला, भोजन तथा चलचित्र हैं, हेतु ₹ 75 करोड़ की एक अतिरिक्त राशि उदृष्टि की। परिषद ने एक विस्तार योजना तैयार की (मई 2008) जिसमें 14 नए भा.सां.के. को खोलना शामिल था जो वि.मं. द्वारा स्वीकृत था। गैर-योजना व्यय समिति, वित्त मंत्रालय ने भी निम्नलिखित शर्तों के तहत विस्तार योजना स्वीकृत की (फरवरी 2009):

- ₹75 करोड़ का अनुदान एक बार का अनुदान होगा तथा आवर्ती व्यय को भविष्य में वि.मं. के बजट में से पूरा किया जाएगा;
- कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एक वर्ष के पश्चात किया जाएगा; तथा
- बदलाव उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर किये जाएंगे।

परिषद ने 2009 तथा 2011 के बीच स्वीकृत विस्तार योजना के अनुसार 14 नए भा.सां.के. खोले। तथापि, इनके अतिरिक्त परिषद द्वारा अगस्त 2010 तथा अक्तूबर 2011 के बीच प्राग, बुडापेस्ट तथा हेग में तीन और भा.सां.के. खोले गए थे। इसके अतिरिक्त, आठ और भा.सां.के. खोले जाने की प्रक्रिया में थे (मार्च 2012)। चूंकि भा.सां.के. के खोले जाने में अतिरिक्त वित्तीय भार तथा पदों का सृजन शामिल है इसलिए वि.मं. के साथ-साथ वित्त मंत्रालय (वि.मं.) से विशिष्ट स्वीकृति अपेक्षित है जो इन अतिरिक्त भा.सां.के. हेतु प्राप्त नहीं की गई थी। 14 स्वीकृत भा.सां.के. का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

परिषद ने बताया (दिसम्बर 2011 तथा सितम्बर 2012) कि संबंधित मिशनों की सिफारिश पर परिषद के सक्षम प्राधिकारियों ने नए भा.सां.के. खोलने का निर्णय लिया था। उसने आगे बताया कि भा.सां.के. के खोले जाने संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों, को नए भा.सां.के. के खोले जाने को संसाधित करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

परिषद का उत्तर, कि संबंधित मिशनों की सिफारिश पर नए अतिरिक्त केन्द्र खोले गए थे, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

अनुशंसा

- *भा.सां.सं.प. को नए भा.सां.के. खोलने से पहले विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय की आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी चाहिए।*

1.2.4 श्रमशक्ति प्रबंधन

1.2.4.1 कर्मचारी बल

मार्च 2012 को परिषद (विदेश में भा.सां.के. तथा भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) का कर्मचारी बल **तालिका-5** में दिया गया है। सभी पद वित्त मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत हैं।

तालिका 5: संस्वीकृत बल, तैनात कर्मचारी तथा कमी की स्थिति

वर्ग	संस्वीकृति पद	तैनात कर्मचारी	कमी (-)
क	78	68	(-) 10
ख	53	36	(-) 17
ग	120	109	(-) 11

परिषद में श्रमशक्ति प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों की जांच ने निम्नलिखित प्रकट किया:

1.2.4.2 विदेश में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में निदेशकों की नियुक्ति

भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जानकारी तथा प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने विदेश में 37 भा.सां.के. का अनुरक्षण किया (मार्च 2012) जिनकी अध्यक्षता निदेशकों द्वारा की जाती है। निदेशक के पद भा.सां.सं.प. केडर, वि.मं. केडर तथा बाह्य व्यक्तियों द्वारा मानवित हैं। वि.मं. केडर से संबंधित अधिकारियों का वि.मं. द्वारा चयन किया जाता है जबकि बाह्य व्यक्तियों तथा जो भा.सां.सं.प. केडर से संबंधित है उनका चयन भा.सां.सं.प. द्वारा किया जाता है तथा अंततः वि.मं. द्वारा स्वीकृत किया जाता है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 16 बाह्य व्यक्तियों (**अनुबंध-III**), भा.सां.सं.प. केडर से संबंधित 20 व्यक्तियों तथा वि.मं. केडर से संबंधित 8 व्यक्तियों ने विदेश में विभिन्न भा.सां.के. में निदेशक के पद ग्रहण किए।

क. निदेशक की संस्वीकृत संख्या

परिषद में निदेशक के तीन पदों की संस्वीकृत संख्या थी (मार्च 2012)। सभी तीनों पद परिषद मुख्यालय/भारत में क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने स्वयं के केडर से भरे गए थे। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है कि परिषद विदेश में अपने सांस्कृतिक केन्द्रों में निदेशक, भा.सां.के. के पदों का संचालन कर रही थी जिन्हें भा.सां.सं.प. केडर, वि.मं. केडर के स्टाफ तथा बाह्य व्यक्तियों द्वारा भरा गया था परंतु परिषद ने इन पदों को अपनी संस्वीकृत संख्या में नहीं दर्शाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक मामले[12] में (अप्रैल 2004), परिषद ने निदेशक, भा.सां.के. के पद को नियमित करने हेतु वि.मं. को सिफारिश की थी। तथापि, वि.मं. ने परिषद को सीधे वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाने का निर्देश दिया। आगे की कोई प्रगति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। परिषद ने भा.सां.के. के निदेशक के अतिरिक्त पदों के सृजन का मामला (दिसम्बर 2010) पुनः उठाया परंतु फिर से यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा पदों के सृजन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वि.मं. द्वारा भी स्वीकृत नहीं किया गया था।

---

[12]जकार्ता में जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक के लिए परिषद ने निदेशक के एक पद को संस्वीकृत करने का अनुरोध करते हुए वि.मं. को अप्रैल 2004 में सिफारिश की। चूंकि वि.मं. विदेश में भा.सां.के. में पद के सृजन अथवा उन्नयन में शामिल नहीं था इसलिए वि.मं. द्वारा परिषद को सूचित किया गया था कि परिषद द्वारा मामला सीधे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाए।

वि.मं. तथा भा.सां.सं.प. केडर के अधिकारियों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 12 भा.सां.के. में निदेशक के पदों को 16 बाह्य व्यक्तियों द्वारा भरा गया था (**अनुबंध-III**)। परिषद ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इन बाह्य व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते पर ₹6.11 करोड़ का व्यय किया था। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं जैसा किराया मुक्त आवास, चिकित्सा भत्ता, बाल अवकाश यात्रा, सामाजिक स्थानातंरण अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, आर.जी. भी अदा की जा रही थी। पदों की उचित संस्वीकृति बिना निदेशक भा.सा.के. के पदों का संचालन तथा उस पर व्यय करना अनियमित था।

परिषद ने बताया (फरवरी 2012) कि विदेश में भा.सां.के. में निदेशकों की नियुक्ति भा.सां.स.प. के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति से की गई थी। इसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अभ्युक्तियों को नए निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा तथा अगर आवश्यकता हुई, दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे। तथापि उत्तर मौन था कि इन मामलों में वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त क्यों नहीं की गई।

ख. बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.सां.के. निदेशक के रूप में बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे। बाह्य व्यक्तियों के चयन हेतु किसी प्रक्रिया का अनुपालन किया भी प्रकट नहीं होता है। लेखापरीक्षा में जांच किए गए सभी 16 मामलों में रिक्तियों के प्रसार, प्राप्त तथा विचार किए गए अवेदनों की संख्या में कोई पत्राचार नहीं था। परिणामस्वरूप, विदेश में निदेशक भा.सां.के. के रूप में बाह्य व्यक्तियों के चयन में पारदर्शिता की कमी स्पष्ट थी।

इसके अतिरिक्त, बाह्य व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालयों/अन्य सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे थे, को निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रदान किए गए वेतनमान तथा पद उनके मूल कार्यालय में उनके वर्तमान वेतनमान के आधार पर थे। परंतु परिषद द्वारा निजी क्षेत्रों से आ रहे बाह्य व्यक्तियों को वेतनमान तथा पद प्रदान करने हेतु कोई दिशानिर्देश अथवा मानदण्ड तैयार नहीं किए गए थे जिसका परिणाम एक ही पद के लिए अलग ग्रेड पे तथा गरिमा प्रदान करने में हुआ जैसा **तालिका 6** में दर्शाया गया है:

तालिका 6: निदेशक, भा.सां.के. रूप में बाह्य व्यक्ति के वेतनमान तथा पद

क्र.सं.	निदेशक का नाम तथा निजी क्षेत्र में उनकी भूमिका	प्रदान किया गया वेतनमान	प्रदान किया गया पद
1.	श्री अरूप कुमार दत्ता (पत्रकार)	₹14300-400-₹18300(पूर्व संशोधित) ₹37400-₹67000₹8700 के ग्रे.वे. सहित (जनवरी 2006 से प्रभावी)	कौंसलर
2.	सुश्री रेणुका नारायण (पत्रकार)	₹15600-₹39100 ₹7600के ग्रे.वे. सहित	प्रथम सचिव

क्र.सं.	निदेशक का नाम तथा निजी क्षेत्र में उनकी भूमिका	प्रदान किया गया वेतनमान	प्रदान किया गया पद
3.	सुश्री गीती सेन (पत्रकार)	₹15600-₹39100 ₹7600के ग्रे.वे. सहित	प्रथम सचिव
4.	श्री राजेश मेहता (अकेडिमीशियन)	₹15600-₹39100 ₹6600के ग्रे.वे. सहित	द्वितीय सचिव

परिषद ने बताया (फरवरी 2012) कि निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए तीन बाह्य व्यक्ति, निजी अभिकरणों के लिए कार्य कर रहे पत्रकार थे तथा उनके वेतन को निजी क्षेत्र में उनकी कमाई के अनुसार निर्धारित किया गया था। परिषद ने आगे बताया (सितम्बर 2012) कि भा.सां.के हेतु निदेशकों के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देशों/मानदण्डों का निरूपण कर लिया गया है जिसे सांविधिक निकाय तथा वि.मं. की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

परिषद द्वारा प्रदान कारण उचित नहीं है क्योंकि सरकार में नियुक्ति निजी क्षेत्रों में उनकी स्थिति को ध्यान में न रखते हुए, संबंधित नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

अनुशंसाएं

- ❖ *परिषद को भा.सां.के. में निदेशकों के पद के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय की पूर्व संस्वीकृति की मांग करनी चाहिए।*
- ❖ *परिषद को निदेशक, भा.सां.के. की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश तथा नियम एवं शर्तें तैयार करनी चाहिए तथा चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए।*

1.2.4.3 क्षेत्रीय कार्यालयों में श्रमशक्ति प्रबंधन

परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय विदेशी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना[13] कार्यान्वित करते हैं, स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने हेतु एक मंच प्रदान करते हैं तथा विदेशी मण्डलियों का उनके प्रदर्शनों का प्रबंध करने का ध्यान रखते हैं। अंतराष्ट्रीय छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में आगमन पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत, छात्रवृत्ति का भुगतान, आवास स्थान में सहायता, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ संपर्क, बैंक खाता खोलना, प्रगति रिपोर्टों की मॉनीटरिंग, छात्रों के डाटा बैंक का अनुरक्षण आदि शामिल है।

---

[13]छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियॉ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लेखा-विद्या, व्यवसाय प्रशासन तथा प्रबंधन में हैं। छात्रवृत्तियां भारतीय नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला आदि सीखने के लिए भी प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा में वर्तमान कार्यभार के संबंध में क्षे.का. में श्रमशक्ति के उपयोग की समीक्षा की गई थी। चार वर्षों (2008-09 से 2011-12) के दौरान नियुक्त संस्वीकृत कर्मचारी द्वारा कार्यान्वित की गई छात्रवृत्तियों की औसत संख्या तथा क्षे.का. द्वारा औसत वार्षिक व्यय की तुलना के आधार पर विश्लेषण किया गया। स्थिति **तालिका-7** में दर्शाई गई है:

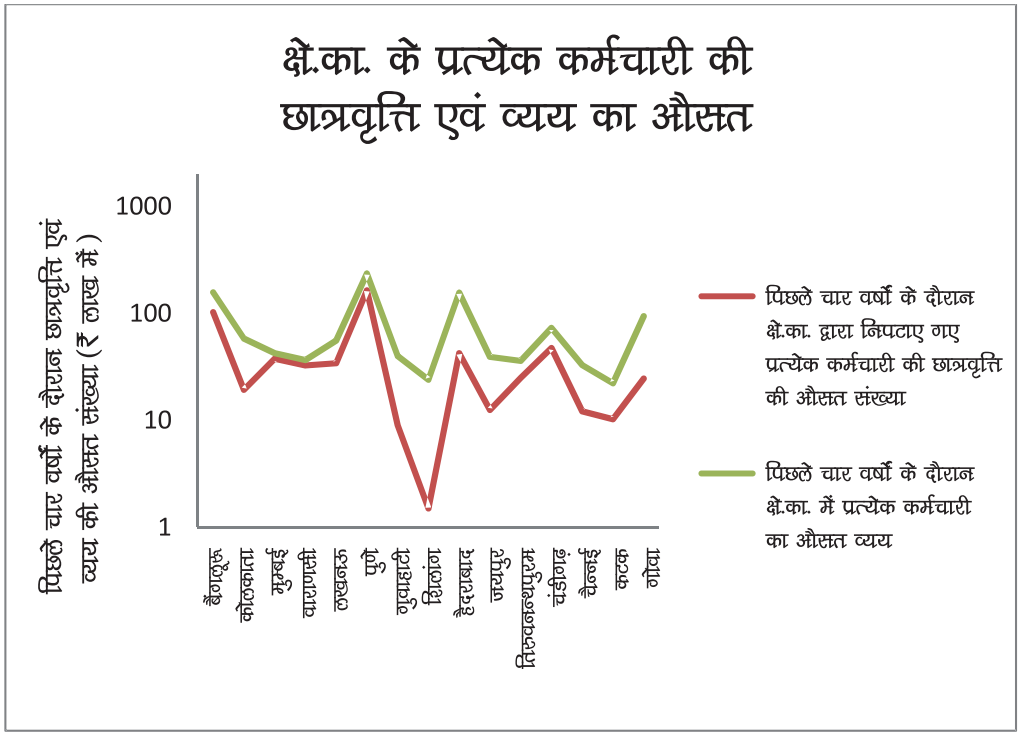
तालिका 7:संस्वीकृत कर्मचारी औसतन संख्या, छात्रवृत्ति तथा व्यय की तुलना

क्रं. सं.	क्षे.का. का नाम	संस्वीकृत कर्मचारी संख्या (अपने +आउटसोर्स)[14]	पिछले चार वर्षों के दौरान क्षे.का. द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की औसतन संख्या	पिछले चार वर्षों के दौरान क्षे.का. द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की गई प्रति कर्मचारी छात्रवृत्तियों की औसतन संख्या	पिछले चार वर्षों के दौरान क्षे.का. का औसतन व्यय (₹ लाख में)	पिछले चार वर्षों के दौरान क्षे.का. में प्रति कर्मचारी औसतन व्यय (₹ लाख में)
1.	बैंगलूरू	6 (4 + 2)	616	102.67	946	157.66
2.	कोलकाता	9 (1 +8)	174	19.33	524	58.22
3.	मुंबई	6 (4 + 2)	226	37.66	255	42.5
4.	वाराणसी	3(1 +2)	98	32.66	110	36.66
5.	लखनऊ	4 (3 + 1)	137	34.25	223	55.75
6.	पुणे	6 (2 + 4)	986	164.33	1419	236.5
7.	गुवाहाटी	3 (1 + 2)	18	9	120	40
8.	शिलांग	2(1+1)	03	1.5	48	24
9.	हैदराबाद	6(3 + 3)	255	42.5	939	156.5
10.	जयपुर	4 (2 + 2)	50	12.5	157	39.25
11.	तिरूवनन्तपुरम	4 (3 + 1)	100	25	144	36
12.	चण्डीगढ़	4 (स्वयं स्टाफ)	190	47.5	293	73.25
13.	चैन्नई	7(स्वयं स्टाफ)	85	12.14	230	32.85
14.	कटक	4(1 + 3)	41	10.25	89	22.25
15.	गोवा	3 (0 + 3)	74[15]	24.66	283	94.33

[14]लिपिक एवं उससे ऊपर

यह पाया गया था कि बैंगलूरू, मुंबई, पुणे तथा हैदराबद में क्षे.का. की संस्वीकृत कर्मचारी संख्या बराबर थी परंतु इन कार्यालयों द्वारा संचालित कार्य में बड़ी विभिन्नताएं थीं। जबकि पुणे कार्यालय ने प्रतिवर्ष 986 छात्रवृत्तियों की औसतन संख्या का संचालन किया, अन्य क्षे.का. अर्थात् मुंबई, बैंगलोर तथा हैदराबद ने क्रमशः 226, 616 तथा 255 वार्षिक छात्रवृत्तियों का संचालन किया। पुणे क्षे.का. का औसतन व्यय ₹1419 लाख था जबकि तीन अन्य क्षे.का. का व्यय क्रमशः ₹255 लाख, ₹946 लाख तथा ₹939 लाख था। चैन्नई कार्यालय में भा.सां.सं.प. के स्वयं के स्टाफ की अधिकतम संख्या थी परंतु वार्षिक रूप से संचालित छात्रवृत्तियों की औसतन संख्या केवल 85 थी।

इसके अतिरिक्त, क्षे.का में प्रति कर्मचारी संचालित छात्रवृत्तियों की औसतन संख्या तथा प्रति कर्मचारी औसतन व्यय ने बड़ी विभिन्नताएं प्रदर्शित की जो क्रमशः दो से 164 तथा ₹22.25 लाख से ₹236.50 लाख के बीच थीं जैसा नीचे दर्शाया गया है:



[15]आंकड़े वर्ष 2011-12 से संबंधित (नया खुला क्षेत्रीय कार्यालय)

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षे.का. का संचालन विभिन्न स्तरों के अधिकारियों[16] द्वारा किया जा रहा था। पुणे क्षे.का., जिसने दोनों, संचालित छात्रवृत्तियों की संख्या तथा व्यय की राशि के अधिकतम परिणाम में सहयोग दिया, की अध्यक्षता कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की गई थी जबकि चैन्नई क्षे.का. में, जहाँ कार्य सार्थक रूप से कम था, क्षे.का. की अध्यक्षता एक निदेशक[17]/कार्यक्रम निदेशक की श्रेणी के अधिकारी द्वारा की गई थी।

इस प्रकार विभिन्न क्षे.का. के लिए संख्या तथा श्रेणी के अनुसार श्रमशक्ति वितरण उनके कार्यभार के अनुरूप नहीं था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि वित्त् मंत्रालय से पदों की लंबित स्वीकृति के कारण विभिन्न क्षे.का. में अस्थायी प्रबंधन तथा नियुक्ति का परिणाम, नियुक्त अधिकारियों के पदों के बेमेल होने में हुआ। परिषद ने आगे बताया कि मामले की स्वीकृति की प्राप्ति पर जल्द ही निपटान किया जाएगा तथा लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसाओं के अनुसार भा.सां.सं.प. द्वारा समीक्षा की जाएगी।

अनुशंसा

- ❖ *परिषद संख्या के साथ-साथ पद के अनुसार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त मानव संसाधन की तुलना में वर्तमान कार्य भार की समीक्षा करें।*

1.2.5 प्रदर्शनियों की प्रायोजकता हेतु कलाकार का चयन

विदेश में प्रदर्शन हेतु कलाकारों तथा प्रदर्शनियों हेतु कलाकारों तथा/अथवा सामग्री भेजना परिषद के दो आवश्यक कार्य थे। प्रदर्शन के लिए विदेश में कलाकारों को भेजने के लिए परिषद ने सूचीबद्ध क्रियाविधि निर्धारित की थी। परंतु प्रदर्शनियों के मामले में, यह पाया गया था कि कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी। कलाकार, जो विदेश में अपनी रचनाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वित्तीय सहायता हेतु सीधे परिषद से संपर्क करते हैं। वह परिषद को सूचित करेंगे कि उन्हें प्रदर्शनी के स्थान पर उनकी रचनाओं को दर्शाने हेतु आमंत्रित किया गया था।

---

[16]सहायक कार्यक्रम अधिकारी (ग्रेड वेतन-₹ 4600/-), कार्यक्रम अधिकारी (ग्रेड वेतन-₹5400/-), कार्यक्रम निदेशक (ग्रेड वेतन ₹6600/-), वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक (ग्रेड वेतन- ₹7600/-), निदेशक (ग्रेड वेतन- ₹8700/-)

[17]2010-11 तक निदेशक श्रेणी के अधिकारी तथा 2011-12 के आगे कार्यकम निदेशक श्रेणी के अधिकारी

परिषद द्वारा प्रायोजित सभी 20 प्रदर्शिनियों (परिषद द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक की सहायता सहित) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विदेश में प्रदर्शनियों हेतु परिषद द्वारा ₹ 2.00 लाख से ₹8.00 लाख के बीच व्यय किया गया था। परिषद ने विदेश में प्रदर्शनियों हेतु कलाकारों की पात्रता के लिए नियम, विनियम अथवा मानदण्ड तैयार नहीं किए थे। लेखापरीक्षा ने कलाकारों को प्रदान सुविधाओं में व्यापक विचलन भी पाए जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(क) सात मामलों में, कलाकारों तथा उनके साथ जा रहे व्यक्तियों को 20 इकोनोमी श्रेणी के हवाई टिकट प्रदान किए गए थे। जबकि चार[18] अन्य मामलों में कलाकारों/ क्युरेटरों/आयोजन ऐजेन्टों को 10 व्यवसायिक श्रेणी के हवाई टिकट प्रदान किए गए थे।

(ख) 17 मामलों में मेजबान देश में आवास अन्य सुविधाएं परिषद द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं परंतु तीन मामलों में ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

(ग) 11 मामलों में परिषद ने व्यय की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच किए बिना प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु कलाकार/एजेंसी को एकमुश्त अनुदान प्रदान किए।

इस प्रकार प्रदर्शनियों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाओं/वित्तीय सहायता के लिए मानदण्ड़ों के अभाव के अतिरिक्त पारदर्शिता की कमी थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि इकोनोमी श्रेणी अथवा व्यवसायिक श्रेणी की हवाई टिकट प्रदान करने के संबंध में निर्णय कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर लिया गया था। उत्तर ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में कलाकारों की वरिष्ठता कैसे निर्धारित की गई थी।

अनुशंसा

- ❖ *परिषद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हेतु कलाकारों के चयन तथा उसके लिए वित्तीय सहायता हेतु उपयुक्त मानदण्ड तैयार करे।*

1.2.6 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण किसी संस्था की प्रबंधन प्रक्रिया का वो अभिन्न अंग है जो कि यथोचित आश्वासन देता है कि कार्य प्रभावी रूप से तथा दक्षता से किए गए हैं, कि वित्तीय रिपोर्ट तथा परिचालनात्मक डाटा व्यवहार्य है तथा कि लागू नियमों तथा

---

[18]पेरिस लोर्वे कार्सेल-2010-11, सत्यग्रह-2008-09, श्रुति प्रतिष्ठान द्वारा संस्कृति कला गैलरी में कला शिविर हेतु प्रदर्शनी-2011-12 तथा श्री. जतिन दास द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी 2011-12

विनियमों की अनुपालना की गई हैं, जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण से संबंधित लेखापरीक्षा संवीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

1.2.6.1 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल को विदेश भेजा गया

परिषद की वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के अनुसार, महानिदेशक ₹ 15 लाख तक के व्यय को स्वीकृत करने हेतु सक्षम थे तथा ₹15 लाख से अधिक के व्यय हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति अपेक्षित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डलों को विदेश भेजे जाने से संबंधित वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान 41 यात्रा कार्यक्रमों जहाँ समूह की हवाई यात्रा, भोजनव्यवस्था, निवास तथा दैनिक भत्ता पर कुल व्यय ₹ 15 लाख से अधिक था, में से 34 मामलों में अध्यक्ष, भा.सां.स.प. की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि परिषद ने या तो प्रस्तावों को विभाजित करने का सहारा लिया था या फिर हवाई यात्रा, दैनिक भत्ता आदि पर अनुमानित व्यय को शामिल नहीं किया था। इसलिए 2009-10 से 2011-12 के दौरान 70 देशों में भेजे गए 34 प्रतिनिधिमण्डलों पर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के अभाव में ₹ 8.15 करोड़ का व्यय अप्राधिकृत था (**अनुबंध-IV**)।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि बाहर जा रहे समूह के लिए हवाई किराये, मानदेय आदि हेतु प्रस्ताव पिछली प्रक्रिया के अनुसार अलग से प्रस्तुत किए गए हैं। परिषद ने आगे बताया कि प्रत्येक अनुभागों के बजट अनुमानों की स्वीकृति के दौरान, बाहर जा रहे प्रतिनिधि मण्डलों के बजट अनुमानों की अध्यक्ष, भा.सां.सं.प. की स्वीकृति थी।

परिषद के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि परिषद द्वारा अपनाई गई प्रकिया उच्च्तर प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने का कारण बनी। आगे अक्तूबर 2012 में, परिषद को बाहर जा रहे सांस्कृतिक प्रतिनिधमण्डलों के बजट अनुमानों की अध्यक्ष, भा.सां.सं.प. की स्वीकृति से संबंधित लेखापरीक्षा हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परंतु परिषद ने ऐसे दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे।

अनुशंसा

❖ *परिषद को सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलों की स्वीकृतियां प्रदान करने हेतु वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन में निर्धारित सीमाओं का अनुपालन करना चाहिए।*

1.2.6.2 इवेन्ट का आयोजन करने हेतु सेवाओं का प्रापण

परिषद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न इवेन्टो (प्रदर्शनियों तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन) का आयोजन करने के लिए विभिन्न सेवाओं का प्रापण करती है। सा.वि.नि. तथा सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के विभिन्न प्रावधान अपेक्षा करते हैं कि धन का उचित मूल्य अर्जित करने के लिए सभी खरीद पारदर्शी, प्रतियोगितात्मक तथा स्पष्ट रूप से की जाए। वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹20 लाख से अधिक की सेवाओं के प्रापण (**अनुबंध-V**) से संबंधित ₹11.54 करोड़ के कुल भुगतान वाले सभी 18 मामलों की जांच ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

क. सा.वि.नि. के नियम 179 के अंतर्गत, मंत्रालय अथवा विभाग को समान कार्य में लीन अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से औपचारिक अथवा अनौपचारिक जांच 'येलो पेजस' तथा व्यापार जर्नलों की संवीक्षा, वेबसाईट आदि के आधार पर संभाव्य अथवा संभावित ठेकेदारों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। 18 नमूना जांच किए गए मामलों में से 17 ने प्रकट किया कि परिषद ने समान कार्यों में लीन संभाव्य एवं संभावित ठेकेदारों की सूची तैयार नहीं की थी।

ख. सा.वि.नि. का नियम 180 निविदा जांच तैयार करना अपेक्षित करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i)ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य अथवा सेवा का ब्यौरा, (ii) मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा ठेकेदार को प्रदत्त सुविधाएं तथा निवेश, (iii) अपेक्षित कार्य/सेवा को पूरा करने हेतु ठेकेदार द्वारा पूरी की जाने वाली पात्रता तथा योजना योग्यता मापदण्ड, तथा (iv) ठेकेदार द्वारा अनुपालन की जाने वाली सांविधिक तथा संविदात्मक बाध्यताएं शामिल होनी चाहिए।

तथापि, यह पाया गया था कि 18 में से 15 मामलों में न तो संविदा जांच की गई थी और न ही विक्रेता/विभाग की संविदात्मक एवं सांविधिक बाध्यताएं सूचित की गई थी।

ग. सा.वि.नि. का नियम 184 बताता है कि जहाँ यह बहुत आवश्यक हो, विशेष मामले में, विशिष्ट रूप से चयनित ठेकेदार को कार्य दिया जा सकता है अगर मंत्रालय अथवा विभाग में सक्षम प्राधिकारी ऐसा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से करते हैं। ऐसे मामलों में, विस्तृत, औचित्य, परिस्थितियां जो चयन द्वारा आउटसोर्सिंग का कारण बनी

तथा विशेष रूचि अथवा उद्देश्य जो यह पूरा करेगा, प्रस्ताव का एक अनिवार्य भाग बनेगा।

परिषद ने नियम के उल्लंघन में 18 में से 16 मामलों में अभिलेख में कोई विस्तृत औचित्य प्रदान किए बिना एकल स्रोत आधार पर विक्रेताओं के चयन का सहारा लिया।

घ. नियम 204 (iv)(ग) के अनुसार, एक संविदा दस्तावेज को ₹10 लाख तथा अधिक की अनुमानित कीमत वाले कार्यों के संबंध में इसे एक स्वयं-अन्तर्विष्ट संविदा बनाने हेतु सभी आवश्यक धाराओं के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। नियम का उल्लंघन करते हुए सभी 18 परीक्षित मामलों में कार्यों के निष्पादन हेतु फर्मों के साथ परिषद ने अनुबंध नहीं किया था।

ङ नियम 159 के अंतर्गत, सामान्यरूप से प्रदान की गई सेवाओं हेतु भुगतानों को केवल सेवाएं प्रदान किए जाने के पश्चात ही जारी किया जाना चाहिए। तथापि, कुछ मामलों में निजी फर्मों को अग्रिम भुगतान करना आवश्यक हो जाता है तो यह संविदा मूल्य के तीस *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त के अनुसार अग्रिम भुगतान करते समय बैंक गांरटी आदि के रूप में पर्याप्त अभयपत्र फर्म से प्राप्त किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नियम के उल्लंघन में, बैंक गारंटी अथवा निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त किए बिना अथवा सक्षम प्राधिकारी से नियम में छूट की मांग किए बिना फर्मों को अनुमानित लागत के 30 *प्रतिशत* से अधिक के अग्रिम भुगतान किए गए थे।

परिषद ने प्रक्रिया के रूप में निजी अभिकरणों से सेवाएं तथा कार्यों के प्रापण हेतु विज्ञापन जारी नहीं किए थे। परिषद ने कार्य को सौंपने हेतु अभिकरणों के एकल स्रोत चयन के लिए निर्धारित उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया था इसलिए फर्मों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया। सा.वि.नि./संस्वीकृति पत्रों की विभिन्न शर्तों पर ध्यान न देने के बावजूद परिषद ने मंत्रालय को प्रमाणित किया (फरवरी 2008 तथा जनवरी 2010) कि शर्तों का अनुपालन किया गया था।

इसी प्रकार वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान ₹ 20 लाख से अधिक की सेवाओं के प्रापण से संबंधित ₹11.54 करोड़ के कुल भुगतान वाले 18 मामलों के भुगतान वाउचरों की संवीक्षा ने मदवार दरों को अंकित न करना, सहायक दस्तावेजों को संलग्न न करना, इनवॉईस संख्या न होना तथा सर्विस टैक्स संख्या न होने के विवरणों का ब्यौरा (**अनुबंध-VI**)में दिया गया है। छः मामलों में परिषद द्वारा फर्मों को किए गए भुगतान में से ₹ 4.19 लाख की राशि के करों की कटौती नहीं की गई थी (**अनुबंध-VII**)।

इस प्रकार, परिषद में प्रापण तथा भुगतान हेतु बिलों के संसाधन में बड़ी कमियां थीं।

परिषद ने बताया (जनवरी 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर विषयों को भविष्य में अनुपालना हेतु दर्ज कर लिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सां.वि.नि. के प्रावधानों की निरंतर अनुपालना की गई है।

1.2.6.3 हवाई यात्रा में अनियमितताएं

जैसा कि हवाई यात्रा के सभी मामलों, जहाँ भारत सरकार हवाई यात्रा की लागत करती है, में वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश (जुलाई 2009) दिया गया है कि संबंधित अधिकारी केवल एअर इंडिया से ही यात्रा करें। यह आदेश भारत सरकार द्वारा निधीयन स्वायत्त निकायों में अधिकारियों पर भी लागू थे। विचलन के मामलों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से छूट की मांग की जानी थी। वित्त मंत्रालय ने आगे निर्देश दिया (सितम्बर 2010) कि हवाई टिकट सीधे एअर इंडिया अथवा प्राधिकृत यात्रा एजेन्ट अर्थात् मेसर्स बालमर लोरी एण्ड कम्पनी अथवा मेसर्स अशोक ट्रैवलस एण्ड टूर्स के माध्यम से खरीदी जानी चाहिए।

2009-12 के दौरान 98.32 *प्रतिशत* व्यय एअर इंडिया के अलावा अन्य एअरलाईनों द्वारा हवाई यात्रा पर किया गया था तथा केवल 1.68 *प्रतिशत* हवाई यात्रा व्यय एअर इंडिया से संबंधित था जिसने सरकार के नीति निर्देशों में असामानता को दर्शाया।

यह भी पाया था कि परिषद द्वारा सांस्कृतिक समूहों तथा स्टाफ का हवाई टिकट पैनल के हवाई यात्रा ऐजेन्टों के माध्यम से कराया गया था। 2009-10 से 2011-12 के दौरान, परिषद द्वारा ₹ 35.59 करोड़ का व्यय प्रदर्शनों तथा प्रदर्शनियों हेतु सांस्कृतिक समूहों तथा स्टाफ की हवाई यात्रा पर किया गया था।

परिषद ने अपने उत्तर में बताया (सितम्बर 2012) कि एयर इंडिया में जाने की बजाए निजी विक्रेताओं से टिकटें प्रदान करके इसने सरकारी धन की बचत की थी तथा हवाई टिकटों की खरीद हेतु मानक मानदण्डों का निरूपण सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इसने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन से छूट की मांग संभव नहीं है क्योंकि भा.सां.सं.प. विदेश में कई मण्डलियों तथा सदस्यों को भेजती है।

अनुशंसा

- ❖ *परिषद को हवाई यात्रा के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए।*

1.2.6.4 भा.सां.सं.प. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वृत्ति छात्रों की मॉनीटरिंग

क्षेत्रीय कार्यालय, परिषद की अनिवार्य गतिविधियों को पूरा करने हेतु, स्थानीय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संगठनों तथा राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करते

हैं। व्यय तथा कार्यों के आधार पर तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (15 में से) अर्थात् बैंगलोर, जयपुर तथा वाराणसी को विस्तृत लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चयन किया गया था।

क. पंजीकरण

विदेशी छात्रों को, आगमन के 14 दिनों के भीतर, विदेशी पंजीकरण कार्यालय (वि.पं.का.)/विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (वि.क्षे.प.का.) में पंजीकरण करना अपेक्षित है। वि.पं.का/वि.क्षे.प.का. द्वारा इन छात्रों को आवासीय परमिट जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को, जब वह अपने संबंधित देशों के लिए प्रस्थान करते हैं, पासपोर्ट तथा आवासीय परमिट को प्रस्तुत करने पर वि.प.का./वि.क्षे.पं.का. द्वारा प्रस्थान वीजा जारी किया जाता है।

परिषद ने पाया (नवम्बर 2007) कई वृत्तिछात्र अपने अध्ययन की समाप्ति के तुरंत पश्चात अपने स्वदेश के लिए प्रस्थान नहीं करते हैं जो सुरक्षा संबंधित मामले उत्पन्न कर सकते हैं। परिषद ने अपने क्षे.का. का अपने पाठ्यक्रम समाप्त कर रहे छात्रों का ध्यानपूर्वक पता लगाने तथा उनके अध्ययनों की समाप्ति के तुरंत पश्चात उनका अपने देश के लिए प्रस्थान को सुनिश्चित करने की सलाह दी। क्षेत्रीय कार्यालय पाठ्यक्रम की समाप्ति पर प्रस्थान कर रहे छात्रों के प्रस्थान वीजा की एक प्रति रखते हैं।

तीन क्षे.का. (बंगलोर, वाराणसी तथा जयपुर) में 91 विदेशी छात्रों के आवासीय परमिट तथा 34 विदेशी छात्रों के प्रस्थान वीजा के संबंध में नमूना जांच ने प्रकट किया कि 67 प्रतिशत मामलों में आवासीय परमिटों की प्रति उपलब्ध नहीं थी जबकि प्रस्थान वीजा के लिए 88 प्रतिशत मामलों में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि स्थानीय प्राधिकारी तथा भा.सां.सं.प. मुख्यालय वृत्तिछात्र के वास को सामूहिक रूप से मॉनीटर करते हैं तथा मॉनटरिंग की कमी आपसी सूचना की कमी के कारण हो सकती है।

ख. उपस्थिति तथा प्रगति रिपोर्ट

परिषद/क्षेत्रीय कार्यालयों ने विदेशी छात्रवृत्ति छात्रों को अपने निर्देशों में प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर अपने संबंधित क्षे.का. को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से उपस्थिति शीट तथा प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण पर बल दिया।

तीन क्षे.का. में 91 विदेशी छात्रों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 98 *प्रतिशत* मामलों में उपस्थिति रिपोर्ट का अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा 87 प्रतिशत मामलों में प्रगति रिपोर्ट का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

1.2.6.5 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी संगठन में आंतरिक लेखापरीक्षा महत्व वृद्वि तथा संगठन के परिचालनों को सुधारने हेतु तैयार एक स्वतंत्र, उद्देश्य आश्वासन तथा परामर्श कार्य है। भा.सां.सं.प. में आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य इसके लेखा अनुभाग द्वारा किया जा रहा था।

2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु शामिल की गई इकाईयों तथा उठाई गई आपत्तियों की स्थिति को **तालिका 7** में अंकित किया गया है।

तालिका -7

की गई आंतरिक लेखापरीक्षा, उठाई गई तथा बकाया आपत्तियों की वर्ष-वार स्थिति

वर्ष	भा.सां.के. एवं क्षे.का. की कुल सं.	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की सं.	कुल इकाईयों के प्रति शामिल इकाईयों की प्रतिशतता	उठाई गई आपत्तियों की कुल संख्या	31.3.2012 को बकाया आपत्तियों की संख्या
2006-07	20+9	7	24	41	41
2007-08	22+12	शून्य	-	-	-
2008-09	23+13	शून्य	-	-	-
2009-10	26+14	2	5	11	11
2010-11	36+15	10	20	118	118
2011-12	37+15	13	25	194	194

यह देखा जा सकता है कि 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई जबकि अन्य वर्षों में आवृतन कुल फील्ड इकाईयों के प्रति केवल पांच से 25 प्रतिशत था। 2006-07 से 2011-12 के दौरान परिषद मुख्यालय के विभिन्न स्कंधों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थीं। उपयुक्त अनुपालना के अभाव में उजागर सभी आपत्तियों बकाया थीं। यह देखा गया था कि भा.सां.सं.प. के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका नहीं थी और ना ही इसने आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार की थी।

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य अधिक प्रभावी नहीं था।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2012) कि 2012-13 के दौरान अधिक भा.सां.के. तथा क्षे.का. की लेखापरीक्षा की जाएंगी।

1.2.6.6 मंत्रालय की भूमिका

सा.वि.नि. का नियम 208 (iv) बताता है कि जहां कहीं संभव हो, आवर्ती अनुदान प्रदान करने के बजाए मंत्रालय एक कॉर्पस निधि का सृजन करें जिसके निवेश पर वापसियों सहित अपने आंतरिक रूप से सृजित संसाधन स्वायत्त संगठन को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने योग्य बनाएंगे। नियम 208 (v) के अनुसार, (कार्य आकार तथा प्राकृति) पर निर्भर प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों में स्वायत्त संगठनों की बाह्य पीयर समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 208 (vii) के अनुसार, स्वायत्त निकायों का प्रशासनिक मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो अनुपातिक निवेश आवश्यकताओं सहित कार्य के कार्यक्रम तथा उत्पादन में गुणवत्ता सुधार के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे। उत्पादन लक्ष्य, जो निष्पादन की मापनीय इकाईयों में प्रदान किए गए हैं, को इन संगठनों को प्रदान बजट सहायता का आधार बनना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने कॉर्पस निधि का सृजन नहीं किया था तथा 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान कोई पीयर समीक्षा नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने परिषद के निष्पादन पर आवश्यक निरीक्षण करने हेतु परिषद के साथ समझौता ज्ञापन भी नहीं किया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2012) कि किसी भी कॉर्पस निधि का सृजन करने हेतु कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसने आगे बताया कि न तो कोई पीयर समीक्षा की गई थी और न ही भा.सां.सं.प. के साथ कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था।

निष्कर्ष

भा.सां.सं.प. को भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथ आपसी मेल-मिलाप को स्थापित तथा सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, परिषद के प्राधिकारियों, जिसमें सामान्य सभा, शासी निकाय तथा वित्त समिति शामिल है, ने नीति तथा कार्यक्रम तैयार किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो इन प्राधिकारियों ने नियमित बारंबारता के अनुसार बैठक की थी और न ही कोई वार्षिक कार्य योजना तैयार की थी।

परिषद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करती है। तथापि, परिषद भा.सां.सं.प. छात्रवृत्ति योजना को पर्याप्त प्रचार प्रदान करने में विफल रही जिसका परिणाम स्लॉटों के कम उपयोग तथा देशों के विषम आवेदन में हुआ। इसने उन देशों, जिनके साथ कोई सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम करार विद्यमान नहीं था, को

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 25 *प्रतिशत* स्लॉटों को आवंटन किया। परिषद ने वास्तविक आधार पर भा.सां.के. के बजट अनुमान तैयार न करके तथा अपने भा.सां.के. को बजट के आधार तथा समय पर निधियाँ प्रेषित न करके वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु एक नियंत्रण क्रियाविधि के रूप बजट का उपयोग नहीं किया था।

परिषद ने 3 भा.सां.के. प्रारम्भ किये तथा वह विदेश मंत्रालय की स्वीकृति के बिना 8 अन्य भा.सां.के. प्रारम्भ करने की प्रक्रिया में थी। परिषद वित्त मंत्रालय से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न देशों में निदेशक, भा.सां.के. पद का संचालन कर रही थी। निदेशक, भा.सां.के. के पदों के लिए बाह्य व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों के अभाव में परिषद यादृच्छिक ढ़ंग से नियुक्तियां कर रही है तथा चयनित व्यक्तियों को एक ही पद हेतु अलग वेतन प्रदान कर रही है।

परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों हेतु कलाकरों के चयन तथा पात्रता के लिए कोई प्रतिमान तैयार नहीं किए तथा मामले दर मामले के आधार पर यह कार्य किए है। परिषद ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना 70 देशों में 34 प्रतिनिधिमण्डल भेजे जिसमें ₹ 8.15 करोड़ का व्यय शामिल है। परिषद ने सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना निजी फर्मों को भुगतान द्वारा सेवाओं के प्रापण पर पर्याप्त व्यय किया।

अनुबंध-I

(पैरा 1.2.3.1 के संदर्भ में)

भा.सां.सं.प. का बजट प्राक्कलन, प्रस्तावित संशोधित प्राक्कलन, आबंटित निधि एवं वास्तविक व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	प्रस्तावित संशोधित प्राक्कलन	विदेश मंत्रालय द्वारा आबंटित निधियाँ	वास्तविक व्यय	(+)अतिरिक्त (-) बचत आवंटित निधियों के संदर्भ में
2006-07	6050.00	9176.00	6250.00	6747.52	(+)497.52
2007-08	7000.00	8163.85	7670.73	7742.19	(+) 71.46
2008-09	8982.00	10807.00	8645.87	8827.98	(+) 182.11
2009-10	13343.00	14954.00	13900.00	13009.12	(-) 890.88
2010-11	16641.00	17641.00	15000.00	14837.00	(-) 163.00
2011-12	21956.00	19702.00	14000.00	17639.01	(+) 3639.01

अनुबंध-II

(पैरा 1.2.3.2 के संदर्भ में)

विदेश में भा.सां.के. से संबंधित बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	(+)अतिरिक्त (-) बचत	अतिरिक्तता का प्रतिशत
2008-09	22.85	25.32	(+) 2.47	10.80
2009-10	29.10	39.87	(+) 10.77	37.01
2010-11	45.39	42.40	(-) 2.99	-
2011-12	29.00	46.10	(+) 17.10	58.96

विदेश में भा.सां.के. से संबंधित प्रेषण एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रेषण	वास्तविक व्यय	कमियां	कमियों का प्रतिशत
2008-09	19.37	25.32	5.95	30.71
2009-10	38.14	39.87	1.73	4.53
2010-11	41.16	42.40	1.24	3.01
2011-12	35.16	46.10	10.94	31.11

अनुबंध-III

(पैरा 1.2.4.2 के संदर्भ में)

2006-2012 के दौरान विदेशों के भा.सां.के. में निदेशक के पद पर आसीन बाहरी व्यक्ति

क्र.सं.	भा.सां.के. का नाम	निदेशक का नाम	अवधि*	कुल प्रदत्त वेतन (₹ लाख में)
1.	मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र, कायरो, मिस्र	डा.ए.बशीर अहमद	16.1.2006 से 26.1.2009	47.26
2.	इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट लुई, मॉरीशस	सुश्री अमिता शॉ	29.11.2010 से	28.52
3.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जॉर्जटाउन, गुयाना	सुश्री मालती सहाय	26.6.2008 से 24.6.2010	61.92
4.	लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान	डॉ.नासिर रजा खान	19.4.2009 से 25.11.2010	26.95
5.	लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान	श्री राजेश मेहता	जून 2011 से	13.21
6.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहनसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	श्री विनोद कुमार संदलेश	21.1.2011 से	24.70
7.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलंबो, श्रीलंका	श्री म.रामचंद्रन	24.10.2010 से	24.61
8.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुआ, फिजी	प्रो. महावीर सिंह	27.1.2006 से 28.1.2009	18.81
9.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, सुआ, फिजी	डा. कमल किशोर मिश्र	6.3.2009 से	50.13
10.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काठमांडू, नेपाल	डा. गीति सेन	अक्तूबर 2009 से सितम्बर 2011	42.47
11.	भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, बैंकाक, थाइलैण्ड	सुश्री रेणुका नारायनन	अगस्त 2009 से	53.36
12.	जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इण्डोनेशिया	श्री अरूप कुमार दत्ता	17.05.2004 से 05.10.2007	50.91
13.	जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इण्डोनेशिया	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह	21.01.2008 से 18.07.2011.	135.00
14.	जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इण्डोनेशिया	श्री जहुर हैदर जैदी	19.8.2011 से	11.99
15.	टैगोर केन्द्र, बर्लिन	प्रो.ह.स. शिव प्रकाश	जून 2011 से	21.22
16.	महात्मागांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो	श्री ज.प.आर्य	5.3.2012 से	--
कुल				**611.06**

*निदेशकों हेतु जो पद पर बने रहें, 31.03.2012 को वित्तीय निहितार्थों के परिकलन हेतु लिया गया है।

अनुबंध-IV

(पैरा 1.2.6.1 के संदर्भ में)

व्यय का विभाजन

क्र.सं.	प्रायोजित दौरे का विवरण	प्राक्कलनों एवं अनुमोदनों से संबंधित टिप्पणी
1	सुश्री शैली शर्मा के नेतृत्व में 4-23 सितम्बर 2010 तक इटली और तुर्की में नमस्ते फ्रांस उत्सव में भाग लेने के लिए 14 सदस्यीय भांगड़ा समूह।	दो अलग प्राक्कलन(i) ₹6.69 लाख (5 सदस्यों के हवाई किराया, मानदेय, बीमा, दै.भ. आदि के लिए) तथा (ii) ₹11.82 लाख (9 सदस्यों के हवाई किराया, मानदेय, बीमा,म.भ. आदि के लिए) एक ही दिन (30 अगस्त 2010) म.नि.,भा.सां.सं.प. के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। ₹18.51 लाख के प्राक्कलन को, 15 लाख की सीमा से कम रखने के लिए विभाजित कर दिया गया था।
2	श्री रतन थैयम (उत्तर प्रियदर्शी) के नेतृत्व में 4-17 अप्रैल 2010 तक चीन में भारत उत्सव में 38 सदस्यीय थियेटर समूह।	दो अलग प्राक्कलन (i) ₹8.48 लाख (मानदेय, बीमा, दै.भ. आदि के लिए) (ii) ₹14.73 लाख (हवाई किराया के लिए) एक ही दिन (31 मार्च 2010) म.नि., भा.सां.सं.प. के समक्ष रखे गये थे। ₹23.21 लाख के प्राक्कलन को, ₹15 लाख की सीमा से कम रखने के लिए विभाजित किया गया था।
3	सुश्री मधुमिता मिश्रा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय घुँघरू नृत्य अकादमी, शंघाई एक्सपो 2010, सिंगापुर, इण्डोनेशिया तथा दक्षिण कोरिया के लिए 9-31 अक्तूबर 2010 के लिए।	म.नि.,भा.सां.सं.प. के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलन, दौरान कार्यक्रम पर अपेक्षित व्यय के रूप में ₹19.85 लाख दर्शाता है। हालांकि, यह भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।
4	आनन्द शंकर जयंत के नेतृत्व में 29 जुलाई से 16 अगस्त 2009 तक रूस, ग्रीस और सीरिया के लिए 12 सदस्यीय कुचुपुडी समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया।
5	श्री शाहधर आचार्य के नेतृत्व में 22 सितम्बर से 7 अक्तूबर 2009 तक वियतनाम, जापान और रूस के लिए सेराइकेला छाऊ का 12 सदस्यों का समूह।	दौरा कार्यक्रम पर व्यय ₹15 लाख से अधिक (₹13.75 लाख यात्रा पर + ₹2.58 लाख मानदेय पर आदि) था। हालांकि भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। म.नि.,भा.सां.सं.प. को अनुमोदन हेतु प्राक्कलन भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।
6	डा. ल. सुब्रमण्यम का छः सदस्यीय समूह, रूस, पोलैण्ड, स्पेन, पुर्तगाल और इटली को 30 मई से 20 जून 2009 तक के लिए।	दो अलग प्राक्कलन (i) ₹14.52 लाख (मानदेय) बीमा, मं.भ. अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, आदि के लिए) और (ii) ₹1.40 लाख (घरेलू हवाई किराये के लिए) म.नि., भा.सां.सं.प. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये थे। प्राक्कलन को विभाजित कर ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
7	सुश्री तनुश्री शंकर के नेतृत्व में 18 सितम्बर से 2 अक्तूबर 2009 तक रूस, नीदरलैण्ड और अजेरबैजान के लिए 12 सदस्यीय आधुनिक नृत्य समूह।	म.नि., भा.सां.सं.प. को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत व्यय प्राक्कलन (₹14.90 लाख) में समूह के सदस्यों को देय दै.भ. शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, दौरे पर वास्तविक व्यय ₹15 लाख से अधिक (ई.बी.टी.,दै.भ., अतिरिक्त प्रदर्शन) जैसे प्रभारों के प्रति जो प्राक्कलन में शामिल नहीं थे। हालांकि भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
8	स.मारियानेला फिलिगिना मैसकरेन्स दियास के नेतृत्व में 4-14 नवम्बर 2010 तक अर्जेन्टीना के लिए गोएन्चिम नोकत्रम समूह।	हवाई यात्रा पर प्राक्कलित व्यय (₹13.86 लाख) को प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया था और म.नि.भा.सां.सं.प. को केवल ₹3.80 लाख का प्रस्ताव ही अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। कुल प्राक्कलित व्यय ₹17.66 लाख था, तथापि, भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन इस मामले में प्राप्त नहीं किया गया था।
9	कलाक्षेत्र संस्थान से भारत उत्सव, चीन के लिए 22-25 अक्तूबर 2010 तक के लिए 30 सदस्यीय भारतनाट्यम नृत्य समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
10	गंगा बाई कामद के नेतृत्व में 25 मई से 8 जून 2010 तक त्रिनिदाद और टोबेगो, सुरीनाम,	₹12.13 लाख (हवाई किराया, मानदेय, बीमा, दै.भ. आदि के प्रति) और ₹4.32 लाख (प्रदर्शन के दौरान किये जाने वाले व्यय के प्रति) के दो अलग

क्र.सं.	प्रायोजित दौरे का विवरण	प्राक्कलनों एवं अनुमोदनों से संबंधित टिप्पणी
	ग्रेनाडा आदि के लिए 11 सदस्यीय राजस्थानी समूह गंगा बाई तेरातेली।	प्राक्कलन परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। ₹16.45 लाख के प्राक्कलन को विभाजित कर ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
11	श्री गाजी खान के नेतृत्व में 13 अक्तूबर से 3 नवम्बर 2010 तक न्यूजीलैण्ड के लिए 12 सदस्यीय राजस्थानी लोक नृत्य समूह।	समूह के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय, समूह को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते (₹3.37 लाख) को प्राक्कलन मे शामिल नहीं किया गया था। प्राक्कलन को ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
12	सुश्री राजश्री नगरकर के नेतृत्व में 11-25 नवम्बर 2010 तक जापान, इण्डोनेशिया और रूस के लिए 12 सदस्यीय लावनी समूह।	हवाई यात्रा पर प्राक्कलित व्यय (₹17.77 लाख) को म.नि.भा.सां.सं.प. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। कुल प्राक्कलित व्यय ₹21.82 लाख था। तथापि, भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन इस मामले में प्राप्त नहीं किया गया था।
13	श्री जोरावर सिंह जादव, के नेतृत्व में 29 अक्तूबर से 14 नवम्बर 2010 तक त्रिनिदाद और टोबैगो, सुरीनाम एवं सं.रा.अ. के 12 सदस्यीय भावी, बहुरूपी तथा एक्रोबेटिक गुजराती समूह।	₹16.88 लाख का प्राक्कलित व्यय भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसका अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
14	सरोज वैद्यनाथन के नेतृत्व में 19 मार्च से 4 अप्रैल 2011 तक जर्मनी एवं अल्जीयर्स के लिए 10 सदस्यीय गणेश नाट्यालय भारतनाट्यम समूह।	म.नि.,भा.सां.सं.प. को वित्तीय अनुमोदन हेतु ₹14.99 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया था। यह देखा गया था के उदृत प्रदर्शनों की दर सही नहीं (₹50000 के स्थान पर ₹40000 उल्लिखित था) थी। अंतिम व्यय ₹17.69 लाख ₹15 लाख की सीमा से ऊपर था। तथापि, भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
15	कार्तिकेश्वर राणा के नेतृत्व में 14-21 मार्च 2011 तक त्रिनिदाद एवं टोबेगो के लिए 10 सदस्यीय मयूर-भंज छाउ समूह।	दो अलग प्राक्कलन (i) ₹2.81 लाख (मानदेय, बीमा, दै.भ. आदि के प्रति) तथा (ii) ₹13.52 लाख (हवाई किराया के प्रति), परिषद के द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। ₹16.33 लाख के प्राक्कलन को विभाजित कर ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
16	श्री अमरदीप सिंह जडेजा के नेतृत्व में 8-24 अक्तूबर 2009 तक न्यूजीलैण्ड के लिए सौराष्ट्र लोक कला केन्द्र का 12 सदस्यीय गुजराती लोक नृत्य समूह।	हवाई किराया पर अपेक्षित व्यय (₹10.67 लाख) को म.नि., सां.सं.प. के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। कुल प्राक्कलित व्यय ₹16.93 लाख था, तथापि भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन नहीं लिया गया था।
17	2-6 मई 2009 तक ग्याना, सुरीनाम, वेनेजुएला तथा त्रिनिदाद एवं टोबेगो के लिए 9 सदस्यीय संयुक्त संगीत एवं नृत्य समूह, जिसमें कुमुद दीवान एवं महुआ शंकर सम्मिलित थे।	संयुक्त दौरा कार्यक्रम दो भागों में था (i) महुआ शंकर के नेतृत्व वाले कथक नृत्य समूह पर ₹12.84 लाख का व्यय तथा (ii) कुमुद दीवान के नेतृत्व वाले शास्त्रीय समूह पर ₹10.56 लाख का व्यय। ₹23.40 लाख के प्राक्कलन को विभाजित कर ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
18.	2011 में कनाडा में भारत का वर्ष उत्सव में 12 से 29 अगस्त 2011 तक के लिए 14 सदस्यीय कदमब समूह।	हवाई किराये पर प्राक्कलित कुल व्यय (₹11.45 लाख) एवं दै.भ. चिकित्सा, मानदेय, होटल में रहने, समूह के अन्य परिवहन) पर प्राक्कलित व्यय (₹10.55 लाख) प्रस्तुत किये गये (10 अगस्त 2011) तथा (8 अगस्त 2011) और म.नि.,भा,सां.सं.प. द्वारा 16 अगस्त 2011 एवं 17 अगस्त 2011 को, भा.सं.सं.प. के अध्यक्ष के अनुमोदन से बचने के लिए अनुमोदित किया गया।
19.	25 सदस्यीय इला अरूण समूह के 16 से 30 अक्तूबर 2011 तक कनाडा दौरे के लिए।	रूपांकन, बनावट एवं किराये की लागत पर प्राक्कलित व्यय (₹12.50 लाख) तथा संकल्पना, नृत्यकला, पूर्वाभ्यास आदि के लिए अन्य प्राक्कलन (₹12.50 लाख) परिषद के म.नि. को अनुमोदन हेतु एक ही दिन (24.8.2011) अलग-अलग प्रस्तुत किये गये थे। इसके अतिरिक्त, पोशाक, रंगमंचीय सामग्री तथा आयोजन स्थलों के किराये के प्रति अनुमोदन (₹25.00 लाख) हेतु प्राक्कलनों के 12.9.2011 को प्रस्तुत किया गया था। अतिरिक्त सामान, प्रर्शन शुल्क, दै.भ., चिकित्सा बीमा, संयोजन प्रभार,

क्र.सं.	प्रायोजित दौरे का विवरण	प्राक्कलनों एवं अनुमोदनों से संबंधित टिप्पणी
		विविध पर प्राक्कलित व्यय (₹11.50 लाख) तथा लगभग ₹16.62 लाख के यात्रा लागतों हेतु व्यय 05.10.2011 को प्रस्तुत किया गया था। प्राक्कलनों को विभाजित कर दिया गया था और भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
20.	सुश्री रंजना गौहर के नेतृत्व में 27 जून से 3 जुलाई 2011 तक के लिए दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, सिंगापुर और फिलीपिंस के लिए भारत उत्सव समूह।	14 सदस्यीय ओडिसा नृत्य तथा 7 सदस्यीय (14-सदस्यीय समूह के मध्य) ओडिसी नृत्य समूह दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, सिंगापुर, तथा फिलीपींस के लिए ₹8.12 लाख और ₹8.05 लाख के प्राक्कलित व्यय उसी दिन अर्थात (23.6.2011) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये और म.नि., भा.सां.सं.प. द्वारा उसी दिन अनुमोदित किये गये। भा.सा.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति लेने से बचने के लिए व्यय को विभाजित किया गया था।
21	सुश्री आनंद शंकर जयंत के नेतृत्व में 17 मई से 6 जून 2011 तक ब्राजील में भारत उत्सव।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
22.	सुश्री शुभ्रा भारद्वाज का 16 मार्च से 2 अप्रैल 2011 तक सं.रा.अ., कनाडा एवं त्रिनिदाद तथा टोबेगो के लिए बॉलीवुड समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
23.	गुरू जयराम राव का 17 अगस्त से 2 सितम्बर 2011 तक 2011 में कनाडा में भारत उत्सव वर्ष का कनाडा दौरा।	8 अगस्त 2011 को हवाई किराया पर प्राक्कलित व्यय (₹14.73 लाख) और 10 अगस्त 2011 को (दै.भ. सामान, मानदेय पर) प्राक्कलित व्यय (₹9.31 लाख की राशि का) म.नि.,भा.सां.सं.प. के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। ₹24.04 लाख के प्राक्कलन को विभाजित किया गया और ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।

क्र.सं.	प्रायोजित दौरे का विवरण	प्राक्कलनों एवं अनुमोदनों से संबंधित टिप्पणी
24.	सुश्री मीनाक्षी राय के नेतृत्व में 12 मई से 7 जून 2011 तक कनाडा-2011 में भारत उत्सव में भागीदारी हेतु चिन्ह समूह का दौरा।	केवल 18 सदस्यों के लिए सेक्टर दिल्ली ओटावा-एडमोन्टोन-दिल्ली के लिए हवाई किराया पर प्राक्कलित व्यय (₹13.32 लाख) म.नि., भा.सां.सं.प. द्वारा अनुमोदित (29.5.2011) किया गया था। अन्य प्राक्कलन, जिसमें उसी सेक्टर के 18 सदस्यों के हवाई किराया के प्रति अनुमोदित उद्धरण तथा दरों के अनुसार उल्लिखित ₹12.27 लाख राशि के दै.भ. मानदेय, ई.बीटी.चिकित्सा/सामान, संचयन प्रभार तथा विविध व्यय शामिल थे, को म.नि., भा.सा.सं.प. द्वारा अनुमोदित किया गया(12-5-2011) था। व्यय को विभाजित कर भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹15 लाख की सीमा से नीचे रखा गया था।
25.	सुश्री उषा वेंकटेश्वरन के नेतृत्व में 6 से 14 मार्च 2011 तक सं.रा.अं. तथा कनाडा के लिए 15 सदस्यीय शाकुतलम समूह।	कुल प्राक्कलित व्यय (₹21.77 लाख) भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।
26.	सुश्री तनुश्री शंकर के नेतृत्व में सं.रा.अ. में 7 से 18 मार्च 2011 तक के लिए 16 सदस्यीय समूह।	हवाई किराया, दै.भ. (₹14.28 लाख) तथा आवास, म.भ. मानदेय, विविध व्ययों (₹14.27 लाख) पर प्राक्कलित व्यय के प्रस्ताव म.नि., भा.सां.सं.प. के समक्ष अनुमोदन हेतु एक ही दिन (22 फरवरी 2011) प्रस्तुत किये गये थे। प्राक्कलित व्यय को विभाजित कर भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति होने से बचने के लिए ₹15 लाख की सीमा से नीचे रखा गया था।
27.	डॉ.एल. सुब्रहमण्यम के नेतृत्व में 01.6.2011 से 10.6.2011 तक कनाडा में भारत उत्सव में 9 सदस्यीय वायलन समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
28.	श्री परमजीत सिंह के नेतृत्व में 22 दिसम्बर 2011 से 6 जनवरी 2012 तक कुआलालंपुर और फिजी के लिए 12 सदस्यीय पंजाबी पॉप बैंड।	दिल्ली-सुवा-दिल्ली (₹10.80 लाख) और मुंबई-सुआ-मुंबई (₹3.85 लाख) के हवाई किराये पर कुल प्राक्कलित व्यय अनुमोदन हेतु प्रस्तुत (29.11.2011) किया गया था जबकि प्रदर्शन शुल्क दै.भ., स्थानीय परिवहन, फिजी में विविध व्यय का प्राक्कलित व्यय(₹13.80 लाख) को अलग से 01.12.2011 को यात्रा के उसी क्षेत्र के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। मलेशिया एवं फिजी के (22.12.11 से 06.1.12) के लिए प्राक्कलित व्यय को विभाजित कर भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति लेने से बचने के लिए ₹15 लाख की सीमा से कम रखा गया था।
29.	भारत-जापान कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ, 4 से 9 फरवरी 2012।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन (₹39.27 लाख के) प्राक्कलित व्यय के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।
30.	भारत उत्सव में भागीदारी हेतु सांस्कृतिक समूह का कोलंबिया दौरा, श्री कल्पेश दलाल 8 से 26 नवंबर 2011 ।	एक्वाडोर (8 से 20 नवंबर 2011) और कोलंबिया (20 से 26 नवंबर 2011) में क्रमशः ₹12.15 लाख और ₹10.69 लाख के कुल प्राक्कलित व्यय को विभाजित कर ₹15 लाख से कम रखा गया था। भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
31.	असम ज्योति सांस्कृतिक गोष्ठीः शिव प्रसाद दास संत विंसेंट तथा पैरामारिबो 30 मई 2011 से 8 जून 2011।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष के समक्ष 27 मई 2011 को प्रस्तुत कुल प्राक्कलित व्यय (₹23.87 लाख) को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था इसके अतिरिक्त, छः इकॉनामी क्लास टिकटों के लिए हवाई किराया (₹9.11 लाख) उसी दिन (27.5.2011) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था और आठ वापसी टिकटों (₹12.15 लाख) के प्रति एक अन्य प्रस्ताव 25.5.2011 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राक्कलनों को ₹15 लाख से कम रखा गया था।
32.	सुश्री सोहैला कपूर के नेतृत्व में 31 अक्तूबर से 20 नवम्बर 2011 तक कनाडा, यू.के. तथा सं.अ.अ. में 19 सदस्यीय माहिम जंक्शन थियेटर समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राक्कलित व्यय (₹35.73 लाख) के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

क्र.सं.	प्रायोजित दौरे का विवरण	प्राक्कलनों एवं अनुमोदनों से संबंधित टिप्पणी
33.	श्री संदीप शर्मा के नेतृत्व में 28 मई से 18 जून 2011 तक त्रिनिदाद और टोबेगो, ग्रेनाडा, बार्बादोस एवं सुरीनाम के लिए 16 सदस्यीय नक्ष विरसा पंजाब दा भांगड़ा एवं गिद्दा समूह।	भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन लिया गया था।
34.	सुरेश के.नायर के नेतृत्व में 10 अक्तूबर से 7 नवम्बर 2011 तक बेरूत, फिनलैण्ड,तुर्कमिनिस्तान तथा रूस के लिए 14 सदस्यीय मौट्रिक्स बॉलीवुड समूह।	चिकित्सा, यात्रा बीमा एवं ई.बी.टी. (₹14.44 लाख) 8 प्रदर्शकों के प्रदर्शन शुल्क, दै.भ. (₹12.48 लाख) 7 प्रदर्शकों के लिए प्रदर्शन शुल्क बेरूत, फिनलैण्ड, तुर्कमिनिस्तान तथा रूस में रहने के लिए दै.भ., स्थानीय परिवहन विविध (₹13.77 लाख) को शामिल करते हुए हवाई किराये पर प्राक्कलित व्यय म.नि.भा.सां.सं.प. के अनुमोदनार्थ उसी दिन (30.9.2011) अलग-अलग प्रस्तुत किये गये थे और ₹15 लाख से कम रखे गये थे। भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
35.	13-19 अक्तूबर 2011 तक त्रिनिदाद एवं टोबेगो तथा 20-23 अक्तूबर 2011 तक सुरीनाम में 08 सदस्यीय कव्वाली समूह।	चिकित्सा यात्रा बीमा एवं ई.बी.टी.(₹12.07 लाख) मानदेय, दै.भ. तथा विविध व्ययों (₹6.64 लाख) को शामिल करते हुए हवाई किराये पर प्राक्कलित व्यय को उसी दिन (30.9.2011) अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था और उसे ₹15 लाख से कम रखते हुए, भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति नहीं ली गयी थी।
36.	6-17 अक्तूबर 2011 तक न्यूजीलैण्ड में 4 सदस्यीय कठपुतली समूह तथा 11 सदस्यीय मणिपुरी नृत्य समूह।	हवाई किराया, चिकित्सा बीमा, ई.बी.टी. (₹12.46 लाख) तथा दै.भ. प्रदर्शन शुल्क (₹7.35 लाख) पर प्राक्कलित व्यय को म.नि., भा.सां.सं.प. के समक्ष उसी दिन (30.9.2011) अलग-अलग अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था और ₹15 लाख से कम रखा गया था, इस प्रकार भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष की स्वीकृति नहीं ली गयी थी।
37.	इण्डोनेशिया के लिए सांस्कृतिक समूह-श्री संजय शर्मा के नेतृत्व में 2-26 नवम्बर 2011 तक 24-सदस्यीय ब्रज लोक कला मंच समूह।	24 सदस्यीय समूह के इण्डोनेशिया और फिजी दौरे के लिए हवाई किराये पर प्राक्कलित व्यय (₹38.00 लाख) के लिए भा.सां.सं.प. के अध्यक्ष से स्वीकृति नहीं ली गयी थी।
38.	भारतीय छोटे उत्सव में भाग लेने के लिए 23-06-2011 से 03-07-2011 तक श्रीमती उमा शर्मा के नेतृत्व में 14 सदस्य का कथक समूह।	हवाई किराए (₹11.96 लाख) एवं प्रदर्शन शुल्क, स्थानीय परिवहन, चिकित्सा, यात्रा बीमा एवं इ.बी.टी., विविध (₹9.53 लाख) के अनुमानित व्यय म.नि.,भा.सां.सं.प. के समक्ष अनुमोदन हेतु पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए थे तथा ₹15 लाख से कम रखे गए थे, जिससे कि भा.सां.सं.प. अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
39.	13-23 अगस्त 2011 से फिजी में श्रीमती मीरा दास के नेतृत्व में 12 सदस्य का ओडिसी समूह	12 सदस्य समूह के अनुमानित व्यय को 6 सदस्य समूह हेतु प्रत्येक के लिए ₹14.51 लाख एवं ₹12.01 लाख की राशि को विभाजित कर दिया गया एवं भा.सां.सं.प., म.नि. के समक्ष क्रमशः 08.08.2011 एवं 09.08.2011 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था जिससे कि व्यय को ₹15 लाख से कम रखा गया तथा भा.सां.सं.प. अध्यक्ष का अनुमोदन टाला गया।
40.	मैसर्ज टीमवर्क्स प्रोडक्शन को 3-24 सितम्बर 2011 से साझा इतिहास के पांचवें संस्करण दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अनुभव के संबंध में यात्रा अनुदान।	कार्योत्तर संस्वीकृति हेतु ₹12.44 लाख की राशि तथा बजट अनुमानों हेतु मानदेय एवं दै.भ. के प्रति ₹8.66 लाख की राशि उसी दिन (22.9.2011) को प्राप्त कर ली गई थी तथा ₹15 लाख से कम रखी गई थी, जिससे कि भा.सां.सं.प. अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
41.	12 अक्तूबर से 7 नवम्बर 2011 तक दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम एवं थाइलैंड में सुश्री पीनाज मसानी के नेतृत्व में 13 सदस्य बॉलीवुड समूह।	₹11.43 लाख की राशि का बजट अनुमान अनुमोदन हेतु 4 अक्तूबर 2011 को प्रस्तुत किया गया था और इसके अतिरिक्त, इन्डोनेशिया (₹8.79 लाख), वियतनाम (₹9.70 लाख) थाइलैंड (₹9.31 लाख) तथा दक्षिण कोरिया (₹13.84 लाख) के दौरे पर अन्य अनुमानित व्यय को 10 अक्तूबर को अनुमोदित कर दिया गया था। अनुमानों को ₹15 लाख से कम रखा था। जिससे कि भा.सां.सं.प., अध्यक्ष का अनुमोदन टाला गया था।

अनुबंध-V
सेवाओं का प्रापण
(पैराग्राफ 1.2.6.2 के संदर्भ में)

क्र.स.	समारोह का नाम	कंपनी/संगठन का नाम	किया गया व्यय (₹ लाख में)	प्रदत्त सेवाएं
1.	भारत अफ्रीका भागीदारी सम्मेलन	मैसर्ज मार्डन स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	37.92	सम्पूर्ण ऑडियो सिस्टम, लाइट, स्टेज, नेपथ्यशाला, बैठक का क्षेत्र, जनरेटर सेट, शौचालय, इत्यादि ।
2.	जैसलमेर में सार्क कलाकार शिविर 15-22 जनवरी, 2007	सहर	53.16	भागीदारी हेतु कलाकार शुल्क, यात्रा, आवास एवं भोजन, स्थानीय परिवहन, कला सामग्री, आयोजन स्थल से नई दिल्ली में भा.सा.स.प. मुख्यालय तक कलाकृतियों को पहुंचाना, आदि।
3.	सार्क बैन्ड उत्सव 2007	सहर	122.00	स्टेज सजावट, बनाना,साउंड, जनरेटर, लाइटें, बैठने की व्यवस्था, कार्ड/पोस्टर, की प्रिंटिंग प्रैस एवं मीडिया कवरेज, परिवहन, फोटोग्राफी, सुरक्षा, स्वयंसेवक यात्रा, बैंड का आवास एवं भोजन आदि।
4.	भारत में चीन के उत्सव का समापन समारोह	मैसर्ज शोक्राफ्ट प्रोडक्शन	99.15	वी.वी.आई.पी. प्रवेश द्वार, टी.वी.चालक दल एन्क्लोजर, नेपथ्यशाला, वी.वी.आई.पी. के बैठने हेतु प्लेटफार्म, मास्किंग एवं एल.इ.डी. वॉल फ्रेम, चलायमान पर्दा, अतिथि सहायता डेस्क,वैलेट पार्किंग, चलायमान शौचालय, अशरिंग ड्यूटी, आदि।
5.	पोंडीचेरी में दक्षिण एशियाई कलाकार शिविर	सहर	75.00	भागीदारी के लिए कलाकार शुल्क, यात्रा, आवास एवं भोजन, स्थानीय परिवहन, कला सामग्री, आयोजन स्थल से नई दिल्ली में भा.सा.स.प. मुख्यालय तक कलाकृतियां पहुंचाना, आदि।
6.	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	मैसर्ज पारस आर्ट स्टूडियो	63.21	अग्निरोधी कपडें पर डिजिटल प्रिंटिग, वास्तुशिल्प डिजाइन, अभिन्यास, मंच सृजन, कम वोल्टेज स्पॉट लैंप, हवाई किराया, स्थानीय परिवहन, सृजनात्मक चालक दल का आवास एवं भोजन, आदि।
7.	कोवलम में दक्षिणी एशियाई कलाकार शिविर, (अग्रिम भुगतान)	सहर	50.00	भागीदारी के लिए कलाकार शुल्क, यात्रा, आवास एवं भोजन, स्थानीय परिवहन, कला सामग्री, आयोजन स्थल से नई दिल्ली में भा.सां.सं.प. मुख्यालय तक कलाकृतियों को पहुंचाना, आदि।
8.	दक्षिणी एशियाई बैन्ड उत्सव दिसम्बर 2009	सहर	110.00	स्टेज सजावट,बनाना, ध्वनी, जनरेटर, लाइटें, कुर्सियां एवं अन्य बैठने की व्यवस्थाएं, सैट डिजाइन एवं माहौल, कार्ड/ पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग, कलाकार की लागत (पारिश्रमिक, यात्रा, समाचार-स्थानीय वाहन आदि), समाचार-पत्र में विज्ञापन, प्रैस एवं मीडिया कवरेज, सुरक्षा, स्वयं सेवक आदि।

9.	भारत में रूसी उत्सव	मैसर्ज मार्डन स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	55.00	चरणों के साथ बहुस्तरीय स्टेज, नेपथ्यशाला, बैठक क्षेत्र, पुलिंदा बनाना, जनरेटर सेट, सामान्य प्रकाशन, चलायमान शौचालय आदि।
10.	दक्षिण एशियाई बैन्ड उत्सव-दिसम्बर 2010	सहर	110.00	स्टेज सजावट, बनाना, ध्वनि, जनरेटर, लाइटें, कुर्सियां एवं अन्य बैठनें की व्यवस्थाएं, सेट डिजाइन एवं माहौल, कार्ड/पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग, कलाकार की लागत (पारिश्रामिक, यात्रा, रहना, स्थानीय वाहन आदि) समाचार-पत्र में विज्ञापन, प्रैस एवं मीडिया कवरेज, सुरक्षा, स्वयंसेवक आदि।
11.	सार्क साहित्यिक उत्सव	सार्क लेखक एवं साहित्य संस्थान	70.00	प्रतिनिधियों के लिए हवाई टिकट/ रेल किराया, स्थानीय आतिथ्य (होटल में रहने की व्यवस्था, वाहन, भोजन आदि।
12.	सार्क संगोष्ठी व लोकगीत उत्सव 2007	सार्क लेखक एवं साहित्य संस्थान	49.58	सार्क संगोष्ठी एवं लोकगीत समारोह 2007 का आयोजन
13.	भा.फै.डि.प./सार्क फैशन शो 2007	भा.फै.डि.प.	30.00	आयोजन स्थल, स्टेज, लाइट एवं ध्वनि, ऑडियो, सेट डिजाइन, कोरियोग्राफी, मेकअप कलाकार, मॉडल, नेपथ्य समन्वयक, आवास, भोजन एवं पेय, ड्रेसर्स, दरजी, आमंत्रण एवं कोरियर, यात्रा एवं जमीनी परिवहन, फोटोग्राफी, वीडियों आदि।
14.	सार्क वस्त्र प्रदर्शनी 2007	हथकरघा शीर्ष सोसायटी निगम संघ	20.00	सार्क वस्त्र प्रदशनी का आयोजन।
15.	दक्षिण एशियाई बैंड उत्सव-फरवरी 2009	सहर	107.24	स्टेज सजावट, बनाना, ध्वनि, जनरेटर, लाइटें, कुर्सियां एवं अन्य बैठनें की व्यवस्थाएं, सेट डिजाइन एवं माहौल, कार्ड/पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग, कलाकार की लागत (पारिश्रामिक, यात्रा, रहना, स्थानीय वाहन आदि) समाचार-पत्र में विज्ञापन, प्रैस एवं मीडिया कवरेज, सुरक्षा, स्वयंसेवक आदि।
16.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव-नवंबर 2011	मैसर्ज मॉडर्न स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	43.46	स्टेज, नेपथ्यशाला, बैठने की व्यवस्था, जनरेटर सेट, स्टेज लाइट, ध्वनि, वीडियो, पुलिंदा एवं माहौल प्रकाशन उपकरण आदि।
17.	दक्षिण एशियाई बैंड उत्सव-दिसम्बर 2011	सहर	28.05	सेट डिजाइन एवं माहौल, प्रचार, प्रैस एवं मीडिया कवरेज, स्थानीय परिवहन, बडी स्क्रीन के साथ वीडियोग्रॉफी एवं प्रक्षेपण, भा.सा.स.प. वेबसाइट पर सीधा प्रसारण, सुरक्षा, स्वयंसेवक आदि।
18.	दूसरा जैज उत्सव-मार्च 2012	सहर	30.00	सेट डिजाइन एवं माहौल, कार्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग, स्थानीय परिवहन, कलाकारों के उपकरण, प्रैस एवं मीडिया कवरेज, सीधा प्रसारण, सुरक्षा स्वयंसेवक आदि।
	योग		**1153.77**	

अनुबंध-VI
(पैराग्राफ 1.1.2.6.2 के संदर्भ में)
विभिन्न बिलों में कमियाँ

क्र.स.	उत्सव का नाम	कमी	परिषद का उत्तर
1.	भारत - अफ्रीका भागीदारी सम्मेलन (अप्रैल 2008)	(क) उत्सव के लिए पूर्वाभ्यास 5 अप्रैल, 2008 को हुआ था और वास्तविक उत्सव 6 एवं 7 अप्रैल, 2008 को पुराना किला में हुआ था। तथापि, यह नोट किया गया कि परिषद ने चार दिनों के लिए भुगतान किया था। चूंकि समारोह हेतु सेवाएं तीन दिनों के लिए प्रदान की गई थी, चौथे दिन के भुगतान (₹6.64 लाख) को परिषद द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। (ख) कम्पनी ने 29 चलायमान शौचालयों के लिए अपने बिल में दो बार ₹1.50 लाख प्रभार किया था।भुगतान के समय परिषद द्वारा यह तथ्य अनदेखा रहा।	परिषद ने उत्तर दिया (जनवरी 2012) कि उसने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया है तथा प्रासंगिक जी. एफ. आर. प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, वह अभी कार्यप्रणाली को सुधारने की प्रक्रिया में है।
2.	जैसलमेर में सार्क कलाकार शिविर (जनवरी, 2007)	(क) सेवा कर के प्रति ₹5.96 लाख की राशि लगाई गई थी, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बिना यह देखे किया गया था कि विक्रेता ने न तो इसका बिल दिया था और न ही परिषद को सेवा कर संख्या प्रदान की थी। (ख) हवाई यात्राओं के लिए ₹2.79 लाख की राशि के "ए.बी.सी. ट्रेवल्स" यात्रा अभिकरण के बिल सहर ने प्रस्तुत किए। तथापि, यह देखा गया कि यात्रा टिकटों की प्रतियाँ बिलों के साथ संलग्न नहीं की गई थी तथा यात्रा एजेंट के हस्तलिखित बिल के आधार पर ही भुगतान कर दिया गया था। पांच ऐसे मामले भी पाए गए थे जहाँ बिलों पर यात्रियों के नामों का उल्लेख नहीं था। बुनियादी विवरणों की अनुपस्थिति में, यात्रा टिकटों के क्रय के प्रति किया गया भुगतान शंकास्पद था।	परिषद द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
3.	सार्क बैन्ड उत्सव- (दिसम्बर, 2007)	(क) डिजाइन, निमार्ण, संकल्पना एवं ₹9.93 लाख की राशि बिना किसी बिल संख्या की थी। (ख) मैसर्ज दिल्ली टैंट एवं डेकोरेटर्स द्वारा दिए गए बिल में सेवा कर एवं डी-वैट दोनों ही लिए गए थे। चूकि बिल में दिए गए मद किराए पर लिए गए थे, न कि बैचे गए थे, ₹12,500/- की राशि का डी-वैट लिया जाना उचित नहीं था। (ग) ₹2.25 लाख की राशि सहर द्वारा कलाकारों, सहयोगियों एवं जनता हेतु निशानियों पर खर्च हुई दर्शाई गई हैं। तथापि, उनके क्रय एवं वितरण, अभिलेखों में नहीं पाए गए थे। (घ) ₹7.99 लाख एवं ₹7.00 लाख की राशि क्रमशः मैसर्ज दिल्ली एवं डेकोरेटर्स और मैसर्ज ऑडियो डिजाइन को स्टेज स्थापना एवं साउंड सिस्टम हेतु भुगतान के लिए दर्शाई गई जबकि कोई मद वार दर नहीं थी। जबकि, दावे की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में स्थापित नही हो पाई थी। (ड़) सेवा कर के प्रति ₹13.50 लाख की राशि लगाई गई थी, जिसका भुगतान परिषद द्वारा यह देखे बिना ही कर दिया गया था कि विक्रेता ने परिषद को न तो अपना बिल	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उसने पहले से ही प्रक्रियाओं में सुधार करना शुरू कर दिया था।

क्र.स.	उत्सव का नाम	कमी	परिषद का उत्तर
		दिया था तथा न ही सेवा कर संख्या दी थी।	
4.	भारत में चीनी उत्सव का समापन समारोह (दिसम्बर, 2010)	कंपनी के 21.12.2010 दिनांकित इनवॉइस में मदवार दरों का उल्लेख नहीं था।	परिषद ने बताया (जनवरी 2012) कि शुरू किए गए कार्य संलग्न है। तथापि, परिषद ने शुरू किए गए कार्यों की मद वार दरे प्रदान नहीं की थीं।
5.	पुडुचेरी दक्षिण एशियाई कलाकार शिविर (मार्च, 2010)	(क) ₹6.50 लाख के समन्वय शुल्क के संबंध में अनुचित बिल जमा किया गया था, तब भी भुगतान कर दिया गया था। (ख) सेवा कर के प्रति ₹7.04 लाख की राशि लगाई गई थी, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बिना यह देखे कर दिया गया था कि विक्रेता ने दावा किए गए सेवा कर के समर्थन में कोई बिल/इनवाइस/चालान प्रदान नहीं किया था।	परिषद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
6.	न्यूयार्क में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस (अक्तूबर, 2007)	₹31.28 लाख (वाउचर सं. 155 दिनांकित 17/01/2008) हेतु कंपनी बिल संख्या पी.ए.एस./इ.एक्स.एस.वी./2007/10/057 दिनांकित 17.10.2007 में मद वार दरों का उल्लेख नहीं किया गया था। (ख) कंपनी द्वारा ₹3.44 लाख की राशि का सेवा कर लगाया गया था तथा परिषद द्वारा इसका भुगतान किया गया था। तथापि, कंपनी का बिल सेवा कर पंजीकरण संख्या का वहन नहीं करता।	परिषद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
7.	दक्षिण एशियाई बैन्ड उत्सव (दिसम्बर, 2009)	(क) मैसर्ज ऑडियो डिजाइन को साउंड एवं लाइट उपकरण प्रदान करने के लिए ₹8.91 लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया था लेकिन कोई मद वार दरें नहीं थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा दावे की प्रमाणिकता स्थापित नहीं हो पाई थी। (ख) पर्यवेक्षण, डिजाइन, उत्पादन खर्चों आदि हेतु मैसर्ज सुमंत जयकृष्णन को ₹2.48 लाख का भुगतान दर्शाया गया था जबकि सहर ने भी अलग से उसी के लिए ₹7.50 लाख का दावा किया था। (ग) बैंड उत्सव हेतु बनाए गए 100 पैनलों हेतु तथा उन्हें विभिन्न मेट्रों स्टेशनों , दिल्ली हॉट, दिल्ली के न.दि.न.पा., दि.न.नि. क्षेत्रों में लगाने हेतु मैसर्ज पुंज आर्ट स्टूडियो को ₹4.26 लाख (₹1.92 लाख + ₹2.34 लाख) का भुगतान दर्शाया गया था। तथापि, मैट्रो, दिल्ली हॉट, न.दि.न.पा. एवं दि.न.नि प्राधिकारियों की रसीदें मैसर्ज पूंज आर्ट स्टूडियों के बिलों के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे। यह समझा नहीं जा सका है कि किस प्रकार परिषद ने इस आवश्यकता की पूर्ति से अपने आप को संतुष्ट किया। (घ) समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु मैसर्ज एक्सपोजिशन कंस्लटेंटस (प्रा) लिमिटेड को ₹5.35 लाख की राशि का भुगतान दर्शाया गया था। तथापि, कथित कंपनी द्वारा रसीद केवल ₹4.00 लाख हेतु दी गई थी। इसके अलावा, विज्ञापनों की प्रतियाँ बिल के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी।	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उनका अनुसरण करते हुए उन्होनें प्रक्रियाओं को सुधारना शुरू कर दिया था।

क्र.स.	उत्सव का नाम	कमी	परिषद का उत्तर
		(ड.) मैसर्ज मल्टीमीडिया पेशेवर केन्द्र को ₹46,800/- की राशि देय दर्शाई गई थी। तथापि कथित कम्पनी द्वारा दी गई रसीद ₹44,550/- की थी। (च) ₹6,250 तथा ₹10,000/- की राशि का भुगतान जनरेटरों तथा विघुत अनुमति पर व्यय की ओर दर्शाया गया था। तथापि रसीदों के अलावा अभिलेख में कोई बिल नहीं पाए गए थे। (छ) ₹10.90 लाख की राशि सेवा कर के प्रति लगाई गई थी, जिसका भुगतान परिषद द्वारा यह देखे बिना कर दिया गया था कि विक्रेता ने दावा किए गए सेवा कर के समर्थन में काई बिल/ इनवाइस/ चालान नहीं दिया था।	
8.	भारत में रूसी उत्सव (फरवरी 2008)	(क) ठेकेदार के बिल में प्रदत्त मदों/सेवाओं के विवरण तथा प्रत्येक मद की दर, आदि का उल्लेख नहीं था। (ख) परिषद के वित्त एवं लेखा स्कंध ने मामले में प्रक्रियात्मक और वित्तीय अनियमितताएं पाई तथा ए.एस(एफ.ए), विदेश मंत्रालय, जो कि परिषद का भी वित्तीय सलाहकार है की सहमति लेने की सलाह दी। तथापि, परिषद ने मामले को ए.एस. (एफ.ए) को मामला बताए बिना ठेकेदार को भुगतान किए।	परिषद ने बताया (जनवरी, 2012) कि उसने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया है तथा प्रासंगिक जी.एफ.आर. प्रावधानों का अनुसरण करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया में सुधार शुरू कर दिए गए है।
9.	सार्क साक्षरता उत्सव 2010	(क) सा.ले.सा.स. के द्वारा जमा किए गए ₹22.93 लाख की राशि के, यात्रा एजेंट के 12 बिलों में उड़ान एवं वर्ग जिसमें की यात्रा की तिथियों के साथ वास्तव में यात्राएं की गई थी, के विवरण नहीं थे। यात्रा टिकटों की राशि को सत्यापित करने के लिए हवाई टिकटों की प्रतियाँ संलग्न नहीं की गई थी। (ख) हवाई टिकट एवं रेल किराया प्रतिपूर्ति के प्रति ₹2.50 लाख की राशि के 12 भुगतान दर्शाए गए थे, लेकिन टिकटों की कोई प्रतिया संलग्न नहीं की गई थी। (ग)विभिन्न होटलों की व्यवस्थाएं करने के संदर्भ में ₹17.00 लाख हेतु जे एवं एम. आतिथ्य सेवाओं के बिल जमा किए गए थे। विभिन्न होटलों अर्थात फोरेस्ट ग्रीन होटल, ग्लीटर होटल, विक्रम होटल, ग्रेंड सरताज होटल, सप्तगिरी होटल के बिल ₹17.00 लाख के समर्थन में जमा नहीं किए गए थे।	परिषद ने बताया (दिसम्बर 2011) कि सा.ले.सा.स. को ₹70 लाख का सहायता अनुदान प्रदान किया गया था। परिषद का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सार्क साक्षरता समारोह के आयोजन का कार्य परिषद द्वारा सा.ले.सा.स. को सौंपा गया था।
10.	सार्क संगोष्ठी सह-लोकगीत उत्सव (दिसम्बर, 2007)	परिषद ने सा.ले.सा.स. को ₹49.58 लाख का अंतिम भुगतान किया था। तथापि, अभिकरण ने व्यय के समर्थन में बिल के साथ सहायक दस्तावेजों को संलग्न नहीं किया था।	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उसके अनुसरण में उन्होनें पहले से ही प्रक्रियाओं में सुधार शुरू कर दिए थे।
11.	सार्क फैशन शो (दिसम्बर, 2007)	भा.फै.डि.प. द्वारा ₹74,160/- की राशि सेवा कर के प्रति लगाई गई थी जिसका भुगतान परिषद द्वारा यह देखे बिना ही कर दिया गया था कि भा.फै. डि.प. ने अपनी सेवा कर संख्या नहीं दी थी।	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उसके अनुसरण में उन्होनें पहले से ही प्रक्रियाओं में सुधार शुरू कर दिए थे।

क्र.स.	उत्सव का नाम	कमी	परिषद का उत्तर
12.	सार्क वस्त्र प्रदर्शनी (दिसम्बर 2007)	परिषद ने हथकरघा शीर्ष सोसायटी निगम संघ (ह.शी.सो.नि.सं.) को बिना बिल प्राप्ति के ही ₹33.55 लाख की शेष राशि दे दी थी। ह.शी.सो.नि.सं. ने ₹33.55 लाख वापिस यह बताते हुए कर दिए कि उपरोक्त प्रदर्शनी से संबंधित उसके काई बकाया देयताएं/लेखा नहीं थे।	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उसके अनुसरण में उन्होनें पहले से ही प्रक्रियाओं में सुधार शुरू कर दिए थे।
13.	दक्षिण एशियाई बैन्ड उत्सव (फरवरी, 2009)	(क) बैन्ड उत्सव के लिए निर्मित 100 पैनलों हेतु तथा उन्हें विभिन्न मैट्रो स्टेशनों, न.दि.न.पा., दिल्ली के दि.न.नि.क्षेत्रों पर लगाने के लिए मैसर्स पुंज आर्ट स्टूडियों को भुगतान के लिए ₹3.93 लाख (₹1.60 लाख + ₹2.33 लाख) दर्शाया गया था। तथापि, मैट्रो, न.दि.न.पा. एवं दि.न.नि. प्राधिकारियों की रसीदें मैसर्स पुंज आर्ट स्टूडियो के बिलों के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार परिषद ने यह भुगतान करने से पूर्व ₹3.93 लाख के दावे की प्रमाणिकता/सत्यता से अपने आप को किस प्रकार संतुष्ट किया। (ख) भा.सा.स.प. ने सहर द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल के प्रति ₹75,247/- का भुगतान किया, जोकि मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड के नाम से उठाया गया था। यह राशि विशाल शेखर समूह के होटल " द ललित " में रहने की व्यवस्था पर खर्च हुआ था। (ग) समारोह के शुरू होने से एक सप्ताह पहले, होटल मौर्या के रेस्टोरेंट " द पवेलियन" में दिनांक 15.02.2009 को शराब एवं रात्रि भोज के लिए ₹1288.88 का व्यय किया गया था।	परिषद ने (जनवरी 2012) लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट किया तथा बताया कि उसके अनुसरण में उन्होनें पहले से ही प्रक्रियाओं में सुधार शुरू कर दिए थे।
14.	दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सव (नवम्बर, 2011)	कम्पनी के 16.12.2011 दिनांक के बीजकों में मदवार दरों का उल्लेख नहीं था। इन महत्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति में, अधूरे बिल पर ही भुगतान किए गए थे।	परिषद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।
15.	दक्षिण एशियाई बैन्ड उत्सव (दिसम्बर, 2011)	(क) मैसर्स सुमंत जयकृष्णन को पर्यवेक्षण, डिजाइन, उत्पादन खर्चों आदि हेतु ₹2.76 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि सहर ने उसी के लिए ₹9.38 लाख का अलग से दावा किया था। (ख) बैन्ड उत्सव के लिए निर्मित पैनलो हेतु तथा उन्हें विभिन्न मैट्रो स्टेशनों, दिल्ली हाट (आई.एन.ए. एवं पीतमपुरा), न.दि.न.पा., दिल्ली के दि.न.नि. क्षेत्रों पर लगाने के लिए मैसर्स पुंज आर्ट स्टूडियों को ₹3.74 लाख (₹1.98 लाख + ₹1.76 लाख) का भुगतान दर्शाया गया था। तथापि, मैट्रो, न.दि.न.पा. एवं दि.न.नि. प्राधिकारियों की रसीदें, बिलों के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे।	
16.	दूसरा जैज़ उत्सव (मार्च, 2012)	(क) मैसर्स सुमंत जयकृष्णन को पर्यवेक्षण, डिजाइन, उत्पादन खर्चों, आदि हेतु ₹2.92 लाख का भुगतान दर्शाया गया था जबकि उसी के लिए सहर ने अलग से ₹8.50 लाख का दावा किया था। (ख) जैज़ उत्सव के लिए निर्मित पैनलों एवं उन्हें न.दि.न.पा. के विभिन्न स्थानों एवं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उन्हें लगवाने के लिए ₹2.58 लाख का भुगतान	परिषद से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

क्र.स.	उत्सव का नाम	कमी	परिषद का उत्तर
		किया गया था। तथापि, न.दि.न.पा. की रसीद, बिल के साथ संलग्न नहीं पाए गए थे। (ग) किसी श्री विक्रांत जैन को परिचालन प्रभार हेतु ₹90,000/- की राशि का भुगतान किया गया था लेकिन कोई मद-वार दर उपलब्ध नहीं थी।	

अनुबंध -VII
(पैराग्राफ 1.2.6.2 के संदर्भ में)
टी.डी.एस. की कटौती न होना

क्र.स.	उत्सव एवं कंपनी का नाम	भुगतान की गई राशि
1.	जैसलमेर में सार्क कलाकार शिविर-सहर	सहर ने ₹4.29 लाख के समन्वय शुल्क का दावा किया, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बिना टी.डी.एस. की कटौती के किया गया था।
2.	सार्क बैंड उत्सव, 2007-सहर	सहर ने ₹9.93 लाख के डिजाइन, निर्माण, अवधारणा एवं कार्यान्वयन शुल्क का दावा किया, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बिना टी.डी.एस. की कटौती के किया गया था।
3.	पुडुचेरी में दक्षिण एशियाई कलाकार शिविर-सहर	सहर ने ₹6.50 लाख के समन्वय शुल्क का दावा किया, जिसका भुगतान परिषद द्वारा बिना टी.डी.एस. की कटौती के किया गया था।
4.	न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस- मैसर्स पारस आर्ट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड	प्रदर्शनी के आयोजन के संबंध में मैसर्स पारस आर्ट स्टूडियो को ₹31.28 लाख की राशि का भुगतान किया गया था परन्तु कोई टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी।
5.	दक्षिण एशिया बैंड उत्सव, फरवरी 2009 - सहर	सहर ने ₹7.50 लाख के समन्वय शुल्क का दावा किया जिसका भुगतान परिषद द्वारा टी.डी.एस. की कटौती किए बिना ही कर दिया गया था।
6.	दक्षिण एशिया बैंड उत्सव, दिसम्बर 2009- सहर	सहर ने ₹7.50 लाख के समन्वय शुल्क का दावा किया जिसका भुगतान परिषद द्वारा टी.डी.एस. की कटौती किए बिना ही कर दिया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य-पद्धति

अध्याय II : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति

विशेषताएं

- विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार 15 अन्तर-विषयी केन्द्रों के खोलने की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र सात अन्तर-विषयी केन्द्र खोले गये।

(पैराग्राफ 2.2.2.1)

- शिक्षण - स्टाफ की अत्यन्त कमी थी एवं शिक्षक-छात्र अनुपात निर्धारित मानक से अधिक था। विज्ञान संकाय में असफलता दर 50 प्रतिशत से अधिक ।

(पैराग्राफ 2.2.2.2, 2.2.2.3 और 2.2.2.4)

- विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि ₹ 35.07 करोड़ में से मात्र ₹ 14.09 करोड़ का ही उपयोग विश्वविद्यालय कर सका था।

(पैराग्राफ 2.2.6)

- विश्वविद्यालय छात्रावासों में, अनधिकृत कब्जे के साथ-साथ छात्रावास आवंटन की प्रतीक्षा सूची थी।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

- विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय ₹ 36.67 करोड़ के सापेक्ष ₹ 22.80 करोड़ की धनराशि का उपयोग कर सका। पुस्तकालय के पास उसके संसाधनों के संरक्षण हेतु कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था एवं मूल्यांकन पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

(पैराग्राफ 2.2.7.2)

- अनुपयोगी निधियां, वर्ष 2006-07 में ₹ 64.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-2012 में ₹ 97.15 करोड़ हो गयी थीं।

(पैराग्राफ 2.2.8.1)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि खाते पर ब्याज का भुगतान करने हेतु अनुरक्षण अनुदान की राशि का विचलन किया।

(पैराग्राफ 2.2.8.2)

- विरासत भवन की मरम्मत हेतु आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 2.2.9.2)

अनुशंसाएं:

- *विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकें आवश्यक अन्तराल के अनुसार आयोजित की जानी चाहिये, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके।*
- *विश्वविद्यालय को समयबद्ध ढंग से शेष केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।*
- *विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।*
- *प.पा. एवं स.षि.स. द्वारा बी.ए. में नामांकन घटने के कारणों का निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।*
- *विश्वविद्यालय आई.क्यू.ए.सी. के क्रिया कलापों को उचित ढंग से व्यवस्थित करे एवं मान्यता हेतु आवेदन करे।*
- *विश्वविद्यालय अनधिकृत कब्जों की मॉनीटरिंग करें, और इसके बाद रिक्त कमरों को प्रतीक्षा सूची के अनुसार आवंटित करे।*
- *विश्वविद्यालय अपने पुस्तकालय संसाधनों के संरक्षण हेतु उपयुक्त क्रियाविधि अपनाये।*
- *सा.वि.नि. 194 के अनुसार पुस्तकों का आवधिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाये।*
- *विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुसरण करे।*

2.1.1 प्रस्तावना

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितम्बर 1887 को स्थापित हुआ था एवं यह कलकत्ता, मुम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद भारत का चौथा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अंतर्गत यह राज्य विश्वविद्यालय के रूप में पंजीकृत था। भारत सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत 14 जुलाई 2005 से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। अधिनियम की धारा-6 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य हैं:

- ❖ अध्ययन की ऐसी शाखाओं में अनुदेशात्मक व अनुसंधान सुविधाओं द्वारा उन्नत ज्ञान को प्रसारित करना जैसा यह उपयुक्त समझे;
- ❖ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मौलिक व प्रयोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये प्रावधान करना;
- ❖ अध्ययन-अध्यापन प्रकिया, अंतर-अनुशासनात्मक व्यवसायिक अध्ययन एवं अनुसंधान में नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना, लिंग असमानता व आंकिक विभेद को दूर करना एवं सामाजिक उन्नति राष्ट्रीय विकास एवं मानव कल्याण हेतु ज्ञान का अनुप्रयोग करना एवं
- ❖ देश के विकास हेतु मानव संसाधन को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय के 11 अंगीभूत महाविद्यालय, 32 विभागों सहित चार संकाय (विज्ञान, कला, वाणिज्य व विधि), तीन संस्थान एवं एक अंगीभूत संस्थान है (मार्च 2012)।

अधिनियम में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों का प्रावधान है:

(1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे एवं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह एवं परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति (कु.) विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी हैं। कुलाधिपति अर्थात भारत के राष्ट्रपति द्वारा उप-कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(3) उप-कुलपति, कुलपति की सहायता करते हैं एवं कुलपति की अनुशंसा से कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(4) संकायों में संकाय अध्यक्ष, अध्यापन व अनुसंधान के मानकों के संचालन व अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होता है एवं कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(5) कुल सचिव परिषद, कार्यकारी परिषद एवं शैक्षिक परिषद के पदेन सचिव होते हैं एवं चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

(6) वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होते हैं एवं विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करते हैं, एवं इसे अपनी वित्तीय नीतियों के अनुरूप सलाह देते हैं तथा चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

अधिनियम, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारियों का भी प्रावधान करता है:

i. परिषद;

ii. कार्यकारी परिषद;

iii. शैक्षणिक परिषद;

iv. संकायों का बोर्ड; तथा

v. वित्त समिति।

2.1.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सम्पादित की गयी थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि आच्छादित थी, जिसमें प्राधिकारियों की भूमिका, शैक्षणिक गतिविधियां, अनुसंधान, सहायक सेवायें, वित्तीय प्रबंधन एवं संरचनात्मक विकास से संबंधित विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्मिलित थी।

2.1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह अभिनिश्चित करने के लिये की गयी थी कि क्या:

- अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों की भूमिका पर्याप्त व प्रभावकारी थी;
- शैक्षिक गतिविधियां दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से आयोजित एवं क्रियान्वित की गई थी;
- मानकों के अनुसार अनुसंधान एवं सलाहकारिता परियोजनाओं के कार्य को पूरा किया गया था तथा अभिप्रेत परिणाम प्राप्त किये थे;
- छात्र सहायता सेवायें जैसे छात्रावास व पुस्तकालय पर्याप्त थे;
- वित्तीय संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रबंध किया गया था एवं
- विश्वविद्यालय ने अपने संरचना से संबंधित निर्माण कार्यों को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित किया था।

2.1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड जहां से प्राप्त हुए:

- इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 एवं विश्वविद्यालय अध्यादेश;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) एवं अन्य अभिकरणों के अनुदानों की नियम एवं शर्तें;
- वि.अ.आ. एंव मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) के दिशानिर्देश/ आदेश; एवं
- कोर्ट, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति इत्यादि की बैठकों के कार्यवृत्त

2.1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2011 में कुलपति के साथ परिचयात्मक बैठक के साथ आरम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानकों, कार्यक्षेत्र एवं प्रणाली पर चर्चा की गयी। जून 2011 से फरवरी 2012 के दौरान विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जाँच की गयी थी। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा का मसौदा 3 अप्रैल 2012 को जारी किया गया था। विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तरों (मई 2012) को प्रतिवेदन में

उपयुक्त रूप में समाहित किया गया है। लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा 18 जनवरी, 2013 को कुलपति के साथ निर्गम बैठक में की गई। मंत्रालय को 11 दिसम्बर 2012 को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित थे (मार्च 2013)।

2.2 लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

2.2.1 प्राधिकारियों की भूमिका

अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्राधिकारियों जैसे परिषद, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद एवं वित्त समिति स्थापित की गयी थी। इनके क्रिया-कलाप, सामर्थ्य, प्राधिकारियों की बैठकों की संख्या, संकल्प एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही सम्बंधी अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए।

2.2.1.1 परिषद

परिषद का मुख्य कार्य समय-समय पर विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना, उनके सुधार एवं विकास के उपायों हेतु सुझाव देना है।

अधिनियम न्यायालय द्वारा वार्षिक बैठकें निर्धारित करता है, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष में विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के साथ आय-व्यय विवरण, लेखापरीक्षा तुलनपत्र एवं अगले वर्ष के लिए वित्तीय अनुमानों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायेगें (अनुसूची के भाग 8(3))।

यह पाया गया कि 2006-07 से 2011-12 की अवधि में 21 जून 2008 को मात्र एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें 31 सदस्यों में से कोरम 25 के प्रति 14 सदस्य उपस्थित थे।

इस प्रकार समय-समय पर विश्वविद्यालय की वृहत नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने एवं विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के उपायों हेतु सुझाव देने की परिषद की क्रियाविधि अप्रभावी पायी गयी।

विश्वविद्यालय द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये (मई 2012) बताया गया कि परिषद की बैठकों एवं उसके कोरम को भविष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।

2.2.1.2 कार्यकारी परिषद (का.प.)

कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय है एवं इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय के राजस्व व सम्पत्ति का प्रबंध एवं देख-रेख करना है तथा इसके प्रशासनिक मामलों को संचालित करना है।

लेखापरीक्षा संविक्षा में आगे पाया गया:

2.2.1.3 वाहनों का क्रय

अविकासात्मक व्यय को रोकने के दृष्टिकोण से 'मितव्ययी उपायों' के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने निर्देशित किया था (जुलाई 2006) कि किसी निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन के लिए भी नये वाहनों का क्रय नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार के आदेश पूर्व में भी जारी किये गये थे (नवम्बर 2005)।

चार स्टाफ कार के क्रय प्रस्ताव हेतु वित्त समिति ने अपनी पहली बैठक में, जो 15 सितम्बर 2006 को आयोजित की गई, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय व वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वाहन क्रय की संस्तुति प्रदान की। इन आदेशों के अनुसार निष्प्रयोज्य घोषित की जगह नई कार के क्रय हेतु भी वि.अ.आ. की स्वीकृति आवश्यक थी। वित्त समिति द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि वाहनों को भाड़े पर लिये जाने पर विचार किया जाए एवं कुलपति हेतु केवल एक कार क्रय करने की संस्तुति की गयी थी।

जबकि का.प. के बैठक (अक्तूबर 2006) में यह पारित किया गया कि विश्वविद्यालय में चार स्टाफ कार की आवश्कयता थी, जिनको निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर क्रय किया जाए। तदनुसार मार्च 2007 में ₹ 18.24 लाख की धनराशि से चार स्टाफ कार क्रय की गयी थीं।

वि.स. ने अपनी बैठक दिनांक 4 अगस्त 2007 में यह पुनः कहा कि मा.सं.वि.मं. से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

इस प्रकार कार्यकारी परिषद ने सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुये, बिना औचित्य के वि.स. की संस्तुतियों से अलग कार्य किया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (मई 2012) कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के कार्यों को जारी रखने, प्रबंध करने, वित्त का विनियमन करने एवं संरचना की व्यवस्था करने के लिए सक्षम थी। अतः मा.सं.वि.मं. की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। उत्तर उचित नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय के निर्देश, स्वायत्त संस्थाओं पर भी लागू थे।

2.2.1.4 वित्त समिति (वि.स.)

वित्त समिति वार्षिक लेखाओं व वित्तीय अनुमानों पर सोच विचार हेतु उत्तरदायी है। यह वर्ष के लिए कुल आवर्ती व अनावर्ती व्यय हेतु सीमाओं की संस्तुति भी करती है। अधिनियम की धारा 13(5) में यह प्रावधान है कि वि.स. प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगी।

यह देखा गया कि नियत से कम संख्या में बैठकें हुईं थी - 2006 व 2007 में प्रतिवर्ष एक, 2008 में दो, 2009 में एक आपातकालीन बैठक एवं 2010 व 2011 में प्रत्येक वर्ष दो। मात्र 2012 में तीन बैठकें जैसा कि निर्धारित थी, की गयी थीं।

विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया (मई 2012) कि वर्ष 2012 से सुधारात्मक उपायों को अपनाया गया है।

अनुशंसा

- ❖ *प्रभावकारी ढंग से कार्य करने हेतु विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकें अपेक्षित समयान्तराल में आयोजित की जानी चाहिए।*

2.2.2 शैक्षिक क्रियाकलाप

2.2.2.1 केन्द्रों का परिचय

XXVIII वें अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय में अन्तर-विषयी अध्ययन संस्थान के 15 केन्द्र[1] होंगे (परिशिष्ट-I)।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आठ केन्द्र उदाहारणार्थ - जैव चिकित्सा चुम्बकीय प्रतिध्वनि केन्द्र, संस्कृति एवं संचार केन्द्र, पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र, बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र, विकासशील देशों के लिए मोबाइल संचार केन्द्र,

---

[1] केन्द्र से तात्पर्य विश्वविद्यालय की एक इकाई अथवा विश्वविद्यालय संस्थान जो शिक्षा, परामर्श तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करता है।

सूक्ष्म विज्ञान एवं सूक्ष्म तकनीकी केन्द्र एवं विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन केन्द्र नहीं खोले गये थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि शेष केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को समयबद्ध ढंग से शेष केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए।*

2.2.2.2 शैक्षिक कार्मिकों की कमी

एक शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक मानक को बनाये रखने के लिए योग्य एवं अनुभवी संकाय की उपलब्धता आवश्यक है। स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति 31 मार्च 2012 को तालिका-1 में दर्शायी गई है:

तालिका-1

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्ति का प्रतिशत)
प्राध्यापक	79	12	67 (85)
रीडर	189	69	120 (63)
व्याख्याता	553	234	319 (58)
कुल	**821**	**315**	**506 (62)**

यह देखा गया कि:

(क) शैक्षिक स्टाफ की कमी 58 से 85 *प्रतिशत* के मध्य थी।

(ख) वि.अ.आ. द्वारा X प्लान के अंतर्गत शैक्षिक स्टाफ में 69 स्वीकृत पदों (मई 2006) में मात्र 29 स्टाफ नियुक्त किए गए, इसी प्रकार ओ.बी.सी. योजना के अंतर्गत शैक्षिक स्टाफ के स्वीकृत 243 पदों में (जुलाई 2008) से मात्र एक की नियुक्ति की गई (मार्च 2012)।

(ग) दो विभाग[2], दो केन्द्र[3] तथा एक संस्थान[4] बिना किसी संकाय के चल रहे थे, इसका पता रिक्त पदों की सूची दिनांक 01.07.2011 से चला।

इस प्रकार स्वीकृत पदों की उपलब्धता होते हुए भी शैक्षिक स्टाफ की भारी कमी के साथ विश्वविद्यालय चल रहा था।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि आरक्षण रोस्टर के प्रयोग के ढंग में वि.अ.आ. की मार्गदर्शिका एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विरोधाभास है, कि विश्वविद्यालय एक इकाई है, या विभाग एक इकाई है। अन्ततः विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. की मार्गनिर्देशिका का अनुकरण करते हुए रिक्त पदों के भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया। यह भी बताया गया कि कुछ पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं पाये गये।

2.2.2.3 शिक्षक-छात्र अनुपात

वि.अ.आ. द्वारा संस्तुत शिक्षक-छात्र अनुपात निम्न है:

तालिका 2

कार्यक्रम	पी.जी. का अनुपात	वि.अ.आ. का अनुपात
विज्ञान	1:10	1:25
मानविकी/सामाजिक विज्ञान	1:15	1:30
मीडिया व मास कम्यूनिकेशन	1:10	1:15

यद्यपि पूर्णतः शिक्षक-छात्र अनुपात समीक्षा अवधि के दौरान (2006-12) 1:43 से 1:72 के मध्य रहा (परिशिष्ट-2) जो संस्तुति मानक से अधिक था।

2.2.2.4 छात्रों की सफलता दर

कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के प्रथम वर्ष के छात्रों की 2007 से 2012 के मध्य सफलता दर का विश्लेषण किया गया **(परिशिष्ट-3)।**

---

[2] दृश्य कला, गृह विज्ञान

[3] जैव सूचना विज्ञान, फिल्म एवं थियेटर

[4] प्रयोगात्मक खनिज विज्ञान एवं शिला विज्ञान का राष्ट्रीय केन्द्र

यह पता चला कि अलग हुए/विफल छात्रों का *प्रतिशत* 11 से 66 के मध्य था। यह देखा गया कि असफलता दर विज्ञान पाठ्यक्रम में अधिक थी (51 से 66 *प्रतिशत*), इसके अतिरिक्त कला व विज्ञान दोनों वर्गों में असफलता दर बढ़ती दिखाई दी।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि विज्ञान संकाय के कुछ छात्र प्रौद्योगिकी/ चिकित्सा संस्थानों में चले गये तथा कुछ छात्र सभी प्रश्नपत्रों में नहीं सम्मिलित हुए। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हुए उसकी असफलता का *प्रतिशत* 21 से 42 तक बढ़ा है। आगे कला पाठ्यक्रम में असफलता दर के बारे में कोई उत्तर नहीं था।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाये जाने चाहिये, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।*

2.2.2.5 पूर्व अनुमति के बिना प्रारम्भ किये गये पाठ्यक्रम

भूगोल विभाग में शहर एवं ग्रामीण नियोजन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2003-04 में प्रारम्भ किया गया, जिसके लिए भारतीय नगर योजना संस्थान (भा.न.यो.सं.) की अनुमति की आवश्यकता थी। विश्वविद्यालय 2009-10 तक लगातार छात्रों को पंजीकृत कर रहा था। इसने पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए मई 2010 में आवेदन किया जिससे भा.न.यो.सं. सहमत नहीं हुआ (अगस्त 2010), क्योंकि भा.न.यो.सं. द्वारा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्राथमिक पूर्वापेक्षा इन्जीनियरिंग में स्नातक (सिविल) या वास्तुकला में स्नातक, आयोजना में स्नातक या अर्थशास्त्र/समाजशास्त्र/भूगोल में स्नातकोत्तर थी। पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष की अवधि भी आवश्यक थी। इसके विपरीत उक्त पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित अर्हता, कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए मात्र एक वर्ष की थी।

इस प्रकार मान्यता न मिलने के कारण पाठ्यक्रम को 2010-11 में बंद कर दिया गया।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि इस पाठ्यक्रम के लिए मान्यता हेतु आवश्यक जानकारी उन्हें नहीं थी तथा विश्वास दिलाया कि नये पाठ्यक्रम केवल उचित मान्यता के बाद ही खोले जायेगें।

2.2.2.6 शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज

शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज (शै.स्टा.कॉ.) की स्थापना 1987 में सेवारत शिक्षकों के लिए कार्यक्रमों के प्रारम्भन तथा पुनश्चर्या हेतु जिसमें प्रत्येक शिक्षक तीन से पांच वर्ष में एक बार सम्मिलित हो सके, की गई थी। प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में ही शै.स्टा.कॉ. को एक वार्षिक कैलेन्डर, जिसमें वर्ष के दौरान संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अन्तरिम समय-सारिणी तैयार करनी थी, तथा उस पर वि.अ.आ. की स्वीकृति प्राप्त करनी थी। विगत पांच वर्षों में शै.स्टा.कॉ. द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नवत है:

तालिका -3

वर्ष	निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वि.अ.आ. से स्वीकृत)	आयोजित पाठ्यक्रम की संख्या	आयोजित पाठ्यक्रमों में कमी (निर्धारित का *प्रतिशत*)
2006-07	17	14	3 (18)
2007-08	18	13	5 (28)
2008-09	19	14	5 (26)
2009-10	18	15	3 (17)
2010-11	22	16	6 (27)
2011-12	22	15	7 (32)
योग	**116**	**87**	**29 (25)**

यह पाया गया कि शै.स्टा.कॉ. द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या में लगातार गिरावट बनी रही जो 17 से 32 *प्रतिशत* तक थी।

विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता, विभागों की पुनश्चर्या के संचालन में असमर्थता, छात्रावास की सुविधा न होने तथा देर से प्राप्त वि.अ.आ. की स्वीकृति को दोषी माना।

तथ्य यह थे, कि शै.स्टा.कॉ. स्वयं पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा था एवं निरंतर कमी हो रही थी।

2.2.2.7 पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सतत शिक्षा संस्थान (प.पा. तथा स.शि.सं.)

प.पा. तथा स.शि.सं. की स्थापना 1978 में छात्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अवसरों के विकल्प के रूप में की गई थी। वर्ष 2006-07 से 2011-12 के मध्य प.पा. तथा स.शि.शं. द्वारा बी.ए. तथा बी.कॉम में पंजीकरण संतोषजनक था किन्तु बी.ए. पाठ्यक्रम में कमी निम्नवत प्रदर्शित हुई:

तालिका-4

पाठ्यक्रम का नाम		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बी.ए.	उ.न.	2905	1920	1723	1286	997
बी.कॉम	उ.न.	1855	2430	3475	3617	2612

इस मामले में कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था।

अनुशंसा

- ❖ प.पा. तथा स.शि.सं. को बी.ए. में पंजीकरण में कमी के कारणों का मूल्यांकन कर आवश्यक कर्रवाई करनी चाहिए।

2.2.3 गुणात्मक आश्वासन

2.2.3.1आन्तरिक गुणात्मक आश्वासन प्रकोष्ठ

वि.अ.आ. मार्गदर्शिका में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान (उ.शि.सं.) की एक उचित संरचना तथा प्रक्रिया से युक्त आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होगी जिसमें हितधारियों के विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थान होगा। उद्देश्य के लिए प्रत्येक उ.शि.सं. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आ.गु.आ.प्र.) योजना मार्ग दर्शन तथा गुणवत्ता आवश्सान का अनुश्रवण तथा गुणात्मक वृद्धि गतिविधियों के लिए स्थापित करेगी। अन्य बातों के साथ आ.गु.आ.प्र. वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे विश्वविद्यालय प्रत्यायन हेतु उसे प्रस्तुत करेगी।

जाँच से पता चला कि, यद्यपि आ.गु.आ.प्र. की स्थापना 2008-09 में की गई किन्तु न तो वार्षिक गुणवत्ता निर्धारण रिपोर्ट और न ही कोई आवधिक निर्धारण रिपोर्ट तैयार की गई थी (मार्च 2012)।

इस प्रकार, गुणवत्ता आश्वासन की क्रियाविधि जैसा कि वि.अ.आ. मार्ग निर्देशिका में उल्लिखित है, नहीं पाई गई।

2.2.3.2 राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद

वि.अ.आ. द्वारा राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (रा.नि.प्र.प.) की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1994 में की गई जिसे विश्वविद्यालय के निष्पादन मूल्यांकन, निर्धारण तथा प्रत्यायन दिलाने के काम सौंपे गये।

यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यायन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (मई 2012) तथा कहा कि प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय रा.नि.प्र.प. गतिविधियों को उचित ढंग से संगठित करके प्रत्यायन के लिए आवेदन करना चाहिए।*

2.2.4 पीठ की स्थापना

विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार से मेघनाद शाहा पीठ की स्थापना, भौतिक विज्ञान की शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए तथा संस्कृत के लिए गंगा नाथ झा पीठ की स्थापना हेतु धनराशि प्रदान की गई थी। इन निधियों के अर्जित ब्याज से व्यय किया जाना था। निधियों एवं पीठ की स्थापना स्थिति (मार्च 2012) निम्नवत थीः

तालिका -5

(₹ लाख में)

पीठ का नाम	धनराशि प्राप्ति तिथि	प्राप्त धनराशि	अर्जित ब्याज (मार्च 2012 तक)	व्यय	पीठ की स्थापना
मेघनाद शाहा	दिसम्बर 1998	70.00	72.16	10.81	स्थापित नहीं
गंगा नाथ झा	मई 1999	50.00	56.97	8.00	फरवरी 2010
	योग		**129.13**	**18.81**	

इस प्रकार यद्यपि मेघनाद शाहा पीठ 1998 में स्वीकृत हुई थी लेकिन भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्षों द्वारा बार-बार अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद मार्च 2012 तक इसकी स्थापना नहीं हो सकी। ₹ 10.81 लाख की धनराशि पीठ की स्थापना किए बिना सेमिनार व्याख्यान तथा संगोष्ठी पर व्यय की गई। इसी तरह गंगा नाथ झा की स्थापना 2010 में की गई।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि पीठ की स्थापना सम्बन्धी मामलों की जाँच की जाएगी। उत्तर अंतरिम प्रकृति का था।

2.2.5 उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह

विश्वविद्यालय के अध्यादेश LXII में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष में अधिकतम एक बार दीक्षान्त समारोह डिग्री प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाएगा। वि.अ.आ. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गयी उपाधि एवं अन्य पुरस्कार, नियम 2008 में भी प्रावधान है कि:

1. उपाधि प्रदान करने की तिथि, छात्रों को उपाधि की अर्हता का अपेक्षित उम्मीदवार होने और उनके पात्र होने के 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए।
2. सुनिश्चित की गयी तिथि के 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने की तिथि को अधिसूचित करेगा ताकि अभ्यार्थी उसके लिये आवेदन कर सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2006-12 की अवधि में दीक्षान्त समारोह नहीं हुए तथा उपाधियाँ छात्रों द्वारा प्रार्थना करने पर प्रदान की गई थीं।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि छात्रों को उपधियाँ उनकी आवश्यकता पर दी गई। उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. प्रावधान के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित क्यों नहीं किए।

2.2.6 अनुसंधान परियोजनाएं

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में अनुसंधान परियोजनाएं एक महत्वपूर्ण संघटक है। अनुसंधान परियोजनाएं धनदायी अभिकरणों से, एक से पांच वर्ष तक विभिन्न अवधियों के लिए स्वीकृत की गई थीं।

विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कुल ₹ 35.07 करोड़ (प्रारम्भिक शेष ₹ 2.17 करोड़ जोड़कर) प्राप्त किए। ₹ 14.09 करोड़ को व्यय करते हुए ₹ 20.98 करोड़ का अप्रयुक्त शेष था, जैसा **तालिका-6** में दर्शाया गया है:

तालिका-6

(₹ करोड में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि	प्रयुक्त धनराशि	अन्तिम अवशेष
2008-09	2.17	3.26	2.36	3.07
2009-10	3.07	5.10	2.70	5.47
2010-11	5.47	15.24	3.46	17.25
2011-12	17.25	9.30	5.57	20.98
	योग	**32.90**	**14.09**	

इस प्रकार विश्वविद्यालय उपरोक्त अवधि के दौरान अपने अनुसंधान अनुदान का मात्र 40 *प्रतिशत* ही उपयोग कर सका।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय के पास विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के अनुश्रवण करने की कोई केन्द्रीयकृत प्रणाली नहीं थी। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक अनुसंधान की गुणवत्ता जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, पूर्ण परियोजनाएं, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अंतिम तकनीकी रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट के संबंध में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

विश्वविद्यालय द्वारा (मई 2012) टिप्पणी को संज्ञान मे लेते हुए बताया कि संकाय अध्यक्ष (अनुसंधान एवं विकास) के कार्यालय की स्थापना अनुसंधान परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए की जा चुकी है।

2.2.7 सहायक सेवाएं

2.2.7.1 छात्रावास प्रबन्धन

विश्वविद्यालय के 14 छात्रावासों में से 13 छात्रावासों[5] के उपायोग की स्थिति निम्नवत थीः

[5] 1. गंगा नाथ झा, 2. पी.सी.बेनर्जी, 3. ताराचन्द्र, 4 शताब्दी ब्वायज, 5. एस.एन.गर्ल्स, 6.पी.डी.गर्ल्स, 7. शताब्दी गर्ल्स, 8. इन्टरनेशनल हाउस, 9. अमरनाथ झा, 10. डायमंड जुबली, 11. सर सुन्दर लाल, 12 महादेवी वर्मा, 13. एस. राधा कृष्णन, (14 कल्पना चावला -सूचना नहीं दी गयी)।

तालिका-7

वर्ष	क्षमता	प्रवेशित	रिक्त	अनधिकृत	प्रतीक्षारत छात्रों की संख्या
2006-07	2078	1746	222	110	910
2007-08	2078	1839	212	27	696
2008-09	2167	1991	162	17	1138
2009-10	2180	2076	102	11	1310
2010-11	2455	2182	142	131	1321
2011-12	1783	1459	324	178	उ.न.
योग	**12741**	**11293**	**1164**	**474**	

वर्ष 2011-12 की सूचना नौ छात्रावासों की है।

संचित प्रवेश क्षमता 12741 के प्रति मात्र 11293 छात्रों को ही छात्रावास सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त 474 छात्रों का अनधिकृत कब्जा था, तथा वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पूर्ण अनधिकृत कब्जा ताराचन्द छात्रावास में देखा गया। अनधिकृत कब्जा एक नियमित लक्षण प्रतीत हुआ।

इस प्रकार अनधिकृत कब्जे तथा रिक्त कमरों के आवंटन न किए जाने से छात्र छात्रावास सुविधा के लिए प्रतीक्षा सूची में थे।

विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि रिक्तता का प्रमुख कारण अनधिकृत कब्जा है तथा स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से कमरों को खाली कराने के प्रयास किए जायेंगे।

अनुशंसा

- ❖ विश्वविद्यालय को छात्रावास में अनधिकृत कब्जों से मुक्त करके खाली कमरों को, जो प्रतीक्षा सूची में हैं, को आवंटित करने का अनुश्रवण करना चाहिए।

2.2.7.2 पुस्तकालय प्रबंधन

विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय पुस्तकालय है जिसमें 6,62,380 पुस्तकें तथा जर्नल (मार्च 2012) हैं। वर्ष 2006-12 की अवधि में पुस्तकालय के लिए अनुदान के उपयोग की स्थिति निम्नवत थीः

तालिका-8

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त	उपयोग	अवशेष
2006-07	2.5	2.5	-
2007-08	1.5	1.5	-
2008-09	7.00	4.00	3.00
2009-10	7.00	6.03	0.97
2010-11	6.29	4.25	2.04
2011-12	12.38	4.52	7.86
योग	**36.67**	**22.80**	**13.87**

(क) इस प्रकार विश्वविद्यालय, पुस्तकालय के लिए प्राप्त अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

(ख) वि.अ.आ. द्वारा (2008-09) ₹ 5.00 करोड़ का विशेष अनुदान पुस्तकालय के आधुनिकीकरण एवं इसकी सेवाओं के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसे पुस्तकालय के स्वचलन, रेडियों आवृत्ति पहचान तकनीक (रे.आ.प.त.) कम्प्यूटरीकृत सूची के निर्माण, डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना तथा उसके संग्रह विकास में प्रयुक्त किया जाना था। विश्वविद्यालय मात्र ₹ 2.44 करोड़ ही संग्रह विकास में खर्च कर सका था। पुस्तकालय के स्वचलन, रे.आ.प.त. प्रद्यौगिकी, कम्प्यूटरीकृत सूची तथा डिजीटल लाइब्रेरी प्रयोगशाला की स्थापना के कार्य निधियों की उपलब्धता होने पर भी नहीं कराए गए।

उत्तर में विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मई 2012) कि अवशेष अनुदान के उपयोग के प्रयास किए जा रहे थे।

(ग) दो फ्यूमीगेशन चैम्बर 2005 में ₹ 0.33 लाख में पुस्तकों को रासायनिक उपचार द्वारा विसंक्रमित करने हेतु क्रय किये गये किन्तु उसका उपयोग प्राप्ति के समय से ही विशेषज्ञ व्यक्ति की कमी के कारण नहीं किया गया।

(घ) इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय के पास अपने संसाधनों के संरक्षण की कोई मार्ग-दर्शिका नहीं थी। यह पाया गया कि बहुत कीमती पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गयी थीं।



चित्र-1: क्षतिग्रस्त पुस्तकें

विश्वविद्यालय ने इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि (मई 2012) कि इस संबंध में मार्ग निर्देर्शिका बनायी जायेगी तथा इस उद्देश्य से संरक्षण सहायक पद सृजित किया जायेगा।

(ड़) क्लोज सर्किट टेलीवीजन कैमरे (सी.सी.टी.वी.) पुस्तकालय में 2003 में स्थापित किए गए थे, किन्तु क्रियाशील नहीं थे (मार्च 2012)। आगे, अग्नि शमन के सुरक्षात्मक उपाय स्थापित नहीं किए गए थे।

(च) सामान्य वित्तीय नियम (सा.वि.नि.) 194 में प्रावधान है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 50 हजार से अधिक है तो उनका भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के अंतराल पर किया जाना चाहिए किन्तु पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने पर भी नहीं किया गया था।

विश्वविद्यालय ने स्वीकार करते हुए कहा (मई 2012) कि स्टाफ की कमी तथा संकलन के सूचीबद्ध न होने के कारण भौतिक सत्यापन नहीं हो सका।

अनुशंसा

- *विश्वविद्यालय को अपने पुस्तकालय संसाधनों के संरक्षण के लिए क्रियाविधि अपनानी चाहिए।*
- *पुस्तकों का भौतिक सत्यापन आवधिक रूप से सा.वि.नि. 194 के अनुसार किया जाना चाहिए।*

2.2.8 वित्तीय प्रबन्धन

2.2.8.1 बजट एवं व्यय

विश्वविद्यालय मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित होता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के राजस्व के अन्य स्त्रोत छात्रों से प्राप्त शुल्क, निवेश एवं बचत खातों से प्राप्त ब्याज है।

वर्ष-वार प्राप्त अनुदान तथा उपयोग का विवरण निम्न हैः-

तालिका-9

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अभिवृद्धि (अनुदान तथा अन्य प्राप्तियां)	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल उपयोगिता धनराशि	अंतिम अवशेष
2006-07	38.53	121.69	160.22	95.42	64.80
2007-08	64.80	134.24	199.04	140.52	58.52
2008-09	58.52	165.25	223.77	164.63	59.14
2009-10	59.14	200.64	259.78	227.14	32.64
2010-11	32.64	258.20	290.84	199.70	91.14
2011-12	91.14	219.88	311.02	213.87	97.15

विश्वविद्यालय उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं कर सका, फलतः अवशेष धनराशि 2006-07 में ₹ 64.80 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 97.15 करोड़ हो गयी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (मई 2012) कि अगले वर्ष के अप्रैल में कार्यों से संबंधित व्ययों एवं भुगतानों को पूरा करने के लिए तर्कसंगत अवशेष की आवश्यकता थी। आगे यह भी बताया गया कि कुछ अवशेष धनराशि प्रतिबद्ध व्ययों को पूरा करने के लिए थी।

2.2.8.2 अनुरक्षण अनुदान का अपवर्तन

मा.सं.वि.मं. ने अपने पत्राचार दिनांक 13 नवम्बर 2003 द्वारा वि.अ.आ. को निर्देश दिया, जिसे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को प्रचारित किया गया कि एक संस्थान का बजट किसी भी स्थिति में भ.नि. अंशदान पर संस्थान की ब्याज देयता तथा उसके निवेश से प्राप्त आय के मध्य कमी को पूरा करने के लिए नहीं बढ़ाया जायेगा। यदि पी.एफ. अंशदान पर ब्याज की देयता तथा भविष्य निधि के निवेश पर अर्जित आय में कमी आती है तो संस्थान के पास कम दर से ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, जब तक कि संस्थान की वित्तीय स्थिति सरकार द्वारा सूचित दर से ब्याज के अनुसरण करने की अनुमति न दें।

वि.स. की दूसरी बैठक (अगस्त 2007) में निर्णय लिया गया कि सामान्य भविष्य निधि की अतिरिक्त धनराशि को अल्पकालीन अवधि की जमाओं में, जो बैंक उँची दर से ब्याज दे रहे हैं, निवेश किया जाए। आगे कहा गया कि किसी कमी को पूरा करने के लिए अनुरक्षण अनुदान का सहारा न लिया जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा सा.भ.नि. अवशेष का बैंकों में 5.5 से 11.25 *प्रतिशत* के मध्य विनियोग किया गया, परिणामस्वरूप 2008-12 के मध्य घोषित ब्याज दर का भुगतान किए जाने पर ₹ 4.49 करोड़ की कमी हुई।

2008-09 से 2009-10 में कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने ₹ 1.31 करोड़ का अनुरक्षण मद से अपवर्तन किया। (₹ 43.63 लाख मार्च 2010 तथा ₹ 87.66 लाख मार्च 2011) बाद के वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 में ₹ 3.81 करोड़ की कमी थी।

विश्वविद्यालय ने कहा (मई 2012) कि सा.भ.नि. के ब्याज का भुगतान एक सांविधिक सेवा व्यय है जिसे अनुरक्षण अनुदान से पूरा किया गया तथा यह अपवर्तन नहीं था।

विश्वविद्यालय की कार्यवाही स्पष्टतया मा.सं.वि.मं./वि.अ.आ. के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती थी।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को मा.सं.वि.मं./वि.अ.आ. के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को सा.भ.नि. खाते पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए।*

2.2.8.3 परिवहन भत्ता का अनियमित भुगतान

पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के तारतम्य में भारत सरकार ने 1 अगस्त 1997 से कर्मचारियों को निवास स्थान से कार्यस्थल तक के मध्य किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु परिवहन भत्ता स्वीकृत किया था। उक्त आदेश के क्रम में परिवहन भत्ता उन कर्मचारियों को देय नहीं था, जिनकी अनुपस्थिति की अवधि कार्यस्थल छुट्टी, प्रशिक्षण, भ्रमण के कारण तीस दिन से अधिक हो।

प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षण स्टाफ के लिए ग्रीष्म अवकाश 7 मई से 15 जुलाई तक घोषित करती है। तदनुसार प्रत्येक वर्ष जून माह में परिवहन भत्ता देय नहीं था। यद्यपि इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों ने

शिक्षण स्टाफ को जून माह के परिवहन भत्ते का भुगतान किया। 2006-07 से 2011-12 के मध्य कुल ₹ 50.97 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया।

उत्तर में विश्वविद्यालय ने बताया (मई 2012) कि ग्रीष्म अवकाश न तो कार्य से अनुपस्थिति है और न ही वि.नि./से.नि. की श्रेणी में आता है। इसके अलावा, शिक्षण स्टाफ अनुसंधान/परीक्षा/प्रवेश परीक्षा इत्यादि में विभाग/कार्यालय में उपस्थिति हुआ। विश्वविद्यालय का उत्तर घोषित अवकाश में परिवहन भत्ते के भुगतान को न्याय संगत नहीं ठहराता।

2.2.9 संरचनात्मक प्रबंधन

2006-07 से 2011-12 के मध्य कुल 16 भवन परियोजनाएं निर्माण के लिए ली गई जिनमें सात परियोजनाएं[6] पूर्ण हो चुकी थीं, तीन परियोजनाएं शुरू होनी थीं तथा छः परियोजनाएं प्रगति पर थीं, यद्यपि उनकी अनुबंध अवधि पूर्ण हो चुकी थी।

परिसर के संरचनात्मक विकास के लिए 16 परियोजनाओं पर आवंटन तथा व्यय क्रमशः ₹ 180.26 करोड़ तथा ₹ 90.66 करोड़ था।

विश्वविद्यालय ने भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि तथा अप्रयुक्त अवशेष के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी। अभिलेख व्यक्तिगत कार्य की पत्रावली सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निम्न टिप्पणी की जाती है।

2.2.9.1 33/11 के.वी. उपकेन्द्र

जाँच से पता चला कि 33/11 के.वी. उपकेन्द्र के पूर्ण हो जाने पर भी विद्युत आपूर्ति संयोजन हेतु भूमिगत केबल, जिसे रेलवे लाईन से होकर गुजरना था, के अभाव में इसे चालू नहीं किया जा सका। रेलवे प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। जब विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया (नवम्बर 2010) रेलवे प्राधिकारियों द्वारा 10 वर्ष के लिए ₹ 13.37 लाख (जून 2011) के लीव चार्जेज मांगे गये, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

---

[6] पूर्ण कार्यः 1. पी.सी.बी. कॉम्पलैक्स -प्रथम चरण में लड़कों के छात्रावास का निर्माण, 2. पी.सी.बी. कॉम्पलैक्स -द्वितीय चरण में लड़कों के छात्रावास का निर्माण, 3. 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन की संस्थापना, 4. लड़कियों के छात्रावास का निर्माण, 5. ऊपरी टैंक, 6. विधि पांच वर्षीय भवन-प्रथम चरण, 7. 24-टाइप -II क्वार्टर।

इस प्रकार रेलवे से स्वीकृति प्राप्त न होने पर उपकेन्द्र कार्य प्रारम्भ नहीं कर सका।

विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (मई 2012) कि रेलवे से लीव चार्जेज की माफी के लिए प्रार्थना की गई थी। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के निवेदन पर उत्तर देने में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई।

पूर्व अनुमति अथवा उचित अनुश्रवण के अभाव में उपकेन्द्र पुनः निष्क्रिय रहा।

2.2.9.2 विरासत भवन

विश्वविद्यालय 125 वर्ष पुराना है, इसके बहुत से विरासत भवन हैं। इन भवनों की मरम्मत एवं पुनरूद्धार के लिए दसवीं योजना में ₹ 3.00 करोड़ तथा ग्यारहवीं योजना में ₹ 5.15 करोड़ वि.अ.आ. द्वारा आवंटित हुआ था। विजयनगरम हॉल के संरक्षण हेतु भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति धरोहर न्यास (भा.रा.क.सं.ध.न्या.) द्वारा प्रारम्भिक आकलन ₹ 3.45 करोड़ का तैयार कर प्रस्तुत किया गया (जनवरी 2008)। बाद में कार्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सल्टेंट आधार पर राइट्स को दिया गया (अप्रैल 2009) जिसने जून 2011 में ₹10.87 करोड़ का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया। राइट्स द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, क्योंकि एजेन्सी को अग्रिम का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार कार्य को प्रदान करने में देरी के परिणामस्वरूप लागत मे बढ़ोत्तरी हुई तथा इस विरासत भवन की अधोगति की रोकथाम हेतु संरक्षण एवं पुनरूद्धार कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका (मार्च 2012)।



चित्र 2 दरभंगा हॉल की जीर्ण-शीर्ण दशा



चित्र -3 टूटा हुआ अशोक स्तम्भ

यह देखा गया कि कई अन्य मूर्तियाँ/भित्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, जिनकी मरम्मत के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। दरभंगा हॉल में स्थित अशोक स्तम्भ टूटा हुआ था। (ऊपर चित्र 2 तथा 3)।

विश्वविद्यालय ने बताया कि संरक्षण एक विशिष्ट कार्य था, तथा वह अपनी विरासत के लिए सजग भी था, तथा संरक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे। आगे बारहवीं योजना में अन्य विरासत भवनों के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था।

2.2.10 निष्कर्ष

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2006-2012 की अवधि आच्छादित थी, में पता चला कि प्राधिकारियों की बैठकें निर्धारित समयान्तराल में नहीं की गई, केन्द्रों के खोले जाने के उद्देश्य नहीं प्राप्त किए गए, शिक्षण स्टाफ की कमी थी, विश्वविद्यालय, गुणवत्ता आश्वासन के सम्बन्ध में अपनी गतिविधियां संगठित नहीं कर सका, अनुसंधान कार्यों का अनुश्रवण नहीं हो सका तथा अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। इसके द्वारा अनुरक्षण अनुदान का अपने कर्मचारियों को सा.भ.नि. खातों पर ब्याज के भुगतान में अपवर्तन किया गया।

परिशिष्ट-1

केन्द्रों की स्थिति

(पैराग्राफ 2.2.2.1)

क्रमांक	केन्द्रों का नाम जिन्हें स्थापित करना था।	वर्ष जिसमें स्थापित हुए
1.	जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र	2000
2.	के. बैनर्जी वायुमंडलीय एवं समुद्री अध्ययन केन्द्र	2000-2001
3.	जैव सूचना विज्ञान केन्द्र	2002
4.	भौतिक विज्ञान केन्द्र	2009
5.	वैश्वीकरण अध्ययन केन्द्र	2010
6.	मेघनाद साहा अंतरिक्ष अध्ययन केन्द्र	स्थापित
7.	महिला अध्ययन केन्द्र	स्थापित
8.	जैव चिकित्सा चुम्बकीय प्रतिध्वनि केन्द्र	स्थापित नहीं
9.	संस्कृति एवं संचार केन्द्र	स्थापित नहीं
10.	पर्यावरण अध्ययन केन्द्र	स्थापित नहीं
11.	मानवाधिकार अध्ययन केन्द्र	स्थापित नहीं
12.	बौद्धिक संपदा अधिकार केन्द्र	स्थापित नहीं
13.	विकासशील देशों के लिए मोबाइल संचार केन्द्र	स्थापित नहीं
14.	सूक्ष्म विज्ञान एवं सूक्ष्म तकनीकी केन्द्र	स्थापित नहीं
15.	विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन	स्थापित नहीं

परिशिष्ट-2

शिक्षक - छात्र अनुपात

(पैराग्राफ 2.2.2.3 देखें)

वर्ष	शिक्षक संख्या	पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या	शिक्षक छात्र अनुपात
2006-07	346	19609	1:57
2007-08	338	24432	1:72
2008-09	335	14357	1:43
2009-10	347	20420	1:59
2010-11	347	16173	1:47
2011-12	315	22615	1:72

परिशिष्ट-3
असफल एवं अलग हुए की दर
(पैराग्राफ 2.2.2.4 देखें)

वर्ष	छात्रों की संख्या जो परीक्षा में सम्मिलित हुए	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	छात्रों की संख्या			छात्रों की संख्या का प्रतिशत जो सम्मिलित हुए		
			असफल	अलग हुये/अनुपस्थित	योग	असफ	अलग हुये/अनुपस्थित	योग
बी.ए.प्रथम								
2007	2746	2047	471	228	699	17	8	25
2008	2770	2155	412	203	615	15	7	22
2009	2861	2228	388	245	633	14	8	22
2010	3324	2436	596	292	888	18	9	27
2011	4032	2952	709	371	1080	18	9	27
2012	11041	7379	2538	1124	3662	23	10	33
बी.एस.सी. प्रथम								
2007	821	400	226	195	421	28	23	51
2008	751	337	159	255	414	21	34	55
2009	761	317	212	232	444	28	30	58
2010	922	402	223	297	520	24	32	56
2011	1087	489	276	322	598	25	30	55
2012	3358	1168	1395	795	2190	42	24	66
बी.कॉम. प्रथम								
2007	468	339	129	0	129	28	0	28
2008	468	415	27	26	53	6	5	11
2009	473	388	33	52	85	7	11	18
2010	536	475	29	32	61	5	6	11
2011	642	540	53	49	102	8	8	16
2012	3871	2824	753	294	1047	19	8	27

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-पद्धति

अध्याय III : मानव संसाधन विकास मंत्रालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य-प्रद्धति

विशिष्टताएं

❖ स्कूलों और विभागों के खोले जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(पैराग्राफ 3.3.1.1)

❖ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को XIवीं योजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था, जिससे निर्माण कार्य सौंपने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप योजना अवधि में महत्वपूर्ण भवन परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकीं।

(पैराग्राफ 3.3.1.2)

❖ अप्रयुक्त निधियां वर्ष 2006-07 में ₹2.56 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹54.30 करोड़ तक बढ़ गई।

(पैराग्राफ 3.3.2.1)

❖ शिक्षण स्टाफ की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के बीच थी।

(पैराग्राफ 3.3.4.1)

❖ विश्वविद्यालय अवसंरचना जैसे भवन तथा अन्य सुविधाएं अर्थात छात्रावास, क्रीड़ा परिसर, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की कमी के साथ कार्य कर रहा था।

(पैराग्राफ 3.3.5.1)

अनुशंसाओं का सार

- *विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.)/मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) के परामर्श से स्कूलों एवं विभागों के खोले जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे, जैसाकि शैक्षणिक अध्यादेश में निर्धारित था।*
- *विश्वविद्यालय उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त अनुदान के संदर्भ में अपने व्यय की योजना बनाए।*
- *विश्वविद्यालय निष्क्रिय निधियों का उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करे।*
- *विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (रा.मू.प्र.प.) से अपने पाठयक्रमों का प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाए।*
- *विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए।*
- *विश्वविद्यालय, अपने विद्यालयों या विभागों के लिए भवनों की उचित अवसंरचना के साथ-साथ अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र तथा क्रीड़ा परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें।*

3.1 प्रस्तावना

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ को राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट/पोस्ट डॉक्टरेट अध्ययन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान प्रदान करने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय को बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के अधीन बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के नाम से पुनः नामित किया गया और विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित (जनवरी 1996) किया गया था। अधिनियम के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगेः

(i) शिक्षण की ऐसी शाखाओं जहां पर यह उचित समझें, में निर्देशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं मुहैया करवा कर उन्नत ज्ञान को बढावा देना;

(ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मुख्य सीमान्त क्षेत्रों तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रमों का प्रावधान बनाना;

(iii) कृषि प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण शिल्प सहित सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास से सम्बन्धित उपयुक्त पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करना;

(iv) उन सिद्धान्तों जिसके लिए बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने जीवन काल में काम किया, के अध्ययन को बढ़ावा देना अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक न्याय एवं जीवन की लोकतांत्रिक शैली एवं विश्व के संविधानों का अध्ययन करना और,

(v) परस्पर अनुशासनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान में शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में नवीनीकरण को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाया जाना तथा जन सामान्य की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति और कल्याण पर विशेष ध्यान देना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की पर्याप्त प्रतिशतता मुहैया कराकर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का कल्याण करना।

21 विभागों वाले आठ स्कूलों जिन्होंने विभिन्न विषयों में 22 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं 17 पी.एच.डी. के कार्यक्रम **(अनुबंध-1)** मुहैया कराए, के माध्यम से विश्वविद्यालय के लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

उप-कुलाधिपति (उ.कु.) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी एवं शैक्षणिक प्रमुख है और सामान्य पर्यवेक्षण तथा विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। विश्वविद्यालय की विशिष्ट गतिविधियां विभिन्न प्राधिकारियों अर्थात प्रबंधन बोर्ड (प्र.बो.), शैक्षिक परिषद,

योजना बोर्ड, अध्ययन बोर्ड और वित्त समिति द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है। उ.कु. की सहायता कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, स्कूलों के डीन और विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। उ.कु. प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद, योजना बोर्ड और वित्त समिति का भी अध्यक्ष होता है।

3.2 लेखापरीक्षा अभिगम

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत की गई थी।

3.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए योजना, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक गतिविधियों, मानव शक्ति प्रबन्धन और अवसंरचना के विकास से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच सम्मिलित है।

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह जानना था कि क्या:

- विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना प्रक्रिया पर्याप्त एवं प्रभावी थी ;
- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन विवेकपूर्ण था;
- प्रारम्भ किए गए शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियां, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी;
- शिक्षण संकाय पर्याप्त था और,
- अवसंरचनात्मक सुविधाएं पर्याप्त थीं।

3.2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से प्राप्त किए गए थे:

- बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994;
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) के दिशानिर्देश;
- सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 और भारत सरकार के अन्य आदेश/नियम;
- विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त

3.2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2011 में उ.कु. के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ आरम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदण्ड तथा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थी। विश्वविद्यालय के अभिलेखों की जांच जून 2011 से दिसम्बर 2011 के दौरान की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा फरवरी 2012 में विश्वविद्यालय तथा जून 2012 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) को प्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं की चर्चा हेतु 20 सितम्बर 2012 को उ.कु. के साथ निर्गम बैठक की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। विश्वविद्यालय (सितम्बर 2012) तथा मंत्रालय (फरवरी 2013) से प्राप्त उत्तर को यथोचित रूप में प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

3.2 5 आभार प्रकट

हम लेखापरीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सहायता एवं सहयोग का आभार प्रकट करते हैं।

3.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.1 नियोजन प्रकिया

योजनाएं, लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। अतः संगठनात्मक या समग्र उद्देश्यों की स्थापना, नियोजन का पहला कदम है। नियोजन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं।

3.3.1.1 पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ

30 दिसम्बर 2004 को भारत के राजपत्र द्वारा अधिसूचित शैक्षिक अध्यादेश के अनुसार, 17 स्कूलों एवं 55 विभागों को भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया जाना था (**अनुबंध-1**)। तथापि, 21 विभागों वाले केवल आठ स्कूल ही मार्च 2012 तक स्थापित किए गये थे।

संवीक्षा ने प्रकट किया कि शैक्षिक अध्यादेश में पारिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई दीर्घ/मध्यम/अल्प अवधि योजना नहीं बनायी गयी थी। यह

भी पाया गया था कि महत्वपूर्ण विद्यालयों जैसे भू-विज्ञान, ऊर्जा अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषाएं एवं साहित्य, ललित कला, प्रदर्शन कला, वाणिज्य तथा अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अभी भी स्थापित किया जाना था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि धन की उपलब्धता के अनुसार चार विद्यालय भवनों[1] का निर्माण किया गया था। आगे यह भी आश्वासन दिया गया था कि वि.अ.आ./मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.) द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार शेष विद्यालयों का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

उत्तर में संदर्भित चार विद्यालयों (भवनों) विश्वविद्यालय में पहले से ही संचालित है। उत्तर में शेष नौ विद्यालयों एवं 34 विभागों के लिए नियोजन प्रक्रिया व समयावधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, धन की अनुपलब्धता जो प्रमुख कारण के रूप में इंगित थी, को वि.अ.आ. द्वारा XIवीं योजना हेतु संस्वीकृति अनुदान के अनुपयोग के सन्दर्भ में आगे के पैरों में देखा जा सकता है।

3.3.1.2 XIवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन

वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय को XIवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की आवश्यकताएं तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था (फरवरी 2007)। विश्वविद्यालय ने पांच नए विद्यालयों तथा 17 विभागों एवं अन्य सुविधाओं अर्थात सभागार, केन्द्रीय पुस्तकालय, क्रीडा परिसर और स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए ₹373 करोड़ की अंतिम समेकित XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की (जून 2008)। वि.अ.आ. ने दो विद्यालयों एवं अन्य भवनों के निर्माण के लिए ₹ 145.91 करोड़ का XIवीं योजना आवंटन अनुमोदित किया (मार्च 2009)।

[1] पर्यावरण विज्ञान, अम्बेडकर अध्ययन, जैविक विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के स्कूल भवन निर्मित थे, और विधिक अध्ययन विद्यालय के भवनों का कार्य निर्माणाधीन था।

विश्वविद्यालय की भवन समिति द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को संस्वीकृति की प्राप्ति (मार्च 2009) के एक वर्ष चार माह बाद अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2010)। ₹145.91 करोड़ के कुल आवंटन में से वि.अ.आ. ने मार्च 2012 तक ₹113.35 करोड़[2] जारी किए थे। विश्वविद्यालय केवल ₹75.73 करोड़ (67 *प्रतिशत*) उपयोग कर सका तथा शेष ₹37.62 करोड़ XIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक अप्रयुक्त रहे (मार्च 2012)। XIवीं पंचवर्षीय योजना को विलम्ब से अंतिम रूप दिए जाने (अगस्त 2010) एवं कार्यों के प्राक्कलन को विलम्ब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण योजना के तीन वर्ष 6 माह बाद भी बड़े विकासात्मक निर्माण कार्यों को ही प्रारम्भ किया जा सका (अक्तूबर 2012)।

XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव एवं निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा कुल जारी निधियों का उपयोग करने में विश्वविद्यालय की असमर्थता के परिणामस्वरूप इसके नियोजित भवन का समापन नहीं हुआ (**अनुबंध-2**)।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि, पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस विश्वविद्यालय का बारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव वि.अ.आ. को समय पर प्रस्तुत किया गया था।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय, वि.अ.आ./मा.सं.वि.मं. के परामर्श से अपने शैक्षिक अध्यादेश में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे।*

2

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित	वि.अ.आ. द्वारा आवंटित	वि.अ.आ. द्वारा जारी		व्यय	संचयी अप्रयुक्त शेष
		वर्ष	धनराशि		
373.00 (जून 2008)	145.91 (मार्च 2009)	2007-08 (08.06.2007)	3.35 (अग्रिम अनुदान)	0.59	2.76
		2008-09	--	3.37	-0.61
		2009-10 (31.03.2009) (31.03.2010)	08-09 के लिए 10.00 एवं 09-10 के लिए12.00	6.57	14.82
		2010-11 (21.12.2010)	29.00	27.55	16.27
		2011-12 (27.11.2011) (04.01.2012)	9.50 49.50	37.65	37.62
		योग	113.35	75.73	37.62 (संचयी)

3.3.2 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय गतिविधियों की योजना, आयोजन, निर्देशन तथा नियंत्रण से सम्बन्धित है तथा इसमें प्रापण और उद्यम की निधियों का उपयोग शामिल है। इसका अभिप्राय उद्यम के वित्तीय संसाधनों पर सामान्य प्रबंधन सिद्धान्तों को लागू करने से है।

3.3.2.1 निधियों का उपयोग

विश्वविद्यालय मुख्यतः वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित होता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों से प्राप्त शुल्क के निवेश एवं बचत खातों से प्राप्त ब्याज आदि के माध्यम से अपना स्वयं का राजस्व सृजित करता है।

वर्ष 2006-12 के दौरान निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग का वर्षवार विवरण निम्नानुसार दर्शाया है:-

तालिका-1:निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त अनुदानें	अन्य आय	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग की कुल निधियां	अप्रयुक्त निधियां[3]
2006-07	1.04	7.99	11.26	20.29	17.73	2.56
2007-08	2.56	16.13	8.59	27.28	21.22	6.06
2008-09	6.06	7.93	12.76	26.75	24.23	2.52
2009-10	2.52	37.96	4.31	44.79	20.68	24.11
2010-11	24.11	46.77	6.85	77.73	46.84	30.89
2011-12	30.89	79.33	3.68	113.90	59.60	54.30

विश्वविद्यालय कुल धनराशि का उपयोग नहीं कर सका और पूर्व वर्ष की शेष धनराशि को अग्रेषित किया जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2007 में धनराशि ₹ 2.56 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 54.30 करोड़ हो गयी। संवीक्षा ने प्रकट किया कि इस धनराशि का बड़ा हिस्सा ₹ 47.26 करोड़ (₹ 43.52 करोड़ योजनागत अनुदान, ₹ 1.06 करोड़ रिहायशी कोचिंग अकादमी के लिए, ₹ 1.30 करोड़ जगजीवन राम छात्रावास के लिए और ₹ 1.38 करोड़ जगजीवन राम बालिका छात्रावास के लिए) योजना तथा निर्माण अभिकरणों को निर्माण कार्य सौंपने में विलम्ब के कारण था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि योजनागत के मामले में उन्हें अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं सा.वि.नि. का पालन करना था, जबकि गैर-योजनागत व्यय के

[3] योजनागत और गैर-योजनागत

मामले में अनुदान अगले वित्तीय वर्ष के लिए मार्च के अंत में जारी[4] किया गया था इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

दिशानिर्देशों के अनुपालन में विलम्ब का कारण उत्तर से मेल नहीं खाता है। आगे अप्रयुक्त राशि की बढ़ती प्रवृत्ति यह स्थापित करती है कि जो धनराशि मार्च के अंत में प्राप्त हुई, उसे अगले वर्ष में उपयोग नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय को निधि प्रवाह के संबंध में दीर्घ/लघु अवधि योजना तैयार करनी चाहिए तथा तदनुसार निधियों के शीघ्र उपयोग की योजना बनानी चाहिए।

3.3.2.2 निधियों का निवेश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर अधिनियम 1994 अधिनियम के अध्यादेश 6 (दूसरी अनुसूची) के अनुसार वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा, वित्तीय नीति पर सलाह देगा और विश्वविद्यालय के निवेश का प्रबन्धन एवं नियंत्रण करेगा।

यद्यपि, विश्वविद्यालय ने 31 मार्च 2012 तक ₹ 2.52 करोड़ से ₹ 54.30 करोड़ तक अप्रयुक्त निधियों की लगातार वृद्धि देखी परन्तु इसने निधियों के प्रबन्धन हेतु कोई निवेश नीति तैयार नहीं की थी (मार्च 2012)। अप्रयुक्त निधि, समीक्षा की अवधि के दौरान बचत खातों में कम ब्याज दर (लगभग 3.5 से 4.0 *प्रतिशत*) पर पड़ी रही। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, विश्वविद्यालय में उपलब्ध निधियों को निवेश करने के लिए एक निवेश और मॉनीटरिंग समिति गठित की गई थी (मार्च 2012)।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2012) कि वि.अ.आ. से प्राप्त अनुदान के निवेश के सम्बन्ध में कई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। प्रबन्धन ने आगे बताया कि, वि.अ.आ. ने अनुदान व्यय हेतु दिया है, न कि निवेश हेतु।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय औचित्य में अपेक्षित था कि उपलब्ध निधियों का निवेश बेहतर लाभ पाने के लिए किया जाना चाहिए। यहां तक कि बैंकों द्वारा फ्लेक्सी खाता सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे निष्क्रिय निधियां भी बेहतर लाभ प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा वि.अ.आ. द्वारा निष्क्रिय निधियों के निवेश पर कोई रोक नहीं थी।

---

[4] ₹ 0.73 करोड़ की अग्रिम अनुदान दोनों वर्षों 2010-11 एवं 2011-12 के लिए जारी की गई थी।

अनुशंसाएं

- ❖ *विश्वविद्यालय को उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त अनुदान के संदर्भ में व्यय की योजना बनानी चाहिए।*
- ❖ *विश्वविद्यालय को निष्क्रिय निधियों का उपयुक्त निवेश सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.3.3 शैक्षणिक कार्यक्रम

3.3.3.1 ग्रहण क्षमता का उपयोग

विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए 22 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रथम वर्ष के नामांकन से सम्बन्धित विश्लेषण ने प्रकट किया कि, 17 पाठ्यक्रमों में नामांकन संतोषजनक अर्थात 75 *प्रतिशत* से अधिक थे। तथापि, पांच पाठ्यक्रमों[5] में औसत रिक्तता 25 *प्रतिशत* से अधिक (25 से 52 प्रतिशत के बीच) थी जैसा **अनुबंध 3** में दर्शाया गया है।

इन पाठ्यक्रमों में छात्रों की अल्प रूचि दर्शाती है कि विश्वविद्यालय में प्रारम्भ पाठ्यक्रमों का चयन मांग के उचित मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि, विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है और छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश देता है। प्रबन्धन ने विश्वविद्यालय में प्रारम्भ पाठ्यक्रमों का चयन उचित अध्ययन के आधार पर न करने की बात स्वीकार करते हुए सूचित किया कि अब अधिक छात्रों को आकर्षित करने के लिए हमारे शैक्षणिक अध्यादेश के अनुसार अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

3.3.3.2 गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता

राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद (रा.नि.प्र.प.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की अनुशंसाओं का परिणाम थीं, जिसने भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने पर विशेष बल दिया। रा.नि.प्र.प. को वि.अ.आ. द्वारा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों

---

[5] अर्थशास्त्र 35%; राजनीति शास्त्र-37%; मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन-35%; व्यावहारिक पशु विज्ञान-31% एवं व्यावहारिक सांख्यिकी-52%।

का निर्धारण तथा प्रत्यापन हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन अभिकरण के रूप में 1994 में स्थापित किया गया था।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय या इसके किसी भी पाठ्यक्रम के प्रत्यायन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

प्रबंधन ने (अगस्त 2012) बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसने प्रत्येक विभाग में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आ.गु.आ.से.) की स्थापना की है जो रा.नि.प्र.प. से प्रत्यायन प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।

3.3.3.3 उत्कृष्टता केन्द्र

विश्वविद्यालय ने पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण विधि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने के लिए योजना बनायी थी (2007-09) लेकिन इसे मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि विश्वविद्यालय को 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में न केवल कानून विभाग एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग बनाने की दृढ़ बचनबद्धता है बल्कि यह अपने सभी विभागों को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने हेतु प्रतिबद्ध भी था। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि वह बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक या दो क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों को स्थापित करने में समर्थ होगा।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय, रा.नि.प्र.प. से अपने पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन कराने हेतु उचित कदम उठाए।*

3.3.4 श्रमशक्ति प्रबन्धन

श्रमशक्ति प्रबन्धन, संगठन की मानव संसाधन आवश्यकताओं की योजना एवं संसाधन तथा उनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करता है। चलायमान बने रहने हेतु संगठन को पर्याप्त स्टाफ एवं प्रत्येक पद पर उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों के होने की आवश्यकता है।

3.3.4.1 स्टाफ की कमी

वि.अ.आ. विभागों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय में पदों की संख्या स्वीकृत करता है। प्रत्येक वर्ष हेतु स्वीकृत पदों एवं कार्यरत शिक्षण स्टाफ की स्थिति निम्न थी;

तालिका-2: संस्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी

वर्ष	संस्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पद एवं इसकी स्वीकृत पद से प्रतिशतता
2006-07	87	38	49(56)
2007-08	87	37	50(57)
2008-09	130	76	54(41)
2009-10	130	76	54(41)
2010-11	130	76	54(41)
2011-12	130	108	22 (17)

जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, शिक्षण स्टाफ की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के बीच थी। 2008-09 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पांच विभागों[6] हेतु प्रत्येक विभाग में 6 पद स्वीकृत किए गए थे जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2010-11 में स्थापित किया गया था। तथापि, संकायों की नियुक्तियां शैक्षणिक सत्र 2011-12 के दौरान की गयी थी।

आगे संवीक्षा ने प्रकट किया कि, संकायों की कमी के कारण 2006-12 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा मात्र 22 अनुसंधान परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं जिसमें से केवल दो परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सका था (मार्च 2012)। इस प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान क्रियाकलापों में नगण्य प्रगति थी।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2012) कि विश्वविद्यालय में श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित/योग्य श्रमशक्ति को नियुक्त करने हेतु अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर रहा है।

अनुशंसा

- ❖ *विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा और अनुसंधान क्रियाकलापों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को भरें।*

[6] औषधि विज्ञान, व्यावहारिक भौतिकी, व्यावहारिक रसायन, व्यावहारिक गणित एवं ग्रामीण प्रबन्धन

3.3.5 अवसंरचना सुविधाएं

3.3.5.1 बुनियादी सुविधाओं की कमी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं आवश्यक हैं। यह पाया गया था कि 1999-2000 तक विश्वविद्यालय के पास केवल एक ही विद्यालय इमारत थी, जो दो विद्यालयों (सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय) और पर्यावरण विज्ञान विद्यालय की आवश्यकता को पूरा कर रही थी। पर्यावरण विज्ञान विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में पूरा हुआ था। 2000-01 से 2011-12 के दौरान केवल एक अतिरिक्त विद्यालय भवन सहित छः विद्यालयों और 18 विभागों (**अनुबंध-4**) को विश्वविद्यालय से जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, इन विद्यालयों/विभागों पर स्थान के सीमित उपयोग के अंतर्गत संचालित करने का दवाब डाला गया है, जैसे व्याख्यान कक्ष का पारी वार उपयोग, परिसंचरण क्षेत्रों में केबिनों का निर्माण, आवासों को कार्यालय के रूप में एवं प्रशासनिक भवन का प्रयोग कक्षा हेतु करना।

आगे यह भी पाया गया था कि, छात्रावास सुविधा की कमी थी और 50 *प्रतिशत* से ज्यादा विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। यद्यपि, अधिनियम की धारा 8 में यह प्रावधान है कि "विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्यतः एक हॉल या छात्रावास में रहता है"। अन्य सामान्य सुविधाएं अर्थात स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर और परिवहन सुविधा (विश्वविद्यालय लखनऊ शहर से लगभग 15 कि.मी. दूर है) या तो उपलब्ध नहीं थी या फिर अपर्याप्त थी।

प्रबंधन ने माना (अगस्त 2012) कि विभिन्न विद्यालयों के लिए भवनों की अतिशीघ्र आवश्यकता है। आगे यह सूचित किया गया था कि अन्य आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2013) कि अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय को अपने वैधानिक निकायों नामतः शैक्षणिक परिषद और प्र.बो. की स्वीकृति से विद्यालय और विभाग स्थापित करने का अधिकार है और वह शैक्षणिक कार्यों को सुचारू रूप से करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी स्थापित कर सकता है। आगे यह बताया गया कि विश्वविद्यालय वास्तव में जारी की गई निधियों का प्रयोग नहीं कर सका था।

3.3.5.2 सेन्टेज प्रभार का परिहार्य भुगतान

वि.अ.आ. द्वारा ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए भवनों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए ₹100 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गई थी (मार्च 2009)। भवन समिति, योजना

अवधि के भीतर निधियों का उपयोग करने तथा संस्वीकृत अनुदान व्यपगत न हो, की दृष्टि से, एक वर्ष के भीतर कार्य पूरा करना चाहती थी, तथा तदनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) से पूछा गया कि क्या वे सभी 10 परियोजनाओं को 12 महीने में पूरा कर सकेंगे। के.लो.नि.वि. ने निर्धारित समय में मात्र तीन कार्यों को पूरा कर सकने में समर्थता व्यक्त की। विश्वविद्यालय ने (सितम्बर/अक्तूबर 2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को तीन निर्माण कार्य जिनका अनुमानित व्यय ₹ 28.10 करोड़ था, पांच निर्माण कार्य (अक्तूबर 2010) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अनुमानित दर ₹ 94.76 करोड़ (**अनुबन्ध-2**) पर तीन राज्य निगमों[7] को दिया और शेष दो कार्य मार्च 2012 तक प्रारम्भ नहीं किए जा सके थे। हालांकि, निगमों ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दर से अधिक ₹ 6.19 करोड़ सेन्टेज प्रभार लिया था। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बिना विश्वविद्यालय ने निर्माण कार्य को पारदर्शी, तुलनात्मक और उचित प्रकार से कराने से वंचित रखा। इसके अतिरिक्त, कोई भी कार्य निर्धारित एक वर्ष की अवधि अर्थात् जनवरी 2012 तक पूरा नहीं हुआ। दिनांक 31 मार्च 2012 को निर्माण कार्यों की प्रगति 20 से 70 *प्रतिशत* के बीच थी। यदि निर्माण कार्य निगम के स्थान पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया होता तो ₹ 6.19 करोड़ सेन्टेज प्रभार को बचाया जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि सा.वि.नि. के प्रावधानों के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही कार्यों को विभिन्न निर्माण एजेंसियों को दिया गया था, क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्धारित समय में निर्माण कार्यों को समाप्त करने में असमर्थता दर्शायी थी। विश्वविद्यालय ने आगे बताया कि उनका केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ अच्छा अनुभव नहीं रहा था। इसने न केवल Xवीं योजना के निर्माण कार्यों में देर की, बल्कि लेखा समायोजन में भी देरी की।

सेन्टेज प्रभार देने के बावजूद कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने की असमर्थता को उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सा.वि.नि. नामांकन के आधार पर कार्यों के आवंटन की अनुमति नहीं देता है। इस प्रकार, अधिक भुगतान के बाद भी योजना के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

---

[7] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम और कन्सट्रक्शन एवं डिजाइन सेवाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम।

अनुशंसा

❖ *विश्वविद्यालय को समुचित भवन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर और आवागमन की सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्णय लेने चाहिए।*

3.4 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति में निम्नलिखित कमियां पायी गयी:

- विश्वविद्यालय, विद्यालय और विभागों को स्थापित करने से सम्बन्धित उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका।
- XIवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तथा अनुमान को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण योजनावधि के समापन के बाद भी XIवीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका।
- अप्रयुक्त निधियों का निवेश न किए जाने के कारण विश्वविद्यालय, बेहतर लाभ प्राप्त करने से वंचित रहा।
- शिक्षण कर्मचारियों की कमी 17 से 57 *प्रतिशत* के मध्य रही थी।
- विश्वविद्यालय, अपर्याप्त आधारभूत अवसंरचना एवं अन्य सुविधाओं जैसे छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल परिसर तथा आवागमन सुविधाओं की कमी के साथ कार्य रहा था।

(रॉय मथरानी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांकः 8 अगस्त 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 14 अगस्त 2013

अनुबंध-1

स्कूल एवं विभागों की स्थिति (31.3.2012 को)

(पैराग्राफ 3.1 एवं 3.3.1.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	स्थापित किये जाने वाले स्कूल का नाम	स्थापित किया गया या नहीं	स्थापना का वर्ष	स्थापित किये जाने वाले विभागों का नाम	स्थापित किया गया या नहीं	स्थापना वर्ष
1	अम्बेडकर अध्ययन स्कूल	हाँ	2000-01	अर्थशास्त्र विभाग	हाँ	2000-01
				इतिहास विभाग	हाँ	2000-01
				राजनीति विज्ञान विभाग	हाँ	2008-09
				दर्शन शास्त्र विभाग	नहीं	-
				सामाजिक कार्य विभाग	नहीं	-
				शिक्षा विभाग	नहीं	-
				समाज शास्त्र विभाग	हाँ	2008-09
2	सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	हाँ	1997-98	सूचना विज्ञान एवं पुस्तकालय विभाग	हाँ	1997-98
				कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	हाँ	1997-98
				सूचना एवं तकनीकी विभाग	हाँ	2007-08
				पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग	हाँ	2008-09
				सतत शिक्षा एवं सामुदायिक सेवाएं विभाग	नहीं	-
3	पर्यावरण विज्ञान का स्कूल	हाँ	1997-98	पर्यावरण प्रभाव अध्ययन विभाग	नहीं	-
				पुनरूद्धार एवं संरक्षण परिस्थिति विज्ञान विभाग	नहीं	-
				पर्यावरण विज्ञान विभाग	हाँ	1997-98
				सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	हाँ	2007-08
4	भू-विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	व्यावहारिक भू-विज्ञान विभाग	नहीं	-
				भू-भौतिक विभाग	नहीं	-
				भू-रसायन विभाग	नहीं	-
5	जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	हाँ	2004-05	व्यावहारिक भू विभान विभाग (रेशम)	हाँ	2001-02
				व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान (बागवानी)	हाँ	2004-05
				जैव प्रौद्योगिकी विभाग	हाँ	2005-06
				औषधि विज्ञान विभाग	हाँ	2010-11
6	गृह विज्ञान का स्कूल	हाँ	2008-09	मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग	हाँ	2008-09
				गृह प्रबन्धन विभाग	नहीं	-
				खाद्य एवं पोषण विभाग	नहीं	-
				क्लॉथिंग एवं टेक्सटाइल विभाग	नहीं	-
				गृह विभाग विस्तार विभाग	नहीं	-
7	ऊर्जा अध्ययन एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल	नहीं	-	नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	नहीं	-
				गैर नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	नहीं	-
8	सामाजिक विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	मानव शास्त्र विभाग	नहीं	-
				बौद्ध अध्ययन विभाग	नहीं	-
9	प्रबन्धन अध्ययन का स्कूल	हाँ	2010-11	ग्रामीण प्रबन्धन का विभाग	हाँ	2010-11
10	शारीरिक विज्ञान का स्कूल	हाँ	2010-11	इलैक्ट्रानिक्स एवं दूरसंचार विभाग	नहीं	-
				व्यावहारिक भौतिकी विभाग	हाँ	2010-11
				व्यावहारिक गणित एवं सांख्यिकीय विभाग	हाँ	2010-11
				व्यावहारिक रसायन विभाग	हाँ	2010-11
11	मानविकी स्कूल	नहीं	-	मनोविज्ञान विभाग	नहीं	-
12	भाषा एवं साहित्य का स्कूल	नहीं	-	संस्कृत एवं पाली विभाग	नहीं	-
				हिन्दी विभाग	नहीं	-
				अंग्रेजी एवं यूरोपियन भाषा विभाग	नहीं	-
				उर्दू विभाग	नहीं	-

				एशियन भाषा विभाग	नहीं	-
13	ललित कला का स्कूल	नहीं	-	चित्रकारी विभाग	नहीं	-
				मूर्तिकला विभाग	नहीं	-
				म्यूजियोलॉजी विभाग	नहीं	-
				व्यावहारिक कला विभाग	नहीं	-
14	प्रदर्शन कला का स्कूल	नहीं	-	संगीत विभाग	नहीं	-
				नृत्य विभाग	नहीं	-
				नाटक विभाग	नहीं	-
15	वाणिज्य का स्कूल	नहीं	-	वित्त एवं लेखा विभाग	नहीं	-
				व्यवसाय अध्ययन विभाग	नहीं	-
				बैकिंग विभाग	नहीं	-
16	प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान का स्कूल	नहीं	-	अंतरिक्ष विज्ञान विभाग	नहीं	-
17	विधिक अध्ययन का स्कूल	हाँ	2000-01	मानवाधिकार विभाग	हाँ	2000-01
				विधि विभाग	हाँ	2008-09

अनुबंध-2

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

(पैराग्राफ 3.3.1.2 के संदर्भ में)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि*	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	स्वीकृत धनराशि	सेन्टेज प्रभार राशि (प्राक्कलन का 7 *प्रतिशत*)	निष्पादित एजेन्सी का नाम	प्रारम्भ करने/पूर्ण करने की तिथि	दिनांक 31.3.12 को भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	
								भौतिक (*प्रतिशत* में)	वित्तीय *प्रतिशत* में)
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14
1	केन्द्रीय पुस्ताकलय	16.03.2009	31.32	20.00	2.05	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम	19.01.2011 / 18.01.2012	38	6.43
2	1200 क्षमता का सभागार	16.03.2009	24.61	15.00	1.61	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम	29.01.2011 / 28.01.2012	42	4.04
3	विधिक अध्ययन हेतु स्कूल	16.03.2009	8.75	8.00	0.57	उ.प्र. समाज कल्याण निगम	01.12.2010 / 03.01.2012	20	1.62
4 (क)	1000 किलो लीटर क्षमता के ओवर हैड टैंक का निर्माण के साथ भूमिगत स्टोरेज ट्यूबबेल, मेन तथा बाह्य पानी लेन	16.03.2009	8.46	8.00	0.55	सी.एण्ड डी. सेवाएं उ.प्र. जल निगम	01.02.2011 / 31.10.2011	65	3.05
4 (ख)	बाह्य सेवाओं का निर्माण जेसे सड़कें, ट्रंक, सीवर लाइनें, ड्रेनेज तथा फुटपाथ आदि	16.03.2009	14.12	12.00	0.92	सी.एण्ड डी. सेवाएं उ.प्र. जल निगम	01.04.2011 / 6.1.2012	30	2.10
5	आवासी कोचिंग अकादमी#	09.09.2009	7.50	7.00	0.49	उ.प्र. समाज कल्याण विभाग	04.10.2010 / 03.01.2012	70	3.89
6	अतिरिक्त दो मंजिला 50 बेड का लड़कियों का छात्रावास	16.03.2009	3.00	3.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	28.04.2009/ 19.03.2010	100	2.18
7	प्रत्येक 272 क्षमता के लड़कों के दो छात्रावास	16.03.2009	14.07	14.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	01/2011 01/2012	92	12.60
8	जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव विज्ञान के विद्यालय भवन का निर्माण (प्रथम चरण)	16.03.2009	11.03	10.00	शून्य	के.लो.नि.वि.	12/2010 12/2011	95	9.00
9	नीचे के क्षेत्र में जमीन भराई	16.03.2009	-	5.00	कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए				
10	बाह्य विद्युतीकरण जैसे 11/44 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण एवं केबिल बिछाना	16.03.2009	-	6.00	कार्य प्रारम्भ नहीं किए गए				
	योग		**122.86**	**108.00**	**6.19**				

* सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत।

\# यह कार्य ₹ 101.00 करोड़ के अतरिक्त स्वीकृत था।

अनुबंध-3

रिक्त पदों के सापेक्ष ग्रहण क्षमता

(पैराग्राफ 3.3.3.1 के संदर्भ में)

क्र. सं.	विषय	वर्ष																		कुल 2006-2012 के लिए			कुल नामांकन (*प्रतिशत* में)	रिक्त पद (*प्रतिशत* में)
		2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12							
		अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	अ	ब	स	कुल ग्रहण	कुल नामांकन	कुल रिक्त पद		
1	अर्थशास्त्र	30	6	24	30	22	8	40	32	8	50	38	12	40	31	9	100	58	42	290	187	103	64.48	35.52
2	इतिहास	30	17	13	20	27	0	40	21	19	46	33	13	50	37	13	50	43	7	236	178	58	75.42	24.58
3	राजनीति विज्ञान							40	13	27	40	17	23	40	39	1	40	32	8	160	101	59	63.13	36.88
4	समाज शास्त्र							30	26	14	30	30	0	46	35	11	50	43	7	156	134	22	85.90	14.10
5	व्यावहारिक पशु विज्ञान	30	4	26	20	13	7	30	23	7	34	26	8	38	33	5	46	38	8	198	137	61	69.19	30.81
6	व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान	30	29	1	30	30	0	30	30	0	34	34	0	36	30	6	30	35	0	190	188	2	98.95	1.05
7	जैवप्रौद्योगिकी	30	28	2	20	20	0	26	24	2	28	28	0	30	32	0	30	30	0	164	162	2	98.78	1.22
8	औषधि विज्ञान													28	28	0	30	30	0	58	58	0	100.00	0.00
9	पर्यावरण विज्ञान	30	25	5	20	20	0	30	30	0	34	34	0	40	42	0	48	48	0	202	199	3	98.51	1.49
10	पर्यावरण सूक्ष्म जैव विज्ञान				20	19	1	26	26	0	28	28	0	30	28	2	34	34	0	138	135	3	97.83	2.17
11	मानव विकास एवं परिवार कल्याण							30	12	18	40	31	9	40	29	11	40	26	14	150	98	52	65.33	34.67

12	कम्प्यूटर विज्ञान	30	27	3	30	30	0	30	30	0	34	34	0	35	34	1	34	34	0	193	189	4	97.93	2.07
13	सूचना प्रौद्योगिकी				15	15	0	20	20	0	24	24	0	34	25	9	35	35	0	128	119	9	92.97	7.03
14	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	30	27	3	30	30	0	30	30	0	34	26	8	34	33	1	36	36	0	194	182	12	93.81	6.19
15	जनसंचार एवं पत्रकारिता							30	30	0	36	36	0	36	36	0	40	40	0	142	142	0	100.00	0.00
16	मानव अधिकार	30	21	9	20	20	0	30	31	0	32	33	0	31	30	1	30	30	0	173	165	8	95.38	4.62
17	विधि							30	30	0	30	29	1	30	30	0	36	36	0	126	125	1	99.21	0.79
18	व्यावहारिक भौतिकी													26	25	1	40	40	0	66	65	1	98.48	1.52
19	व्यावहारिक रसायन													30	26	4	25	36	0	55	62	0	112.73	0.00
20	व्यावहारिक गणित													30	24	6	30	33	0	60	57	3	95.00	5.00
21	व्यावहारिक सांख्यिकी													30	4	26	30	25	5	60	29	31	48.33	51.67
22	ग्रामीण प्रबंधन													40	36	4	46	46	0	86	82	4	95.35	4.65
योग		**270**	**184**	**86**	**255**	**246**	**16**	**492**	**408**	**95**	**554**	**481**	**74**	**774**	**667**	**111**	**880**	**808**	**91**	**3225**	**2794**	**438**		

अ - ग्रहण क्षमता ब - छात्रों का नामांकन स - रिक्त पद

अनुबंध-4
विभागों एवं भवनों की स्थिति

(पैराग्राफ 3.3.5.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विभाग का नाम	विभाग की स्थापना का वर्ष	विद्यालय के लिए भवन की स्थिति
1.	अम्बेडकर अध्ययन के लिए विद्यालय	अर्थशास्त्र विभाग	2000-01	उपलब्ध
		इतिहास विभाग	2000-01	उपलब्ध
		राजनीति शास्त्र विभाग	2008-09	उपलब्ध
		समाज शास्त्र विभाग	2008-09	उपलब्ध
2.	पर्यावरण विज्ञान के लिए विद्यालय	पर्यावरण विज्ञान विभाग	1997-98	उपलब्ध
		माइक्रोबायोलाजी विभाग	2007-08	उपलब्ध
3	सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विद्यालय	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग	1997-98	अनुपलब्ध
		कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	1997-98	अनुपलब्ध
		सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2007-08	अनुपलब्ध
		जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग	2008-09	अनुपलब्ध
4	जैव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विद्यालय	व्यावहारिक पशु विज्ञान विभाग (रेशम)	2001-02	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक वनस्पति विज्ञान विभाग (बागवानी)	2004-05	अनुपलब्ध
		जैव प्रौद्योगि विभाग	2005-06	अनुपलब्ध
		औषधि विज्ञान विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
5	गृह विज्ञान के लिए विद्यालय	मानव विकास एवं परिवार अध्ययन विभाग	2008-09	अनुपलब्ध
6	प्रबन्धन अध्ययन के लिए विद्यालय	ग्रामीण प्रबन्धन विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
7	शारीरिक विज्ञान के लिए विद्यालय	व्यावहारिक भौतिकी विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक गणित एवं सांख्यिकी विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
		व्यावहारिक रसायन विभाग	2010-11	अनुपलब्ध
8	विधि अध्ययन के लिए विद्यालय	मानवाधिकार विभाग	2000-01	अनुपलब्ध
		विधि विभाग	2008-09	अनुपलब्ध

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

2013-14

वेबसाइटः http://www.cag.gov.in